हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

7 मार्च, 2001

(द्वितीय बैठक)

खण्ड–1, अंक–3

अधिकृत विवरण

विशत सूची

बुधवार, 7 मार्च, 2001

(प्रथम बैठक)

पृश्ठ संख्या

नियम 30 के अधीन प्रस्ताव	(3)1
राज्यपाल के अभिभाशण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(3)1
कनाडा के प्रतिनिधि मण्डल का अभिनन्दन	(3)24
राज्यपाल के अभिभाशण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(3)25
बैठक का समय बढ़ाया	(3)60
राज्यपाल के अभिभाशण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(3)60
वाक–आउट	(3)61
राज्यपाल के अभिभाशण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(3)61

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 7 मार्च, 2001

(द्वितीय बैठक)

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्ड़ीगढ़ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सतबीर सिंह कादयान) ने अध्यक्षता की।

नियम 30 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under rule 30.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to move –

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government Business be transacted on Thursday, the 8th March, 2001.

Mr. Speaker: Motion moved –

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government Business be transacted on Thursday, the 8th March, 2001.

Mr. Speaker: Question is –

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government Business be transacted on Thursday, the 8th March, 2001.

The motion was carried.

राज्यपाल के अभिभाशण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now discussion on the Govenor's Address will be resumed. Sh. Nishan Singh may speak.

श्री निशान सिंह (टोहाना): माननीय स्पीकर सर, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर आपकी इजाजत से सदन में चर्चा करना चाहूंगा। मैं सर्वप्रथम गुजरात त्रासदी के बारे में कहना चाहूंगा वहां ऐसी कुदरती आपदा आई, जिसकी वजह से लाखों लोगों केा अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। ऐसी आपदा की घड़ी में हमारी हरियाणा सरकार के बहुत सारे सदस्य आपके नेतृत्व में वहां गए और हरियाणा सरकार की तरफ से व हरियाणा की जनता की तरफ से वहां बहुत ही सराहनीय कार्य किया, उन लोगों के दु:ख में शरीक हुए और वहां जाकर उनकी जो जरूरतें थीं उनको पूरा करने का प्रयास किया। जो लोग एकदम बुरी तरह से उजड़ चुके थे जिसके परिवारों के सदस्य खत्म हो चुके थे किसी के पास सिर छुपाने के लिए छत नहीं थी ऐसे मौके पर हमारे लोगों ने जाकर के अपना भाईचारा व शिश्टाचार दिखाया और उन लोगों की हर तरह से मदद की, उनकी जरूरत का

सामान बांटा। उसके लिए खाने की चीजें व पहनने के लिए कपड़े व हर तरह की मदद की गई और आज भी यह कार्य वहां जारी है। जिसकी सारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशो से जो संस्थाएं वहां आई थी, उन्होंने भी सराहना की है और हरियाणा प्रान्त का नाम इस मामले में देश में ही नहीं बल्कि विदेशो में भी ऊंचा हुआ है। इस मामले में सरकार बधाई की पात्र है। गवर्नर महोदय के अभिभाशण में शिक्षा नीति का जिक्र किया गया और प्रदेश के सर्वागीण विकास के लिए नयी शिक्षा नीति–2000 लागू करने की बात कही गई व पहली क्लास से अंग्रेजी लागू करने की बात कही। ग्रामीण शिक्षा प्रणाली के विकेन्द्रीयकरण की कोशिश की गई। प्राथमिक स्तर से कम्प्यूटर शिक्षा देने की बात कही गई ताकि हमारे बच्चे इसको पढ़कर देश में ही नहीं विदेशों में भी सारे वर्ल्ड के अन्दर व्यापारिक नहर से और हर नजरियें से आम लोगों का मुकाबला कर सकें। ऐसी शिक्षा नीति देने की बात हमारी सरकार ने कही है जोकि बहुत सराहनीय है। सरकार आपे द्वार कार्यक्रम जो चौ. देवीलाल जी द्वारा चलाया गया प्रोग्राम था, उनकी नीति के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे हरियाणा भर में जिस तरीके से पिछले वर्श और इस वर्श भी आम आदमी के बीच जाकर, 90 के 90 हल्कों में जाकर बिना किसी भेदभाव के इस नीति के माध्यम से आम जनता का, आम आदमी का विकास करने के लिए, निचले स्तर तक शासन प्रदान करने के लिए, बिना किसी भेदीााव के नई सड़कों का निर्माण करने के लिए, पुरानी सड़कों की रिपेयर करवाने के लिए, हरिजनों एंव बैकवर्ड क्लासिज

की चौपालों को बनाने के लिए, गलियों और नालियों को पक्का करने की बात की है, स्कूलों के कमरों को बनवाने की बता की है, पशु औशधालयों और औशधालयों को बनाने की बात की है, रिटेनिंग वाल बनाने की बात की है, रिंग बांध बनवाने की बात की है वह बहुत ही सराहनीय कदम है। इस तरह से माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने सारे हरियाणा भर में यह अभियान चलाया है इससे हरियाणा प्रदेश का चहुमुखी विकास तो होगा ही उसके साथ ही सारे प्रदेश की जनता का हरियाणा सरकार की नीतियों में विश्वास भी व्यक्त हुआ है क्योंकि इससे हर आम आदमी को अपनी बात कहने का मौका मिला है। यह एक बहुत ही सराहनीय कार्य है।

स्पीकर महोदय, हरियाणा प्रान्त में इफोर्मेशन टैक्नोलोजी, सूचना प्रोद्योगिकी नीति–2001 को यह सरकार लागू करने जा रही है। जिस तरह के प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने आई.टी. के बारे में हरियाणा प्रान्त में शुरू किए हैं वह बहुत ही सराहनीय हैं। अब विधायकों को, अधिकारियों को और कर्मचारियों को कम्प्यूटर ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की गई है। आज हरियाणा प्रदेश में इस बारे में जो प्रयास किये जा रहे हैं उससे उत्तर भारत में हरियाणा पहला ऐसा प्रान्त बन जायेगा जो आई.टी. के क्षेत्र में सबसे आगे होगा। मैं मानता हूं कि हरियाणा प्रान्त अब सारे भारत में सब प्रान्तों को लीड करेगा। ऐसे हरियाणा सरकार

के भी प्रयास हैं ये सारी बातें राज्यपाल महोदय के अभिभाशण में कही गई हैं।

जहां तक कृशि नीति की बात है। आज प्रदेश के अन्दर किसानों की जो हालत है वह सबको पता है। किसान जिस तरीके से कर्जे के बोझ के नीचे दबे हुए हैं उनको उस बोझे से छुटकाना दिलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो प्रयास किये हैं वह सराहनीय है। कृशि नीति के मामले में किसानों को अच्छे से अच्छे बीज की सुविधा देने की कोशिश की गई है जिसका इस अभिभाशण में भी जिक्र किया गया है। किसानों को आज इस तरह का प्रोत्साहन दिया जाये ताकि वे आम फसलों को छोड़कर नई फसलों की नई तकनीक के साथ खेती कर सकें। आज हमारे प्रदेश के किसानों को सूखे का सामना करना पड़ रहा है। इस हाल में बिजली और पानी की समस्या भी पैदा हो गई है क्योंकि सारे भारत में कुदरती बरसात ने होने के कारण बिजली और पानी की समस्या ज्यादा हो गई है जिससे किसान की फसलें प्रभावित हुई हैं। इसके बावजूद भी हरियाणा प्रदेश की सरकार ने पूरे प्रयास कर किसानों को पूरी बिजली और पानी देने की कोशिश की है। कृशि के मामले में प्रदेश को अग्रणी बनाने के लिए केन्द्रीय भण्डारण में अनाज का भण्डार करने के सारे इंतजाम किये गये हैं ताकि पिछले साल की तरह इस बार अनाज को बर्बाद होने से बचाया जा सके। किसानों के अनाज को खरीदने के उचित प्रबन्ध इस सरकार ने किए हैं जिससे किसानों को उनकी फसल

का पूरा लाभ दिया जा सके। ऐसी कृशि नीति हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश में लाने जा रहे हैं ताकि किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्ति मिल सके।

जहां तक बिजली की बात है। इसमें कोई शक नहीं कि बरसात कम होने की वजह से बिजली की दिक्कत हमारे प्रांत में आई है परन्तु बावजूद इसके हमारी सरकार ने किसानों को आठ–आठ घंटे बिजली दी है और उसकी वोल्टेज भी हमेशा अच्छी किसानों को दी है। पहले किसानों की मोटरें वोल्टेज कम होने के कारण जल जाया करती थी लेकिन अब अच्छी बिजली मिलने और बिजली की वोल्टेज पूरी मिलने से किसानों का नुक्सान नहीं हुआ है। इसके अलावा नहरी पानी की हमारे प्रदेश के सामने दिक्कत होने के बावजूद भी बिजली ली गई है। इसके साथ–साथ बिजली की जनरेशन को बढ़ाने का प्रयास हो रहा है और हम यह मानकार चलते हैं कि आने वाले साल में बिजली की दिक्कत दूर हो जाएगी। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाशण में यह भी दर्शाया गया है कि मुख्यमंत्री महोदय ने रणजीत सागर डैम से जो बिजली पैदा हो रही है उसमें से 50 प्रतिशत हिस्से की मांग की है। सदन में भी कई साथी इस बारे में विचार कर रहे थे। मैं उनको बताना चाहूंगा कि पहले से ही मुख्यमंत्री महोदय कह चुके हैं कि रणजीत सागर डैम से 50 प्रतिशत हिस्सा मिलना चाहिए। इस बात को लेकर प्रधानमंत्री जी की सभी मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग हुई थी। जहां तक मुझे पता चला है कि मुख्यमंत्री महोदय

ने उस मीटिंग में इस मांग को बड़े जोरों से प्रधानमंत्री जी के सामने उठाया था। उन्होंने हरियाणा को बिजली के हिस्से के साथ–साथ एस.वाई.एल. के पानी की भी बात की थी और नदियों के केन्द्रीयकरण की भी बात की थी। इस बात को कल की रैली में प्रधानमंत्री ने यह कह कर मोहर लगा दी कि जल के बंटवारे के बारे में हरियाणा के मुख्यमंत्री हमेशा पहल करते रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक सिंचाई की बात है, सिंचाई के मामले में जहां हम पहले यह देखते थे कि पिछली सरकारों के समय में, पिछले 8–10 सालों से जो हमारे पक्के खालों की दुर्दशा हो चुकी थी, उन खालों को नए सिरे से बनाने के लिए लगभग 28 करोड़ रूपये की लागत से 259 खालों को बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। इससे किसानों को राहत मिली है। हमारी सरकार ने किसान के खेत तक पानी पहुंचाने का प्रयास किया है जोकि एक सराहनीय कार्य है। एम.आई.टी.सी. के द्वारा सरकार का यह प्रयास है कि सिंचाई की सुविधा किसानों को पहुंचाने के लिए इन पक्के खालों को युद्ध स्तर पर बनाया जाए। हमारी सरकार ने इस प्रदेश को बाढ़ मुक्त बनाने का प्रयास किया है। हमारी सरकार छोटी–छोटी ड्रेन्ज बनाकर बाढ़ के पानी और सेम के पानी को निकालने का प्रयास कर रही है ताकि हरियाणा को पूरी तरह से बाढ़ मुक्त बनाया जा सके ओर किसानों की फसलें बरबाद होने से बच जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाशण में औद्योगिक विकास की बात भी दर्शाई गई है। हमारी सरकार ने राज्य से न केवल

औद्योगिक इकाइयों के बढ़ते हुए पलायन को रोका है अपितु मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने विदेशों में जाकर विदेशी निवेशकों को हरियाणा में इण्डस्ट्रीज लगाने के लिए कहा है तथा हमारे प्रवासी भारतीयों को निवेदन किया है कि हरियाणा में उद्योग–धंधे लगाएं। दिल्ली से उद्योगों को बाहर निकालने की बात हो रही है। ये सारे उद्योगपति हरियाणा में अपनी इण्डस्ट्रीज लगाना चाहते हैं। इस अभिभाशण में यह भी दर्शाया गया है कि हमारी सरकार ने औद्योगिक प्लाट भी आबंटित किये हैं जिसके लिए 8000 आवेदन आए थे। जो अपनी इण्डस्ट्रीज हरियाणा की धरती पर लगाना चाहते हैं जिनमें से 4000 को परमिशन मिल गई है और प्लाट आबंटित कर दिए गए हैं। यह एक सराहनीय कार्य है। स्पीकर सर, जन स्वास्थ्य के बारे में राज्यपाल महोदय के अभिभाशण में जिक्र किया गया है कि पूरे हरियाणा प्रान्त के अन्दर पीने के पानी की उचित व्यवस्था की जायेगी। हरियाणा सरकार ने जो नया आयाम देने की कोशिश की है कि पहले जो पीने का पानी 40 लीटर प्रति दिन प्रति व्यक्ति दिया जाता था उसे अब बढ़ाकर 70 लीटर प्रति दिन प्रति व्यक्ति किया जायेगा। यह बहुत ही सराहनीय बात है। इस समय भी कई जगहों पर पीने का पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 70 लीटर दिया जा रहा है और जल्दी ही 70 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रति दिन पूरे हरियाणा में मिलने लगेगा।

स्पीकर सर, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाशण में सड़कों के बारे में जो जिक्र किया है वह भी बहुत

सराहनीय है। मौजूदा सरकार ने 60.75 करोड़ रूपये की लागत से पूरे हरियाणा प्रांत में 2596 कि.मी. सड़कों को ठीक किया है। जिस समय हमारी सरकार ने सत्ता संभाली थी उस समय इन सड़कों की हालत बहुत खराब थी। (शोर एवं व्यवधान) इसी तरह से मुख्यमंत्री महोदय ने 'सरकार आपके द्वार कार्यक्रम' के तहत जो भी घोशणाएं की थीं उनको पूरा किया है यह भी बहुत सराहनीय कार्य है इसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान) इसके अतिरिक्त महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाशण में यह भी दर्शाया है कि हुडको से 321 करोड़ रूपये का लोन स्वीकृत करवा लिया है इससे हरियाणा की सड़कें और भी अच्छी बनाई जायेंगी। स्पीकर सर, परिवहन के बारे में भी राज्यपाल महोदय के अभिभाशण में बहुत अच्छा स्कोप है। हमारी सरकार से पहले परिवहन की बहुत बुरी हालत थी। हरियाणा परिवहन की जो बसें थी उसमें लोग बैठना पसंद नहीं करते थे। वे हरियाणा रोडवेज की बसे में बैठने की बजाय जीप या टैम्पू में बैठना पसंद करते थे लेकिन हमारी सरकार ने 450 नई बसें खरीदी हैं क्योंकि जो पुरानी बसें थीं वे ठीक कराने की हालत में नहीं थीं उनकी हालत बहुत खराब थी। यह सरकार का बहुत ही सराहनीय कार्य है। स्पीकर सर, जो पिछली सरकार थी उसने प्राईवेट सैक्टर को जो बसिज के रूट परमिट दिये थे उनकी नीतियां इतनी ज्यादा खराब थीं कि लोगों ने अपनी बसें बेच दी और दूसरा कार्य करने लगे क्योंकि उनको उससे घाटा होता था। लेकिन अब राज्यपाल महोदय के अभिभाशण में दर्शाया गया है कि

मौजूदा सरकार प्राईवेट सैक्टर को बसिज के परमिट देने के लिए नई नीति लागू करेगी इससे लोगों को फायदा होगा। सरकार का यह कदम भी बहुत सराहनीय है। स्पीकर सर, ग्रामीण विकास के बारे में राज्यपाल महोदय के अभिभाशण में जिक्र किया गया है कि गांवों के विकास के लिए और उन चुनी हुई संस्थाऔं जैसे पंचायतों, नगरपालिकाओं या जिला परिशदों आदि को भी सरकार ने अधिकार दिए हैं। हरियाणा सरकार ने इन संस्थाओं को अधिकार ही नहीं बल्कि उनको प्रशासकीय शक्तियां देकर सरकार का हिस्सा बनाया है। यह सरकार का बहुत ही सराहनीय काम है। इसी तरह से पंचायतों के अंदर ग्रामीण विकास समितियां बनाकर आम आदमी को सरकार के अन्दर हिस्सेदार बनाया गया है ताकि गांव के एक पंच की भी सुनवाई हो सके और वह भी विकास का कार्य करवा सके। इसके अतिरिक्त गांव की ग्रामीण विकास समिति में रिटायर्ड हुए एक फौजी को भी शामिल किया गया है, एक महिला को भी शामिल किय गया है। इस तरह से मौजूदा सरकार ने एक नया आयाम कायम किया है इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। ऐसा करने से गांव के आम आदमी में भी कांफीडैंस आ जायेगा और वह सोचेगा कि वह भी गांव के विकास में अपना हाथ बंटा सकता है। अब वह समझ सकता है कि अगर गांव का विकास होगा तो उसका भी विकास होगा। चुगी गई संस्थाओं को ज्यादा अधिकार देने से उनमें ज्यादा कांफीडैंस आयेगा और वे अपने क्षेत्र का ज्यादा विकास कर पायेंगी।

जहां तक खेलों की बात आती है तो हम सभी मानते हैं खेल–कूद हर आम व्यक्ति के लिये और बच्चे के लिये जरूरी है। जब खेलों को बढ़ावा देने की बात आती है तो मैं कहना चाहूंगा कि दुर्भाग्यवश पिछली सरकारों के समय में चाहे हरियाणा ओलम्पिक संघ की बात ले लें या फिर सरकार को जिम्मेवारी की बात ले लें, पूरी तरह से खेलों को और हरियाणा ओलम्पिक संघ की कार्य प्रणाली को डैड करके छोड़ दिया गया था लेकिन वर्तमान सरकार ने श्री अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में हरियाणा ओलम्पिक संघ का काम फिर से शुरू किया है और खेलों को खूब बढ़ावा दिया जा रहा है। कबड्डी, फुटबाल और वालीबाल जैसे खेल जो कि लुप्त हो चुके थे, उनको दोबारा चालू करने का काम शुरू किया गया है। ब्लॉक स्तर पर, जिला स्रत पर और प्रान्त स्तर पर इन खेलों को बढ़ावा देने का हरियाणा ओलम्पिक संघ ने प्रयास किया है। पिछले दिनों ब्लॉक स्तर पर खेल हुए जिससे बच्चों में नई भावना जागृत हुई। इसी तरह से जिला स्तर पर खेलों को बढ़ावा मिला और बच्चों को खेलों के प्रति अपनी योग्यता दिखाने का अवसर मिला। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि खेलों के प्रति जो सुधार लाने का सरकार द्वारा प्रयास किया गया है वह एक सराहनीय कदम है। इस तरह से खेलों को बढ़ावा दिये जाने से हमारे बच्चों को राश्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अन्तर्राश्ट्रीय स्तर पर खेलने और अपनी योग्यता दिखाने का मौका मिलेगा और ये बच्चे प्रान्त और देश का नाम

रोशन कर पाएंगे। सरकार द्वारा ऐसा कार्य किया गया है जो वाकई सराहनीय है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं पशु पालन के मामले में कुछ कहना चाहूंगा जैसा कि पिछले दिनों हरियाणा का एक कृशि डैलीगेशन इजराइल गया था ताकि कृशि के मामले में और पशु पालन के मामले में अच्छी टैक्नोलोजी लेकर देश में उस टैक्नोलोजी को लागू करने का काम करे क्योंकि कृशि के मामले में बाहर के देश ज्यादा सक्सैसफुल हैं इसीलिये हमें उनसे शिक्षा लेकर अच्छी टैक्नोलोजी को यहां पर लागू करना है। गवर्नर साहब के एड्रैस में कृशि के बारे में जिस तरह से नीतियां दर्शाई गई हैं उससे पता चलता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच काफी सराहनीय है और मैं समझता हूं कि हमारे कृशि मंत्री श्री जसविन्द्र सिंह संधु की अध्यक्षता में वरिश्ठ अधिकारियों द्वारा कृशि संबंधी नई टैक्नोलोजी को युद्ध स्तर पर बढ़ावा दिये जाने का प्रयास किया जा रहा है। यह भी कोशिश की गई है कि अच्छी टैक्नोलोजी को लागू करके गाय और भैंसों से ज्यादा से ज्यादा दूध का उत्पादन लिया जाए जिससे डेयरी फोर्म में भी किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके और डेयरी फार्म ज्यादा से ज्यादा फले–फूलें। पशु पालन के मामले में भी सरकार के प्रयास सराहनीय हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से कानून और व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी तो कोई दो राय नहीं है। पिछली सरकार ने शराबबन्दी लागू करने का जो फैसला किया था उससे

हरियाणा के अन्दर क्राइम काफी बढ़ गया था और जो लोग रास्ते से भटक गये थे उन लोगों को आज तक नकेल डालने के प्रयास वर्तमान सरकार कर रही है। पिछली सरकार के समय में लॉ एंड आर्डर की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि लोग हथियार लेकर समाज में लूट–पाट मचा रहे थे। हमारी सरकार ने ऐसे लोगों को नकेल डालकर लगाम लगाने की पूरी कोशिश की है। गवर्नर एड्रैस में दर्शाया गया है कि हमारी सरकार ने किस तरह के कानून और व्यवस्था सुधारने के प्रयास किये हैं। राज्यपाल महोदय के अभिभाशण में श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में भी दर्शाया गया है। हरियाणा सरकार ने कई तरह से प्रोग्राम बनाये हैं जिससे कि आम आदमी को रोजगार मिल सके। हरियाणा सरकार ने कोशिश की है कि हरियाणा के अन्दर टैक्निकल एजुकेशन को सीधे रोजगार धन्धों से जोड़ा जाए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके और जो अपना व्यापार करना चाहें तो वे अपना काम भी कर सकें। पढ़ाई में भी ऐसा शिक्षा नीति अपनाई जा रही है जो कि सराहनीय कदम है। माननीय गवर्नर महोदय ने जो अभिभाशण सदन में रखा है उसमें सरकार के हर वर्ग के हित को ध्यान में रखा गया है इससे हरियाणा का चहुमुखी विकास होगा और बिरादरी का और आम आदमी का भला होगा मैं इसका समर्थन करता हूं और सदन से भी अनुरोध करता हूं कि इसे आम सहमति दें। धन्यवाद।

श्री शेर सिंह (जुलाना): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाशण के शुरू में ही नैचुरल कलैमिटी के बारे मैं काफी कुछ दर्शाया गया है। नैचुरल कलैमिटी से होने वाले नुक्सान की पूर्ति करने के लिए हरियाणा सरकार ने भी काफी कोशिश की है। इसके बावजूद भी लोगों में काफी उत्साह था, उन्होंने काफी हाथ बटाया। लेकिन इसके बारे में मैं एक बात बताना चाहूंगा कि इस तरह की विपदाएं हमेशा आती रहेगी तो क्या हरियाणा सरकार ने कोई ऐसी स्कीम बनाई है कि कटीजैंसी प्लान जो है उसके बगैर अगर अव्यवस्था होती है तो किस प्रकार से उस पर कार्यवाही करेंगे? इस बारे में विचार करने की बड़ी सख्त जरूरत है। शायद फलड कंट्रोल के बारे में सरकार ने कुछ प्लान बनाई हुई हैं। लेकिन अर्थ क्वेक के बारे में अभी तक कोई स्कीम नहीं बनाई है। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि दिल्ली के आस पास जो हरियाणा प्रदेश के शहर हैं जिनमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्ज हैं, अर्थ क्वेक के कारण वे काफी खतरनाक साबित हो सकती हैं। इसलिए बेहतर होगा कि हमें गुजरात के उदाहरण से कुछ सीखना चाहिए। आईदा इस तरह की विपदा से मुकाबला करना अति आवश्यक है और उसका मुकाबला तभी किया जा सकता है अगर उसके बारे में पहले से कोई स्कीम बनाई गई हो। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं यह कहना चाहूंगा कि इस सरकार का 'सरकार आपके द्वार' जो नारा है यह काफी तगड़ा नारा है। यह नारा एक साल से चल रहा

है। हमारे मुख्यमंत्री हर जगह जाते हैं और काफी कुद लुभावनी बातें कह कर आ जाते हैं और बाद में उन बातों पर शायद काम कुछ भी नहीं होता। यह देखना पड़ेगा कि ये इस तरीके से जनता को कब तक बहकाते रहेंगे? जनता हमेशा यह कहती है कि आज तक जितने दरबार लगे हें उनमें लोग नहीं आते हैं। मेरे हल्के जुलाना में जो 'सरकार आपके द्वार कार्यक्रम' का दरबार लगा वह दरबार नहीं था। उस दरबार में वहां के सरपंच को बुलाकर उस पर डांट मारी गई थी कि अगर बिजली के बिल नहीं भरोगे तो किसी को भी यहां आने की जरूरत नहीं है। अगर माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं तो ये सभी के मुख्यमंत्री हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। इस बारे में विचार करने की जरूरत है।

श्री रामकुमार: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। चौ. शेर सिंह हाउस को गुमराह कर रहे हैं। 'सरकार आपके द्वार' प्रोग्राम के तहत लगाए गए किसी भी दरबार में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी भाशा नहीं बोली है। अगर बोली है तो आप गीता पर हाथ रख कर कहें, वैसे ही गलत बात नहीं कहनी चाहिए।

श्री शेर सिंह: इसमें गीता पर हाथ रखने वाली बात कहां से आ गई। यह बात मैंने नहीं सुनी। जो बात सरपंच ने सुनी, वह बात मैं यहां पर दोहरा रहा हूं।

श्री राम कुमार: अब की बार तो फीते मार कर चुनाव जीत गया आगे आएगा तक बताएंगे।

श्री शेर सिंह: फीते तो आपने मारे होंगे। मैंने कही कोई फीता नहीं मारा। अध्यक्ष महोदय, कृशि के बारे में यहां बातचीत होती रहती है। हरियाणा प्रदेश एक कृशि प्रधान प्रदेश है जिसके बारे में हम बहुत कुछ विचार करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब किसी भी फसल की बिजाई होती है तो उस टाईम बीच किसानों को समय पर नहीं मिलता है बल्कि बीज बाद में मिलता है। बिजाई खत्म होने के बाद बीज आता है। बीज की जो बोरियां आती हैं उनमें काफी निकम्मा बीज आता है इसलिए इस बारे में काफी गौर करने की जरूरत है।

कृशि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह संधु): अध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथी विधायक को बताना चाहूंगा कि यदि हमारे यहां पर नकली बीज और घटिया खाद किसानों को दिया जाता तो फिर हमारा रिकार्ड उत्पादन कैसे हो सकता था? आज के दिन हम केन्द्रीय पूल में पहले से अधिक अन्न दे रहे हैं। यह हम तभी दे रहे हैं जब हमारे यहां पर बढ़िया बीज और सही खाद किसानों को दिया जा रहा है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि इनको यहां पर असत्य बातें नहीं कहनी चाहिएं।

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्रियों से निवेदन है कि जब कोई विधायक चाहे वह किसी भी

पार्टी से बोल रहा हो, उसका बीच में जवाब न दें। जब साथी विधायक अपनी बात खत्म कर लें तो उस वक्त संबंधित मंत्री अपने संबंधित महकमें का जवाब दे सकते हैं इस तरह बीच में बोलना ठीक नहीं है।

श्री शेर सिंह: स्पीकर साहब, पैडी प्रोक्योरमेंट के समय केन्द्र सरकार की तरफ से पंजाब को कुछ पैकेज मिला था। हमारे किसानों को क्या पैकेज मिला, क्या सहायता किसानों को दी गई, क्या उसका फायदा किसानों तक पहुंच पाया या नहीं इसका स्पश्टीकरण सरकार दें। अध्यक्ष महोदय, मैं किसानों को सबसिडी और खाद देने बारे कह रहा था। गेहूं की बिजाई की बात के ऊपर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कयोंकि किसानों को सही समय पर सही पानी नहीं मिल पाया। आज के दिन किसान को जो अपनी पैदावार की लागत मिलती है वह बहुत कम मिलती है जबकि खर्चा बहुत अधिक आता है। कल कुरूक्षेत्र में प्रधानमंत्री जी ने भाशण दैते हुए कहा था कि हमें बाहर से गेहूं सस्ता मिलता है। प्रधानमंत्री जी के इस कथन का क्या मतलब निकाला जा सकता है? आज के दिन किसानों को डिमोरेलाईज करने की बजाये उसका हौसला बढ़ाये जाने की आवश्यकता है और साथ ही साथ उसको उचित दाम दिये जाने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा किसानों का मोरल ऊंचा उठाने के लिए कुछ न कुछ कदम उठाये जाने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं बिजली के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। बिजली पानी के बिना नहीं मिलती। पावर आज के दिन बहुत अधिक महंगी हो चुकी है। इस सरकार ने आने के बाद एक साल के अन्दर बिजली के काफी रेटस बढ़ाये हैं। आज के दिन रेटस इतने अधिक हो गए हैं कि उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। किसान को अपनी उपज का पूरा मूल्य नहीं मिल पाता। जब उसको अपनी उपज का पूरा मूल्य नहीं मिल पायेगा तो वह बिजली के बिल को कैसे भुगतान करेगा? यहां पर बताया गया कि पावर इधर उधर से ले रहे हैं। कोई भी प्लाट यदि 100 गज से नीचे का होगा तो उस पर लोगों से 15 रूपये पर स्केयर यार्ड के हिसाब से सिक्योरिटी ली जायेगी और जो प्लाट 100 गज से 500 गज तक का होगा उस पर 25 रूपये पर स्केयर यार्ड के हिसाब से सिक्योरिटी ली जायेगी और जो 500 गज से ऊपर का प्लाट होगा उससे 50 रूपये पर स्केयर यार्ड के हिसाब से सिक्योरिटी ली जायेगी। सिक्योरिटी के नाम पर लोगों से बहुत अधिक पैसे लिये जा रहे हैं। मेरी सरकार से मांग है कि सरकार ने जो यह पैमाना निश्चित किया है इसको खत्म कर दे। सरकार यदि इसको खत्म नहीं करती तो फिर लोगों से एक तरह से जबरदस्ती पैसा लेने वाली बात है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं सिंचाई के बारे में कहना चाहूंगा। मेरे हल्के जुलाना में एक सुन्दर ब्रांच है। उसमें पानी बहुत कम आता है। पहले 14 दिन में पानी आता था लेकिन उसके

बाद उस ब्रांच में 21 दिन बाद पानी आने लगा, फिर 28 दिन बाद पानी आने लगा और अब तो यहां पर 40 दिन बाद पानी भेजा जा रहा है। 40 दिन बाद भी पूरा पानी नहीं आ रहा बल्कि आधा आ रहा है। इस तरह से जो रजबाहे हैं फिर उनमें पानी कहां से आयेगा? टेल पर तो पानी पहुंचने का मतलब ही नहीं है। अब कहा जा रहा है कि पानी की क्या आवश्यकता है क्योंकि अब तो फसल की कटाई होने वाली है। मेरे कहने का मतलब यह है कि किसानों को अपनी फसल के लिए पूरा पानी सम पर नहीं मिल पाया। आप सबको मालूम है कि यह आंकड़े किसान के लिए बड़े दुखदाई हैं और ये आंकड़े देना उनके लिए बड़े मुश्किल पड़ते हैं। पिछली दफा यहां पर बताया गया था और मुख्यमंत्री जी से भी मेरी बात हुई थी कि हमारे ऐरिया में हेल स्टॉर्म आया था जिसके कारण फसलों को हुए नुकसान के लिए किसानों के लिए कुछ कम्पनसेशन मांगा था और कहा था कि किसानों को कुछ कम्पनसेशन दीजिए तो उन्होंने कहा था कि 'हां उनको कम्पनसेशन मिलेगा' लेकिन आज तक उन गरीबों को कोई कम्पनसेशन नहीं मिला है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि क्रॉप्स की इन्श्योरेन्स की भी कोई–न–कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से आगे आने वाले समय में जरूर होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सभी चीजों को मेन आधार पर शिक्षा है। शिक्षा के द्वारा ही आदमी जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। अभी शिक्षा के बारे में काफी शोर मचाया गया और कहा गया कि एक नई शिक्षा प्रणाली लागू की गई है। गांवों के स्कूलों में

जहां बच्चों के बैठने के लिए तप्पड़ नहीं है, फर्श नहीं है, टीचर के बैठने के लिए कुर्सी नहीं है वहां पर केवल अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा दिलवाने से नई एजुकेशन पॉलिसी नहीं हो जाती, केवल कम्पयूटर लाने से कोई नई शिक्षा नीति नहीं हो जाती है। आज गवर्नमैंट स्कूलों में कितने बच्चे पढ़ते हैं? आज घर–घर में प्राईवेट स्कूल खुले हुए हैं इसलिए इस बात पर गौर करने की जरूरत है। आज गवर्नमैंट स्कूलों में पढ़ाई का स्तर इतना गिर चुका है कि लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वहां भेजना नहीं चाहते हैं। गवर्नमैंट स्कूलों में तो गरीबों के बच्चे ही जाएंगे और वहीं वहां जाकर पढ़ेंगे। जो गरीब गवर्नमैंट स्कूलों में पढ़ेगा यह वहां पर पढ़ कर भी गरीब ही रहेगा क्योंकि वहां से पढ़ा हुआ बच्चा कम्पीटीशन में नहीं आ सकता है। सरकार को इस बात पर गौर करना चाहिए और गवर्नमैंट स्कूलों में अच्छे शिक्षकों को लगाया जाए। कम्पयूटर से हम इम्तिहास लेते हैं और रिजल्ट निकालते हैं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि कम्पयूटर की जरूरत क्या है? क्या हम कम्पयूअर के बिना जो इम्तिहान लिया है उसका रिजल्ट योग्यता के आधार पर दूसरे या तीसरे दिन नहीं निकाल सकते हैं? अभी जो शिक्षकों की नियुक्ति की गई है उसमें शिक्षक की क्या योग्यता है क्या मार्जन है या ये लोग बेहतर जानते हैं मुझे तो इसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं है लेकिन इतना ज्ञान जरूर रखता हूं कि ये भर्तियां किस आधार पर की गई हैं? मैं सरकार से एक बात और पूछना चाहता हूं (विघ्न)।

श्री अध्यक्षः आप अपनी बात को शॉर्ट करें और जल्दी बाईड अप करें।

श्री शेर सिंहः मैं तो बिल्कुल ही शॉर्ट कर दूंगा इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इम्पलॉयमैंट के बारे काफी शोर चल रहा है। (विघ्न) मुझे बोलते हैं कि फीते से भर्ती होती थी। वह फीता मेरे हाथ में तो नहीं रहा, मैंने तो लोगों से फीते का काम करवाया है लेकिन इनके आदमी तो बिना फीते के ही भर्ती हो रहे हैं हम तो फिर भी फीता लगा कर भर्ती किया करते थे लेकिन इनके भर्ती किए हुए लोग तो कभी फीते में ही नहीं आए। अध्यक्ष महोदय, इनसे पूछिये कि क्या यह ठीक है या नहीं? आगे पुलिस की जो भर्तियां हुई हैं उनमें लिए 500 रूपये फीस पहले ही उनसे ले ली गई है। गरीब आदमी 500 रूपये की फीस नहीं दे सकता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन–जातियों के लोगों के लिए भी 500 रूपये फीस है ****

श्री अध्यक्षः शेर सिंह जी, इस प्रकार की भाशा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इन्होंने जो गलत शब्द कहे हैं उनको कार्यवाही से डिलीट कर दिया जाए।

राव इन्द्रजीत सिंहः अध्यक्ष महोदय, ये पहली बर मैम्बर बन कर आए हैं और पहली बार भाशण दे रहे हैं इस प्रकार से बीच में इनको टोकना ठीक नहीं है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: कटवाल साहब, आप अपनी सीट पर बैठें। (शोर)

श्री शेर सिंह: अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति के लोगों को हर जगह पर कन्सैशन है लेकिन यह 500 रूपये जो लिए जाते हैं, इसमें कोई कन्सैशन क्यों नहीं किया गया है? वे लोग जो कि पहले ही समाज में काफी पिछड़े हुए हैं, उनको तो इसमें वैसे ही आने देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हम लोग बार–बार भ्रश्टाचार शब्द का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि भ्रश्टाचार को मिटा देंगे। इस शब्द का इस्तेमाल करने की जरूरत ही क्या है अब लोगों में सरकार की छवि प्रस्तुत है क्योंकि भ्रश्टाचार के मामले में देखने की बात यह है कि कोई भी काम कुछ दिये बगैर नहीं होता है तो फिर हम क्यों भ्रश्टाचार मिटाने की बात करते हैं? यह शब्द तो यहां की डिक्शनरी से ही निकाल दें तो बेहतर होगा। (विघ्न) अभी ग्रामीण पंचायतों के बारे में कहा गया कि हम पंचायतों को अधिकार देंगे। यह बिल्कुल उचित है कि ग्रामीण पंचायतों को अधिकार मिलने चाहिएं लेकिन जो ग्राम पंचायतें बनाई गई हैं आप चाहते हैं बाहर से दो या तीन आदमियों को पंचायतों के कार्य का निरीक्षण करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, दो आदमी पंचायतों के ऊपरन सुपर इम्पोज नहीं किये जाते चाहिएं, आपने उन लोगों को सुपर इम्पोज करके पंचायतों की हद को नीचा कर दिया है। यह बिल्कुल असंवैधानिक है और इस पर गौर करने की जरूरत है। हम कहते हैं कि डैमोक्रेसी

सिस्टम यह नहीं कहता है कि अगर उस पर लगाम ही लगानी है तो इस तरीके के लोग लगाने चाहिएं जो सब तरह के समुदाय के लोग हों। यहां पर रैजोल्यूशन पास करके उसमें उनको शामिल किया जाना चाहिए और उसमें भी चुने हुए लोग ही आ सकते हैं। शायद इसमें भी यह राज है कि इन संस्थाओं से भी उनके ही लोग आएं और वही लोग खर्चा करवाएं। अगर पंचायत खर्च करने में ठीक नहीं है तो क्या बाहर से तीन आदमी आ कर खर्च को ठीक कर सकते हैं? इस तरह की चीजें उचित नहीं हैं।

समाज कल्याण के बारे में बहुत कुछ कहते हैं हम यह दे रहे हैं हम वह दे रहे हैं। परन्तु हमने अपने एरिया में ऐसी कोई बात नहीं देखी है। खासतौर पर ऐसे परिवार जिनके पास धन नहीं है तो वे हम लोगों से पूछते हैं कि हमें कुछ पैसा दे सकते हो। तो हम उनसे कहते हैं कि यह तो आपको 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम से ही मिल सकता है। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को भी पब्लिक ने चुनकर भेजा है हम भी उनके नुमांयदे हैं हम भी तो उनको कुछ पैसा दे सकते हैं ऐसा कोई प्रबन्ध सरकार को करना चाहिए। ये बात डि सैन्ट्रलाईज की करते हैं जबकि इन्होंने सैन्ट्रलाईज किया हुआ है। आज ग्राम पंचायतों को जिला बोर्ड से दस्तखत करवाकर पैसा दिया जाता है यह एक नई बात है।

अध्यक्ष महोदय, ये ला एंड आर्डर की बात करते हैं। अभी तीन चार दिन पहले हमने अखबार में पढ़ा कि किसी जिले में

गोलियां चली। ऐसे ही एक विधायक के साथ हाथापाई हुई है यह बहुत ही अच्छा उदाहरण ला एंड आर्डर का है। वहां पर कुछ लोगों की भी पिटाई हो गई ओर कुछ पुलिस वाली की भी पिटाई हुई थी। ऐसी बात तो हमारे हरियाणा में होती रहती है। रोहतक में भी एक महन्त को थ्रैट दी गई है कि उसे मार देंगे और उससे दो लाख की भी मांग की गई है। वह प्रोटैक्शन की मांग कर रहा है पता नहीं उसे अभी तक प्रोटैक्शन दी भी गई है कि नहीं। अब ये क्या ला एंड आर्डर की बात करेंगे?

श्री अध्यक्ष: शेर सिंह जी अब आप बैठें। आपका समय समाप्त हो गया है। अब राव नरेन्द्र सिंह जी बोलेंगे। (विघ्न)

श्री शेर सिंह: ठीक है जी।

राव नरेन्द्र सिंह (अटेली): माननीय स्पीकर सर, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर चर्चा के लिए आपने मुझे जो बोलने का समय दिया है उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। 5 तारीख को महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने हरियाणा की जनता से समक्ष अपना अभिभाशण पढ़ा। वह अभिभाशण जैसा कि प्रजातन्त्र की व्यवस्था है जो भी मौजूदा सरकार होती है और जो भी वह अपनी कार्य रेखा कार्यान्वित करती है वह राज्यपाल जी को संवैधानिक जिम्मेवारी निभाते हुए यहां पर पढ़नी पड़ती है। हमने उसको सुना और पढ़ा भी। इस सबके बाद हम इस निश्कर्श पर पहुंचे कि जो भी इस सरकार की

कमियां है, विपक्ष का रोल तभी सही होता है जब वह सरकार के कामों को सही मायनों में सरकार के सामने रखे। सत्ता पक्ष के लोग भी यह समझें कि यह विपक्ष वाला हमारी बुराई नहीं कर रहा है वह तो हमारी जो कमियां हैं उनको हमारे सामने रख रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा में जो बिजली की व्यवस्था है शायद ही आज से पहले हरियाणा में कभी रही होगी। ये 24 घंटे बिजली देने की बात करते हैं। दक्षिणी हरियाणा में तो दो ही घंटे बिजली मिल रही है। वहां के किसान के पास थोड़ी सी जमीन है और उसने बैंकों से कर्ज लिया हुआ है। उस किसान की चाहे बहन की शादी हो, परिवार का खच्र चलाना हो या कोई और खच्र हो उसके पास इन्कम का जो सोर्स है वह उसकी खेती ही है। वहां कोई उद्योग नहीं है और न ही पर किसी प्रकार का व्यापार है जिससे काम चल सके। वहां पर खेती ही एक साधन है। (विघ्न) स्पीकर सर, मैं आपके द्वारा मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्शित करना चाहूंगा खासतौर से दक्षिणी हरियाणा के महेन्द्रगढ़ जिले की तरफ। वहां पर आज किसान बिजली के लिए अत्याधिक परेशान हैं। मैं समझता हूं कि जिस इलाके के लोग केवल खेती पर ही निर्भर हों वहां पर तो बिजली मिलना और भी जरूरी है। हमारे यहां पर गहरे टयूबवैल्ज हैं जिनको डीप टयूवबैल्ज कहते हैं वहां पर 700 फीट तक बोरिंग जा चुकी है। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर वहां पर बिजली मिलना तो वहां पर खेती नहीं हो सकती। विश्व बैंक के दबाव में सरकार ने जो बिजली के रेट बढ़ाए हैं वह किसानों के ऊपर सीधी मार है।

सरकार को चाहिए था कि ऐसे इलाकों में जहां पर पानी बहुत गहराई तक जा चुका है उनके लिए बिजली के रेट में कोई स्लैब प्रणाली लागू करती लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं है कि यदि हम विपक्ष के विधायक हैं तो ऐसा कह रहे हैं। सरकार चाहे तो इस बारे में डी.सी. से रिपोर्ट मंगवा सकती है या अखबारों के माध्यम से भी रिपोर्ट ले सकती है। आज दक्षिणी हरियाणा के हर इलाके में चाहे वह अटेली का इलाका हो, चाहे वह नांगल चौ. का इलाका हो या चाहे वह नारनौल का इलाका हो यानि सब जगहों पर किसान इसी बात को लेकर सड़कों पर आकर बैठ गए हैं। अभी चार तारीख को जो भिवानी में रैली हुई थी उसमें भी लाखों किसान इसी बात को लेकर पहुंचे थे क्योंकि उनमें बहुत रोश था। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह उनसे सबक सीखे और इस बारे में जो कमियां रह गई हैं उनको दूर करे। इसी तरह से तहसील लेवल पर काम करवाने के बदले में बिजली के बिल भरने का जो डयूज का आदेश दिया गया था हालांकि शायद वह अब वापिस ले लिया गया है लेकिन वह सिस्टम बहुत ही गलत था। बिजली विभाग में जो जैनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम बनाये गये हैं। उनको ठीक तरह से काम करना चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री जी का एक बयान पढ़ा था कि जो गांव बिजली के बिल नहीं भरेंगे उनको सरकार की तरफ से दवन्नी भी नहीं मिलेगी। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि इसके लिए कौन दोशी है? जब ये अपोजीशन में थे तो लोगों को भड़काकर कहते थे कि बिजली का बिल नहीं भरो।

लेकिन अब जब ये सरकार में हैं और जब इनको फाईलों का पता लगात है तो कहते हैं बिजली का बिल भरें। जिस इलाके के लोग बिजली का बिल भरते हैं उनके लिए सरकार को अलग से नॉर्म्ज बनाने चाहिएं। हमारे इलाके के लोगों ने बिजली के बिल देने में कभी जबरदस्ती नहीं की। इसलिए मेरा सरकार से यह कहना है कि उन लोगों के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए जो बिजली का बिल भरते हैं। अगर किसी इलाके के लोग ये बिल नहीं भरते हैं तो सरकार उनके लिए अलग नीति बना सकती है। इसी तरह से जमीन बेचने का सवाल आया है सरकार ने कहा है कि जो व्यक्ति बिजली का बिल नहीं देगा तो उसकी लैंड से रिकवरी करके बिजली का बिल भरवाया जाएगा। स्पीकर सर, यह सरासर किसानों के साथ धोखा है अन्याय है। सरकार को मेरा सुझाव है कि वह केन्द्रीय पूल से अतिरिक्त बिजली लेने की व्यवस्था करें या उसको पड़ौसी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश से पन बिजली लेने की व्यवस्था करनी चाहिए और किसानों को सस्ती बिजली देनी चाहिए। इसी तरह से भाखड़ा से भी बिजली लेने की व्यवस्था कम से कम रेट पर सरकार कर सकती है अगर सरकार ऐसा करे तो किसानों को बिजी दी जा सकती है। इसी तरह से पानीपत थर्मल प्लांट की छठी यूनिट के पूरा करने की बात भी आयी है इसके लिए भी सरकार को तेजी से काम करना चाहिए। इसी तरह से एक मुख्य मुद्दा सिंचाई का आता है। आप जानते ही हैं कि सिंचाई एक ऐसी आवश्यक चीज है कि इसके बगैर खेती करने की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। आज भी मेरे इलाके में नहरों

के अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुचा है। मेरे आंकड़ों के हिसाब से 1950 क्यूसिक पानी वहां पर आना चाहिए था लेकिन आया इससे बहुत कम है। भाई अभय सिंह जिक्र कर रहे थे कि हमने आपके इलाके की फसल देखी है। हमें वहां बहुत अच्छी किस्म की फसलें लगीं। मैं सरकार से इस बारे में कहना चाहूंगा कि वह चाहें तो डी.सी. से पता करवा लें कि कितने एकड़ जमीन में जिला महेन्द्रगढ़ में बिजाई हुई है जो लोग खेती नहीं कर पाए उनके लिए सरकार कोई मुआवजे की व्यवस्था करे क्योंकि अगर किसान के पास साधन थे और वह बिजली के अभाव में या पानी के अभाव में खेती ठीक नहीं कर सका तो उसके लिए हम सरकार के लोग दोशी हैं। गांव में किसानों को बोरिंग करवानी पड़ती है और उसके लिए उन्हें काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि इसके लिए सरकार ऐसी कोई सबसिडी डिक्लेयर करे जिसके तहत बोरिंग का आधा पैसा किसान को देना पड़े व आधा पैसा सरकार दे। किसान को यदि सबसिडी मिलेगी तो वह बोरिंग करवाएगा। अब मैं पीन के उचित बंटवारे के बारे में बात करना चाहूंगा। जो मैं समझ पाया हूं उसके हिसाब से हरियाणा में पानी के मामले में दो तरह के इलाके हें एक तो सिरसा, हिसार और फतेहाबाद का इलाका है जहां हजारों एकड़ जमीन सेम की वजह से खराब हो जाती है और दूसरा इलाका महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी और भिवानी का है जहां हजारों एकड़ जमनी में पानी के अभाव में खेती नहीं हो पाती है। जो पानी है उसका हिस्सा हमें जिले वार मिलना चाहिए। जहां पानी की अधिकता की वजह से जमीन खराब

हो रही है वहां से हमारे यहां के शुश्क और रेतीले इलाके को पानी मिलना चाहिए। अब मैं एस.वाई.एल. के बारे में बात करना चाहूंगा। एस.वाई.एल. हमारे हरियाणा प्रदेश की जीवन रेखा है। एस.वाई.एल. बनाने के लिए आज जो हरियाणा प्रदेश की चौ. ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार है वह सक्षम है क्योंकि केन्द्र में भी भाजपा की सरकार है व यहां की सरकार में भी भाजपा हिस्सेदार है इसलिए आज के दिन यदि एस.वाई.एल. का काम नहीं हो सकता तो मैं समझता हूं कि यह फिर कभी भी नहीं हो सकता। वैसे भी इनकी सरकार का यह नारा रहा था कि बिजली पानी का प्रबन्ध हम करेंगे। चौ. देवी लाल जी भी यही चाहते थे और यह सरकार कहती भी है कि हम चौ. देवी लाल से सपनों को साकार करने जा रहे हैं। आज चार साल तो हमें भी देखते देखते हो गए। डेढ़ साल से तो चौटाला साहब की सरकार को देख रहे हैं। सरकार कृपया सदन को बताए तो सही कि एस.वाई.एल. के बारे में आज तक क्या कार्यवाही हुई है? (विघ्न)

सरदार जसविन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इनसे जानना चाहूंगा कि कांग्रेस के समय में यह काम क्यों नहीं किया गया?

राव नरेन्द्र सिंह: कांग्रेस ने गलत किया तो क्या आप भी गलत करेंगे? एस.वाई.एल. के मुद्दे पर सदन को संतुश्ट करने की बात नहीं है यह जवाब तो आपने को जनता को देना पड़ेगा। आप अपनी जिम्मेदारी को न भूलें। आप अपने को किसानों को

हमदर्द कहते हैं और यह भी कहा जाता है कि यह किसानों की सरकार है इसलिये यह काम करना आपका फर्ज बनता है, धर्म बनता है। बरसाती नदियों के बारे में मेरा सुझाव है कि सरकार को बांध बांधने को व्यवस्था करनी चाहिये। हमारे इलाके में साहबी, कृश्णावती और दोहान नदियां हैं जिनके पानी में हमारा भी हिस्सा है लेकिन राजस्थान सरकार ने अपने यहां अपने हिस्से में बांध बना लिये हैं जिनकी वजह से हमारे हिस्से में कोई पानी नहीं आ पा रहा है। उनका तो ठीक हो गया है लेकिन हमारे इलाके का काम बिल्कुल खराब हो चुका है। स्पीकर साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उच्च स्तरीय लैवल पर राजस्थान सरकार से इस बारे में बातचीत की जाए। जो पानी का हमारा हिस्सा है वह हमें अवश्य मिलना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी नौलेज में एक बात और लाना चाहूंगा कि नारनौल एरिया में हमारे दोहान पच्चीसी के 25 गांवों ने वर्श 2000 में हुये चुनावों का बहिश्कार किया था। उनकी मुख्य मांग थी कि हमें पाने का पानी मिले लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इनकी इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहां के गांवों में खेती नहीं हो रही है वहां सभी बिरादरियों के गांव है और समय–समय पर आन्दोलन करते रहे हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि उस इलाके को सरकार सूखा–ग्रस्त क्षेत्र घोशित करे ताकि किसानों को कुछ राहत मिले सके। अध्यक्ष महोदय, अब मैं जन स्वास्थ्य के बारे में कहना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाशण मे 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी देने की घोशणा अटेली और

नारनौल में की थी लेकिन मैं उनको बताना चाहूंगा कि ऐसे–ऐसे गांव भी हैं जहां पानी की व्यवस्था ही नहीं है लोगों को पीने के लिये पानी नहीं मिल रहा है। कई गावों में बौरिंग फेल हो चुके हैं। इसलिये वहां पर नहरों पर आधारित जल योजना को लागू किया जाये कयोंकि वहां की हर नहर में पानी भी है। जहां तक औद्योगिक विकास का ताल्लुक है, आज प्रदेश से उद्योग प्लायन हो रहे हैं। प्रदेश में आम यह बात सुनने को मिल रही है कि मौजूदा सरकार ने जो औद्योगिक नीति लागू की है उससे उद्योग वाले घबरा रहे हैं। मैं किसी की आलोचना नहीं करता लेकिन हमें इस बात को देखना चाहिये कि मौजूदा उद्योगों को किसी बात का डर है कि वे यहां से प्लायन कर रहे हैं जबकि दिल्ली के तीन तरफ हरियाणा लगता है परन्तु हरियाणा की बजाए नये उद्योग राजस्थान में भिवाड़ी, और बहरोड तथा उत्तर प्रदेश में नोयडा में जा रहे हैं और ये सारे क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र में डिवैल्प हो रहे हैं। हरियाणा में डिवल्पमैंट क्यों नहीं हो रहा है इसके लिये हरियाणा सरकार को पहल करनी होगी और महेन्द्रगढ़ जैसे पिछड़े इलाके को सबसिडी देकर औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ा क्षेत्र घोशित किया जाये ताकि वहां पर भी ज्यादा से ज्यादा उद्योग लग सकें।

शिक्षा के मामले में मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। क्या कारण है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होती जा रही है और स्कूल व्यापार का केन्द्र बनते जा रहे हैं? यहां तक कि सरकारी अध्यापकों के बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में

पढ़ रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करें। यह एक अच्छा कदम है कि सरकार ने सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी पढ़ाने की व्यवस्था की है। परन्तु ऐसी व्यवस्था की जाये जिससे सरकारी स्कूलों को रिजल्ट अच्छा रहे ताकि आगे पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दाखिले में कोई परेशानी न आने पाये। नौकरियों में तो सरकार का हस्तक्षेप चलता है यह बात तो मैं भी मानता हूं लेकिन आजकल तो सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिये भी राजनैतिक हस्तक्षेप चलने लगा है जैसे जे.बी.टी. और इजींनियरिंग कालेजों में काफी राजनैतिक हस्तक्षेप चलने लगा है यह अच्छी बात नहीं है। इन दाखिलों में कहीं मंत्रियों की लिस्ट तो कहीं अधिकारियों की लिस्ट चलने लग गई है। मैं मानता हूं कि नौकरी में तो हरेक सरकार का हस्तक्षेप चलता है चाहे वह किसी दल विशेश की सरकार रही हो।

श्री अध्यक्ष: आप यह मानते हैं कि आपकी सरकार के समय में नौकरियों में सरकारी हस्तक्षेप चलता था?

15.00 बजे

राव नरेन्द्र सिंह: सर, मैं इस बात को मानता हूं और यह तो हर सरकार में चलता है परन्तु जे.बी.टी., इंजीनियरिंग और मैडीकल कालेजों में दाखिले के समय भी सरकारी हस्तक्षेप चलेगा तो जो होनहार छात्र होंगे उन्हें तो एडमिशन नहीं मिल पायेगा।

एक बात मैं मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को विधायकों के क्या नाराजगी हे कि पंजाब और राजस्थान के अन्दर विधायकों की ग्रांट मिल रही है परन्तु हरियाणा के विधायकों को विधायक ग्रांट नहीं मिल पा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी काफी तजुर्बेकार हैं कई ओहदों पर रहे हैं जब वे विपक्ष में होते थे तो चौत्र संपत सिंह जी के साथ और चौ. धीरपाल सिंह जी के साथ मिलकर हमारे साथ यह बात कहा करते थे कि पता नहीं चौ. बंसी लाल जी ने विधायकों की ग्रांट क्यों बंद कर दी है। मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे विधायक ग्रांट को जारी कर दें क्योंकि लोकसभा में एम.पी. की ग्रांट दो करोड़ है तो कम से कम विधायक ग्रांट को एक करोड़ रूपये तो अवश्य करें क्योंकि गांवों में जब हम जाते हैं तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात पर गौर करेंगे अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे विकास के मामले में चाहे विपक्ष के विधायक का क्षेत्र हो या दूसरी पार्टी के विधायक का क्षेत्र हो, एक समान नहर से व्यवहार करें। विकास के मामले में प्रदेश के अन्दर इस तरह की बता नहीं की जानी चाहिये कि फलां विधायक विपक्ष का है तो उसके क्षेत्र में विकास के कार्य कम करवाए जाएं। विकास के मामले में सभी क्षेत्रों`स एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): राव नरेन्द्र सिंह जी, अटेली के लोगों को क्या कोई दिक्कत है, वहां तो विकास के सबसे ज्यादा काम हुये हैं।

राव नरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि प्रदेश के लोगों को विकास के कार्यों में समान हिस्सा मिलना चाहिये। बुढ़ापा पैंशन और बी.पी.एल. का दोबारा से सर्वे होना चाहिये क्योंकि कई जैयुयन केस रह गए हैं अगर उनको भी इनमें शामिल कर लिया जाएगा तो मैं समझता हूं कि यह उनके लिये न्याय होगा।

श्री अध्यक्ष: राव नरेन्द्र सिंह जी, अब आप बैठिये।

राव नरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरी कांस्टीच्युएंसी की बात अभी रह गई है। मैं क्वैश्चन आवर के बाद अपने हल्के के बारे में कुछ कहना चाहता था लेकिन आपने मुझे इसका मौका नहीं दिया था।

श्री अध्यक्ष: राव नरेन्द्र सिंह जी, इस बारे में अभी तक आपका कोई लिखित नोटिस हमारे पास नहीं आया है।

राव नरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, रोहतक में बाबा मस्तनाथ मठ, अस्थल बोहर के महंत चांदनाथ योगी से अज्ञात लोगों द्वारा 2 करोड़ रूपये की मांग की गई। उस मंहत ने पुलिस सुरक्षा मांगी लेकिन उसको सुरक्षा नहीं मिली। मैं समझता हूं कि उस महंत को सुरक्षा मिलनी चाहिए थी। (शोर)

श्री अध्यक्षः राव नरेन्द्र सिंह जी, अब आप बैठिये, आप 20मिनट बोल चुके हैं।

राव नरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं 5 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से मेवात विकास बोर्ड बनाया है और जिस तरह पंचकूला में शिवालिक विकास बोर्ड बनाया हुआ है उसी तरह से यदि सरकार अहीर विकास बोर्ड बना दे तो वहां के लोगों का कल्याण होगा।

श्री ओम प्रकाश चौटालाः राव नरेन्द्र सिंह जी, आप जातिवाद की आदत नहीं छोड़ रहे हैं, जातिवाद, मजहब को बढ़ावा देना कांग्रेस की प्रवृति है।

राव नरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि अहीरवाल को जो इलाका हैं उसमें गुड़गांव से नारनौल तक का इलाका आता है और इसमें हर बिरादरी के लोग है। हमारे डिप्टी स्पीकर साहब भी उसी इलाके के हैं इसलिएये जातिवाद वाली कोई बात नहीं है।

श्री ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, फिर तो इनके नेता भी बिश्नोई विकास बोर्ड बनाने के लिये कहेंगे। इसलिये इस प्रथा को बदलो। जाति पाति का कोई मामला नहीं है। यह सैकुलर स्टेट है। (इस समय मेजें थपथपाई गई)

राव नरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, अगर ये अहीरवाल के नाम को ठीक नहीं मानते हैं तो मुख्यमंत्री महोदय दक्षिणी हरियाणा विकास बोर्ड बना दें। इसके अलावा मैं नारनौल बाई पास बनाने के बारे में प्रार्थना करना चाहूंगा। नारनौल में आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। वहां पर इइसका आलरेडी काम चल रहा है इसलिये उसको पूरा करवाने की कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, ने नारनौल में सरसों के तेल की मिल लगाने की घोशणा की थी, उसको भी पूरा करवाने की कृपा करें। नारनौल ऐतिहासिक स्थान है, वहां एक जल महल है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी निवेदन करूंगा कि वहां पर टूरिस्ट डिपार्टमैंट द्वारा कोई व्यवस्था करवाएं ताकि वह एक अच्छा पर्यटक स्थान बन सके। इसके अलावा मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि नारनौल में नांगल चौ. रोड पर रेलवे का ओवर ब्रिज बनवाने की भी व्यवस्था करवाएं क्योंकि वहां घंटों–घंटों जाम लगा रहता है। इसी तरह से नांगल चौ. में बस स्टैण्ड और अनाज मंडी भी बनवाने की व्यवस्था करवाएं। धन्यवाद।

श्री राम किशन फौजी (बवानी खेड़ा, अनुसूचित जाति): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर बोलने के लिये समय दिया इसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरी उम्र तीस साल हो गई है और मैं एक रिटायर्ड फौजी हूं लेकिन राज्यपाल महोदय का अभिभाशण जितना **** है, इतना आज तक कही नहीं देखा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य ने अभिभाशण के बारे में जो गलत शब्द इस्तेमाल किया है उसे हाउस की कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री राम किशन फौजी: अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय का अभिभाशण असत्य पर आधारित है। इसमें कहा गया है कि आज के दिन पूरे हरियाणा में 40 लीटर पीने का पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दिया जा रहा है और कई जगह 70 लीटर भी दिया जा रहा है। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि मेरे हल्के के 25 गांवों में पीने के लिये त्राहि–त्राहि मची हुई है। पानी–पानी करके वहां के लोगों की आंखों के आंसू भी सूख गये हैं। खेती के लिये तो पानी मिलना दूर की बात है उन 25 गावों के सर्दियों में भी पीने के पानी की दिक्कत रहती है। लोग 4–5 दिन तक नहाते भी नहीं हैं। अगर सर्दियों में यह हालत है तो गर्मियों में क्या होगा? कानून व्यवस्था या बिजली का मामला तो बाद का है पहले लोगों को पीने का पानी उचित मात्रा में मिलना चाहिये। वहां के लोग तोशाम हल्के के टैंकरों द्वारा पीने का पानी लेकर आते हैं हवां पर साल में लोग 20–20 हजार रूपये का पानी लेकर आते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा कि एक तो उन 25 गांवों पर कुदरत की मार पड़ रही है क्योंकि बरसात नहीं हो रही है और दूसरी तरफ सरकार भी उनके लिये कुछ नहीं कर रही है। क्या सरकार उन गांवों में पीने का पानी पहुचाने के लिये वहां पर नये टयूबवैल लगायेगी या नहरों की टेल तक पानी

पहुंचायेगी ताकि वे लोग पीने क पानी के साथ साथ कुछ खेती भी कर सकें? अध्यक्ष महोदय, किसान किसी नेता के बहकावे में आकर आंदोलन नहीं करता बल्कि मजबर होकर आंदोलन करता है। वहां कि किसानों को पानी न मिलने के कारण उन्होंने आंदोलन किया और सरकार ने उन्हें पानी देने की बजाय जेलों में बंद कर दिया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर वहां के किसानों को पानी दे दिया जासये तो वे लोग आंदोलन नहीं करेंगे बल्कि अपने घरों को चले जायेंगे। इस बारे में मैंने भी मुख्यमंत्री महादय को कहा था कि मेरे हल्के के लोगों की बिजली और नौकरी एक साल बाद दे देना लेकिन उनको पीने का पानी पहले दिया जाये। जब मैं उन 25 गावों में जाता हूं तो वहां की मां–बहनें मुझे कहती हैं कि भाई तुम मुख्यमंत्री महोदय, को हमारी समस्या बताआ और हमारे लिये पीने का पानी लेकर आओ। मेहनत, मजदूरी तो हम दूसरी जगह कर लेंगे। अध्यक्ष महोदय, वहां पर पानी की समस्या गरीब आदमियों के लिये ही है न कि अमीर आदमियों के लिये। अमीरों को तो वहां पर अब भी पानी मिल रहा है। वहां पर पानी के कनैक्शन लेने के लिये सिक्योरिटी 500 रूपये कर दी है। एक गरीब आदमी जो मजदूरी करके 50 रूपये दिन के कमाता है वह 500 रूपये कहां से देगा? इस बारे में मेरा मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि वहां पर गरी बस्तियों में नुक्कड़ पर नल लगाया जाये ताकि गरीब आदमी को पानी के पानी की समस्या न हों। जहां तक बिजली की बात है वह भी गांवों में बहुत कम आती है, शहरों में तो 10–12 घंटे आती है।

शाम को किसान जब खेती करके घर आता है तो बिजली नहीं होती वहां पर बिजली रात के 11 बजे के बाद आती है। किसान को पशुओं के लिये चारा काटना होता है। ऐसे में किसान के पास एक ही रास्ता होता है कि वह हाथ से चारा काटकर पशुओं को खिलाये अन्यथा पशु भूखे मरेंगे। किसान खेत में भी मेहनत करता है और फिर घर आकर चारा भी काटना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मैंने चीन, पाकिस्तान और नेपाल बोर्डर देखा है वहां पर सब यही कहते हैं कि हिन्दुस्तान के अन्दर हरियाणा बहुत ही खुशहाल राज्य है वहां पर सत्य बोला जाता है। लेकिन अब उल्टा हो रहा है यहां पर हर जगह **** बोला जाता है।

श्री अध्यक्ष: यह शब्द हाउस की कार्यवाही से निकाल दिया जाये। ****

श्री राम किशन फौजी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जैसे एम.एल.ए. या दूसरे बड़े अधिकारी तो अपने बच्चो को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिये बाहर दिल्ली और बम्बई भेज सकते हैं लेकिन सरकारी स्कूलों में तो सबसे ज्यादा गरीबों के बच्चे ही पढ़ते हैं आज 36 बिरादरियों में गरीबी बढ़ गई है क्योंकि जमीनें थोड़ी रह गई हैं इसलिये गांवों के ज्यादातर लोगां को मजदूरी के लिये मजबूर होना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, 20 साल बाद, 50 साल बाद गांवों में केवल गरीब लोग ही मिलेंगे, हमारे जैसे एम.एल.एज, एम.पीज. और दूसरे बड़े अधिकारी गांवों में नहीं रहना पसन्द करेंगे। इसलिये मेरा आपके

माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि गांवों में नहीं रहना पसन्द करेंगे। इसलिये मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि गांवों में सरकारी स्कूलों के अन्दर ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जाएं ताकि हर बिरादरी के लोगों के बच्चे स्कूलों में शिक्षा ले सकें। अध्यक्ष महोदय, बड़े लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में एडमिशन करा भी देते हैं तो फेल होने पर वे अपने बच्चों को बाहर पढ़ाई के लिये भेज सकते हैं लेकिन गरीब का बच्चा फेल हो गया तो वह वहां से कहीं भी नहीं जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, अगर किसी ने घर में बिजली का कनैक्शन लेना हो तो बिजली के कनैक्शन की सिक्योरिटी सबके लिये बराबर है। मैं चाहता हूं कि इसमें भी गरीबों को कुछ राहत मिलनी चाहिये। अगर एक करोड़पति ने बिजली का कनैक्शन लेना हो तो उसके लिये भी 1600 रूपये सिक्योरिटी है और यदि एक गरीब आदमी के कनैक्शन लेना हो तो उसके लिये भी 1600 रूपये सिक्योरिटी है। अध्यक्ष महोदय, पहले तो गरीब आदमी यह क्वैक्शन लेगा नहीं और अगर वह कनैक्शन लेगा भी तो किसी साहूकार से कर्ज मांग कर लेगा। उसकी सारी जिन्दगी ब्याज देते देते गुजर जाएगी। इसलिये मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि गरीबों को बिजली के कनैक्शन की सिक्योरिटी भरने में कुछ राहत दी जाए ताकि गरीबों का भला हो सके। अगर सरकार ऐसा करेगी तो इसके लिये में सरकार का धन्यवाद करूंगा। अध्यक्ष महोदय, पहले यह सिक्योरिटी 250 रूपये होती थी लेकिन अब 1600 रूपये सिक्योरिटी है। सरकार के पास टैक्स लगाने के लिये

और बहुत सी जगह है इसलिये इस सिक्योरिटी की राशि को कम किया जाए। अध्यक्ष महोदय, हमारे जैसे नेता बाहर जाकर भाशणबाजी करते रहे हैं कि गरीबों के लिये पीले कार्ड बने हुये हैं। इस बारे में अगर चौ. बंसी लाल भी हाउस के अन्दर झूठ बोलैंगे तो मैं उन्हें हाउस के अन्दर झूठा कहूंगा। अध्यक्ष महोदय, गांवों में गरीब आदमियों के पीले कार्ड नहीं बने हैं। अगर कोई एम.एल.ए. अधिकारी को टेलीफोन कर देता है तो उसका पीला कार्ड बन जाता है। लेकिन गरीब आदमी तो एम.एल.ए. तक भी नहीं पहुंच पाता इसलिये उसका पीला कार्ड नहीं बन पाता। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का दोबारा से सर्वेक्षण करा कर गरीब लोगों के पीले कार्ड बनवाये जाएं। अध्यक्ष महोदय, अब बुढ़ापा पैंशन की बात आती है इसमें भी वही पीले कार्ड वाली बात आती है। गरीब आदमियों की बुढ़ापा पैंशन नहीं बनी हुई है। इसलिये इसके लिये भी दोबारा से सर्वेक्षण कराया जाये उसमें चाहें तो एम.एल.ए. की डयूटी भी सर्वेक्षण में साथ लगा दें। हम भी अधिकारियों के साथ चले जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, पहले अधिकारी कुर्सी के नीचे से रिश्वत लेता था जबकि आज खुले आम रिश्सत ले रहे हैं क्योंकि सरकार तो 'सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम' में व्यस्त रहती है। इसलिये मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस तरह की तानाशाही को भी मिटाया जाए। स्पीकर साहब, मैं बताना चाहता हूं कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले लोगों के लिये जो मकान बताये जाते हैं वे मकान उनको नहीं मिलते

हैं। जो गरीब लोग हैं उनके लिये मकान लेने के लिये शर्तें ऐसी रख दी हैं जिनके कारण वे लोग वे मकान नहीं ले सकते हैं। वहां पर तहसीलदार या बी.डी.ओ. जाकर कहते हैं कि जिसके घर में एक लट्टू होगा यानी एक बल्ब होगा, जिसके घर में सिलवर का गिलास होगा इसको इस तरह का मकान मिलेगा। सिलवर के गिलास तो यू.पी. और बिहार के लोगों के पास होते हैं हरियाणा प्रदेश में किसी के घर में सिलवर का गिलास नहीं मिलेगा। मैं कहना चाहता हूं कि उनको मकान लेने के लिये शर्तों में छूट दी जाए ताकि उनको मकान मिल सकें। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि गरी ब लोगों के लिये जो मकान बनाए जाते हैं उनका पैसा बीच में ही खा जाते हैं गरीबों को उन मकानों के बारे में कोई राहत नहीं मिलती है। इसलिये इस बारे में अच्छे आदमियों की एक टीम भेज कर सर्वे करवाएं और अच्छे अदमियों को भेज कर गरीब लोगों के लिये मकान बनवाएं। स्पीकर साहब, अब मैं परिवहन के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। यह बात ठीक है कि पहले की सरकारों ने प्रदेश में बसें खरीदी हैं और अब भी बसें खरीदी जा रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि गांवों में हरियाणा रोडवेज की बसें जानी चाहिए। गांवों की हमारी बहन बेटियां पढ़नने के लिये गांव स 20—20 किलोमीटर दूर जाती हैं। स्पीकर साहब, आज ऐसा समय आ गया है कि हमारी बहन बेटियां पढ़ने के लिये गांव से बाहर पैदल नहीं जा सकती। गांव का गरीब किसान कहता है कि बेटी तू पढ़ने के लिये गांव से बाहर मत जा क्योंकि आज

जमाना खराब है। गरीब किसान अपनी बेटी से कहता है कि तू पढ़ने से टाल कर दे। मैं कहना चाहता कि गांवो में रोडवेज विभाग की बसे न जाने से हमारी बहन बेटियों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है उनको बहुत असुविधा हो रही है। जिस प्राइवेट बसों को सरकार ने परमिट दिये हुये हैं वे इस बात को मानते नहीं है कि उनकी बसों में हमारी बहन बेटियां पढ़ने के लिये जाएं। जब हम इस बारे में जी.एम. को कहते हैं तो वह कहता है कि यह रूट तो प्राईवेट बस का है इसलिये हरियाणा रोडवेज का इसेस कोई लेना देना नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी प्राईवेट बसों का रूट परमिट रद्द किया जाये जो हमारी बहन बेटियों को अपनी बसों में पढ़ने के लिये जाने पर रोकते हैं। प्राइवेट बसों के परमिट रद्द करके उनकी जगह हरियाणा रोडवेज की बसें लगाई जाए ताकि हमारी बहन बेटियों को सुविधा मिल जाए। स्पीकर साहब, जहां तक स्वास्थ्य की बात है, मैंने इस बारे में पहले भी सुझाव दिया था। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि गांवों के अस्पतालों में दवाईयां नहीं जाती हैं और न ही वहां पर डाक्टर जाते हैं। डाक्टर अपनी पांच दिन की हाजरी एक दिन जाकर भर कर आ जाते हैं। पेशैंट को दवाईयां पर्ची पर लिख दी जाती है। वहां पर जो दवाई होती है वह बड़े बड़े अफसरों को या मेरे जैसे को मिल जाती है गरीबों को नहीं मिलती है। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि कि चैकिंग करने के लिये एक टीम गठित की जाए और जो डाक्टर गरीबों को इवाई नहीं देते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए ताकि गरीब लोगों

को राहत मिल सके और उनको दवाई मिल जाए। स्पीकर साहब, अब मैं पंचायतों के बारे एक बात कहना चाहूंगा। गांवों में जहां पर गलियां बननी चाहिएं वहां पर गलियां नहीं बनाई जाती हैं। यदि किसी गांव में किसी गली को पक्की बनाने के बारे में कोई टेलीफोन चला जाता है, जैसे मेरा टेलीफोन चला गया या किसी और का चला गया तो वह गली बना दी जाती है। स्पीकर साहब, गांव में सरपंच जिस गली को पक्का बनाने के लिये कहता है उसको बना दिया जाता है और जिस गली को ऊंचा उठाकर बनाने के लिये कहता है उसको बना दिया जाता है लेकिन गांव में गरीब लोगों के घरों के आगे गलियां पक्की नहीं बनाई जाती हैं। मैं कहना चाहूंगा कि गरीब लोगों के घरों के आगे की भी गलियां पक्की बनाई जाएं। अध्यक्ष महोदय, यहां पर सभी साथी चुन कर आये हैं। हमें यहां पर अपने हल्के की बातें कहनी चाहिये न कि रैली की। यहां पर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस वाले सुबह से रैली की ही बात कर रहे हैं। रैली का विशय सदन से बाहर का विशय है (शोर एवं विघ्न) स्पीकर साहब, आज पुलिस की भर्ती के लिये 500 रूपये फार्म के नाम से लिये जा रहे हैं। 500 रूपये इतने अधिक रख दिये हैं कि इससे जो गरीब लोगों के बच्चे हैं वे तो पुलिस की भर्ती में खड़े हो नहीं सकते। पुलिस की भर्ती के पूरे प्रोसिजर में 10 दिन का समय लग जाता है। वहां पर एक तो समय की बर्बादी होती है और दूसरे फार्म की कीमत इतनी अधिक रख दी कि गरीब आदमी तो पुलिस की भर्ती के बारे में सोच भी नहीं सकता। इस संबंध में मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस फार्म

की कीमत को बिल्कुल खत्म किया जाये या कम से कम कीमत रखी जाये ताकि आम गरीब आदमी भी पुलिस की भर्ती में खड़ा होने की हिम्मत कर सके।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं कानून व्यवस्था की बात कहना चाहता हूं। आज प्रदेश के अन्दर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रही। सिवानी के अन्दर दिन दिहाड़े लोगों को उठाकर ले जाते हैं। उनसे फिरौती के रूप में 2–2 लाख रूपये से लेकर 5–5 लाख रूपये तक मांगे जाते हैं। इस तरह की जो घटना सिवानी में हुई थी उसका आज तक कुछ पता नहीं चल पाया। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि कानून व्यवस्था की तरफ सरकार अपना पूरा ध्यान लगाये ताकि लोग राहत महसूस कर सकें। अन्त में स्पीकर साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री कंवर पाल (छछरौली): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे गवर्नर महोदय के अभिभाशण पर बोलने के लिये समय दिया। अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को और हरियाणा सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे मुश्किल के समय में जब देश में एक बहुत बड़ी विपति आयी थी और हमारे भाई गुजरात में एक ऐसा कश्ट झेल रहे थे जिसका अन्दाजा लगाना बहुत मुश्किल है, ऐसे कठिन वक्त में हमारी सरकार ने जो

काम करके दिखाया उसके लिये वह वाकई बधाई की पात्र है। इस मामले में हरियाणा सरकार के काम की हर जगह पर सराहना हुई है। हिन्दुस्तान में हर जगह पर चर्चा रही है कि जो काम हरियाणा ने करके दिखाया है वह किसी और की तरफ से नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं शिक्षा नीति के बारे कुछ बातें कहना चाहूंगा। यहां पर बोलते हुये कई साथियों ने जिक्र किया जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनमें बच्चों की संख्या घटती जा रही है। इसका कारण यह है कि हमारी जो ट्रैंक है वह यह हो चुका है कि आज हर कोई अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना चाहता है। यही कारण है कि आज के दिन सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या घटती जा रही है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसी बात को ध्यान में रखते हुये यह कदम उठाया है कि सरकार स्कूलों में भी पहली कक्षा से अंग्रेजी विशय को अनिवार्य विशय बनाया जायेगा। ऐसा होने पर अब गरीब व्यक्ति भी इसका फायदा उठा पायेंगे। हमारी सरकार ने यह नियम बनाया हुआ था कि गावों में यदि लड़कियों के लिये स्कूल में होस्टल बनाया जाता है तो सरकार अपनी तरफ से दुगनी ग्रांट देगी और यदि शहर में लड़कियों के लिय स्कूल में होस्टल बनता है तो उसको तीन गुणा ग्रांट दी जायेगी। मेरे हल्के में भी एक स्कूल के अन्दर लड़कियों के लिये होस्टल बनाया जा रहा था। जब ग्रांट की बात आयी थी तो उस वक्त यह नोटिस में आया कि शहर के लिये यह ग्रांट तीन गुणा है और गांवों के लिये दोगुना है। जब इस संबंध में मैं मुख्य

मंत्री जी से मिला तो उन्होंने हमारी बात को ध्यान से सुनते हुये गांवों में भी ऐसे होस्टलों के लिये तीन गुणा ग्रांट देने की बात कही और हमारे उस स्कूल में जिसमें होस्टल बनाया जा रहा था, तीन गुणा ग्रांट बहुत जल्दी मिल गई। इसके लिये मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं किसानों की बात करना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी एक ऐसे अध्यक्ष के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रही है जिसको यह पता नहीं कि धान के पौधे में और गेहूं के पौधे में क्या अन्तर है? (शोर एवं विघ्न) अध्यक्ष महोदय, जहां तक धान की कीमत की बात है, आज परिस्थितियां बदली हुई हैं। इनके समय में जो परिस्थितियां थी वे आज नहीं हैं। इनके समय में लोगों को खाने के लिये अनाज नहीं मिलता था, खाने के लिये चावल नहीं था। इनके राज में राशन कार्ड पर अनाज मिला करता था और वह भी कहीं मिलता नहीं था। उस समय की इनकी केन्द्र की सरकार के पास 89 लाख टन अनाज का भण्डार था जबकि आज की केन्द्र सरकार के पास 246 लाख टन अनाज पड़ा हुआ है। केन्द्र की सरकार और राज्य की सरकार ने किसानों के हित की ऐसा योजनाएं चलाई जिसके कारण अनाज के उत्पादन में इतनी वृद्धि हुई है। वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने 95 रूपये प्रति क्विंटल गेहूं का रेट किसानों को बढ़ा कर दिया था। इससे किसानों का इतना हौसला बढ़ा कि उन्होंने खेती में जम कर मेहनत की। सरकार ने किसानों के लिये क्रैडिट कार्ड की योजना दी है और फसल बीमा

की योजना दी है जिससे आम किसान का भला हुआ है। अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने कहा है कि डीजल के दाम बढ़े हैं, मैं उनको यह बात बताना चाहता हूं कि डीजल हम नहीं बनाते हैं यह बाहर से आता है। इनकी पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और पूर्व मंत्री रहे हैं उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि चाहे वह हमारी सरकार है या कोई और सरकार होती, डीजल की कीमतें तो बढ़नी ही बढ़नी थीं। इसके साथ ही सबसिडी खत्म करने की बात ये कह रहे हैं तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि डंकल प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले ये लोग ही थे न कि भारतीय जनता पार्टी। उस पर साईन इन्होंने ही किये थे जो कि अब लोगों को भुगतने पड़ रहे हैं (विघ्न एवं शोर) (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुये) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने मित्रों से यह बात कहना चाहूंगा कि जो बात ये किसानों की उठा रहे हैं वह बिल्कुल झूठ है इन्हीं लोगों ने किसान को इस हालत तक पहुंचाया है। आज की सरकार ने तो किसानों को मान–सम्मान बढ़ाया है। आपने देखा है कि इस सरकार ने जवान में मान–सम्मान को बढ़ाया है, जहां तक पंचायतों की बात है, जहां तक पचांयतों की बात है, आज की सरकार ने पंचायतों का भी मान–सम्मान बढ़ाया है। उपाध्यक्ष महोदय, कारगिल में जो लोग शहीद हुये थे उनको जो मान–सम्मान इस सरकार ने और केन्द्र सरकार ने दिया है वह सराहनीय है। इससे पहले भी लड़ाईयां लड़ी गई थी। लेकिन तब शहीदों को ऐसा सम्मान नहीं मिलता था। उपाध्यक्ष महोदय, आपको ध्यान होता कि उन लोगों

को कितना मान–सम्मान इन लोगों ने दिया था। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं अपने हल्के की कुछ समस्याओं का भी जिक्र करना चाहूंगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा हल्का काफी पिछड़ा हुआ हल्का रहा है। मैंने पिछली दफा भी यह बात कही थी कि भगवान तो हमारे हल्के पर मेहरबान हैं। वहां पर पानी भी बहुत मीठा है और सब कुछ अच्छा है लेकिन वहां पर माईनिंग होती है। सारे हरियाणा में बजरी और रेत की जो सप्लाई होती है वह मैक्सीमम वहीं से निकलता है। उसकी वजह से सड़कों की हालत बड़ी खराब है और सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। हालांकि सड़कों पर काम चला हुआ है लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आप के माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस हल्के की सड़कों की ओर विशेश ध्यान दिया जाए। इस हल्के में से गुजरने वाली तीन सड़कें प्रमुख हैं। एक बी.के.डी. रोड है दूसरी शेरपुर से तहारपुर रोड और तीसरी जगाधरी से कलानौर वाया फतेहपुर रोड है। जो फतेहपुर वाली रोड है यह बाई पास बन सकती है। यमुना नगर में बड़ी भीड़ रहती है इसलिये इस सड़क को अगर बढ़िया बना दिा जाए और आगे उस पर कलानौर में रेल फाटक बना दिया जाता है तो शहर का काफी रश कम हो सकता है और शहर को फायदा हो सकता है। सरकार से मेरा निवेदन है कि पहाड़ के नजदीक होने की वजह से फल्ड का जो पानी आता है और यमुना नहर का जो पानी निकलता है उसकी वजह से मेरा हल्का काफी कटा–फटा है जहां पर काफी पुलियों के बनाने की जरूरत है। मैं सरकार से

आग्रह करूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे। जैसे कि घूडो पीपली गांव है यह बिल्कुल दूसरे इलाके से कटा हुआ है अगर सरकार यहां पर एक पुलिया बना दे तो इस गांव को जो 60 किलो मीटर का फासला तय करके शहर तक आना पड़ता है वह फासला सिर्फ 7–8 कि.मी. रह जाएगा। इसी तरह से टापू लाकड़मय, प्रताप पुरी, नवाज पुर है, मण्डौली घग्गड़ बडौली है। वहां पर भी एक–एक पुलिया बनाने की जरूरत है। इसी तरह से खिजराबाद से जो सड़क बिलास पुर जाती है उस पर भी अगर एक पुलिया बन जाए तो लोगों को बहुत लाभ हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाया चाहता हूं कि जो अधिकारी इस बारे में एस्टीमेटस बनाते हैं वह करोड़ों को होता है जबकि वास्तविकता में वहां पर एक पुलिया को बनाने की ही जरूरत होती है लेकिन वे लोग योजना पुल की बनाते हैं। अभी नन्दगढ़ में एक पुलिया बनी है। 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने इसको मन्जूर किया था। उससे पहले इसके लिये एम.पी. ग्रांट से पैसा देने की बात की गयी थी। जब मैं इसका एस्टीमेअस देखने के लिये गया तो उस समय इसका एस्टीमेटस, 12 लाख रूपये का बना हुआ था। लेकिन जब मुख्य मंत्री जी ने तीन लाख रूपये इसके लिये दिये तो यह पुलिया बन गई है। इस तरीके से जहां गॉज वे बन सकता है दूसरे तरीके से वहां पर रास्ता बनाया जा सकता है और मेरे ख्याल से यह सारा प्रोजैक्ट एक या डेढ़ करोड़ रूपये का प्रोजैक्ट है लेकिन जो इसका ऐस्टिमेटस है वह बहुत ज्यादा है। सरकार से मेरा निवेदन

है कि इस ओर ध्यान दे कर मेरे हल्के के काम करवाए जाएं। इसी तरीके से छछरौली से खिजराबाद मेन रोड है, जगाधरी से पौन्टा रोड है यह रूट 3–4 स्टेटस को यानी हिमाचल प्रदेश, उत्राखण्ड और यू.पी. को जोड़ता है इसलिए वहां पर एक बस स्टैण्ड होना चाहिए। मेरे ख्याल से छछरौली हरियाणा में पहले नम्बर का सबसे बड़ा ब्लाक है अगर नम्बर एक पर नहीं है तो दूसरे नम्बर पर तो होगा ही। लेकिन यहां पर कोई भी कालेज नहीं है। यमुनानगर में तो चार कालेज हैं। सर, इस ब्लाक में 172 गांव पड़ते हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि वहां पर एक कालेज बनाने की कृपा करें। छछरौली में एक हॉस्पीटल है उसके बारे में भी मेरा सरकार से निवेदन है कि उसको अपग्रेड करने की कृपा करें। उपाध्यक्ष महोदय, कालका से लेकर छछरौली तक जंगल का इलाका है और वहां पर जंगली जानवर किसानों की फसलों को बहुत नुकसान करते हैं। हाईकोर्ट की भी इन्स्ट्रक्शंज हैं कि कोई भी सिकी जंगली जानवर को नहीं मार सकता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वहां पर जिन किसानों की फसलों का जानवरों द्वारा नुकसान कर दिया जाता है उनको कुछ न कुद सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से पहले बोलते हुए मेरे एक साथी बी.पी.एल. कार्डज के बारे में जिक्र कर रहे थे। जहां पर भी जो अधिकारी बी.पी.एल. के कार्ड बनाने के लिए भेजे जाते हैं उनके द्वारा जो कार्डज बनाए जाते हैं उनमें कुछ गड़बड़ है। मेरा सरकार से निवेदन है कि जो भी कर्मचारी या अधिकारी कार्ड बनाने के लिए जाता है तो उसको यह

हिदायतें दी जानी चाहिएं कि जिस भी कर्मचारी या अधिकारी ने गलत कार्ड बनाया तो उसके लिए उसकी जिम्मेवारी फिक्स की जाएगी और उसके खिलाफ कार्यावाही की जाएगी। वहां पर जो कर्मचारी अधिकारी जाते हैं वे गलत कार्ड बना देते हैं वे ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। तो सरकार इस बारे में भी ध्यान दे। इसके अलावा यहां पर पुलिस भर्ती की भी बात आई थी। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि इस भर्ती में गावं से और गरीब लोगों के बच्चे भर्ती होने के लिए आएंगे। जो इसमें फीस रखी गई है यह निश्चित तौर पर ज्यादा है इसको भी कम करने के लिए सरकार कोई कार्यवाही करे। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री उदयभान (हसनपुर–अनुसूचित जाति): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, पांच मार्च को महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अपना अभिभाशण सदन में पढ़ा और फिर श्री भगवान सहाय रावत जी ने उनके प्रति जो धन्यवाद प्रस्ताव सदन में पेश किया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। राज्यपाल महोदय, बहुत ही आभार के पात्र हैं, जिन्होंने आदरणीय श्री ओम प्रकाश चौटाला जी के सशक्त नेतृत्व में चल रही सरकार के कार्यो का जो लेखा जोखा है उसको अपने अभिभाशण में पढ़ा है। यह बहुत ही सराहनीय है। उपाध्यक्ष

महोदय, गुजरात में जो त्रासदी हुइ है और हमारी सरकार द्वारा वहां पर जो सहायता की गई है उसके लिए इस सरकार की त्रासदी हुई है और हमारी सरकार द्वारा वहां पर जो सहायता की गई है उसके लिए इस सरकार की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। चाहे गुजरात में भूकम्प की त्रासदी हो या उड़ीसा में साईक्लोन से हुई त्रासदी हो, हमारे मख्यमंत्री जी ने बड़े ही सजग रूप से वहां पर युद्ध स्तर पर सेवा की है। उपाध्यक्ष महोदय, आप इस बात के गवाह है, वहां पर अध्यक्ष महोदय, भी गए, हरियाणा के लोगों ने, हरियाणा की संस्थाओं ने बहुत ही मेहनत से वहां के लोगों की सेवा की और वहां के लोगों को जो भी सुविधा दे सकते थे वह मुहैया करवाई। यह बहुत ही सराहनीय काम था और इस बारे में हरियाणा की सारे हिन्दुस्ताव में प्रशंसा की जा रही है और यहां तक कि प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी प्रशंसा की है। यह बहुत ही खुशी की बात है कि इस काम में हरियाणा की सिर ऊपर हुआ है। वहां के 19 गांवों के 9 हजार परिवारों को संभालने का कार्य हरियाणा सरकार के माध्यम से हरियाणा की जनता ने किया है। यह सरकार का बहुत ही सराहनीय कार्य है। उपाध्यक्ष महोदय, 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री जी ने एक और बेहतरीन कार्य किया है वह यह कि गांव–2 में पहुंचकर विकास की गंगा उन्होंने बहाई है। हरियाणा प्रदेश का ऐसा कोई इलाका नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है जाहं पर कुछ न कुछ विकास कार्य न करवाए गए हों। पिछली सरकारों के समय में चाहे वह चौ. बंसी लाल जी की सरकार हो या चाहे वह आदरणीय भजन लाल जी

की सरकार हो, सबमें विकास के कार्य पूरी तरह से रूक गए थे। लेकिन हमारी सरकार ने उन रूके हुए कामों को तीव्र गति से शुरू करवाया है। हर जगह पर उन्होंने विकास के काम करवाए हैं। सरकार ने 15846 कार्यों की घोशणा की थी जिसमें से 8006 कार्य पूरे हो चुके हैं। यह एक बहुत ही सराहनीय बात है। ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बार्ड द्वारा 192.55 करोड़ रूपये की राशि खच्र की गयी। नालियों एवं गलियों की मरम्मत पर 73 करोड़ 39 लाख, स्कूलों के भवनों के निर्माण एवं मरम्मत पर 16 करोड़ 31 लाख एवं हरिजन बैकवर्ड चौपालों के निर्माण पर 14 करोड़ 39 लाख रूपये खर्च किए गए हैं। इस तरह के ऐसे अनेक कार्य हैं जो हरियाणा सरकार ने हरियाणा की जनता के लिए किए हैं। इसके लिए स्वयं हरियाणा की जनता चौटाला साहब की सराहना करती रहेगा। इसके लिए वे वाकई सराहना के पात्र है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जहां तक शिक्षा का मामला है, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा दुर्भाग्य यह रहा है कि आजादी के बाद से हमारे देश के कर्णधार शिक्षा के प्रति उदासीन रहे हैं। कांग्रेस की सरकारों ने शिक्षा जैसे सबसे बुनियादी आवश्यकता की तरह कोई ध्यान ही नहीं दिया। इस देश में दोहरी शिक्षा प्रणाली लागू की गयी। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि गरीब बच्चे को और शिक्षा पढ़ाई जाती है और अमीर का बेटा दूसरी तरह की शिक्षा लेता है। जो शिक्षा की दोहरी पद्धति लागू की गयी है यह कांग्रेस पार्टी की देन है। आज जितने भी विकसित देश हैं वहां

पर चाहे गरीब हों या अमीर हों सबको एक जैसी ही शिक्षा पद्धति से पढ़ाई हासिल होती है। लेकिन हमारे यहां पर कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियों के कारण शिक्षा को रोजगार बना दिया गया। अमीर लोगों को दसूरी तरह की शिक्षा दी गयी और गरीबों को ओर तरह की शिक्षा दी गयी। पब्लिक स्कूलों के साथ–साथ इंग्लिश मीडियम के स्कूलों से सरकारी स्कूल मुकाबला नहीं कर सकते। उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकारों ने शिक्षा के महत्व को ठीक तरह से नहीं समझा है और इसलिए ही उन्होंने इस तरह कोई ध्यान नहीं दिया है। लेकिन हमारे मुख्यमत्री जी ने शिक्षा की तरफ पूरा ध्यान दिया है और इसीलिए सरकार ने दस हजार अध्यापकों की भर्ती की है जो इस बात की गवाह है कि सरकार शिक्षा के प्रति कितनी चिंतित हैं और इसको कितना सुधारना चाहती है। हमारी सरकार ने पहली कक्षा से अंग्रेजी की पढ़ाई अनिवार्य कर दी है और कम्पयूटर की पढ़ाई भी अनिवार्य कर दी गयी है। इसी तरह से इंफर्मेशन प्रोद्योगिकी की जो नीति अपनायी गयी है वह भी बहुत सराहनीय बात है। इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय की जितनी सराहना की जाए उतनी ही कम है। उन्होंने शिक्षा के लिए बहुत ही योगदान किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार शिक्षा को और अधिक गंभीरता से लेगी। हांलाकि सरकार ने पहले भी इस दिशा में अच्छा काम किया है। पहले कितने स्कूलों में टीचर ही नहीं थे लेकिन हमारी सरकार ने दस हजार टीचर भर्ती करके शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन लाने का और बच्चों के विकास की तरफ ध्यान देने का जो प्रयास किया है

वह बहुत ही काबिले तारीफ है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है।

इसी तरह से कृशि के मामले में सरकार का बहुत ही शानदार कार्य रहा है। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के समय में 122 लाख 50 हजार टन के विपरित 130 लाख 69 हजार टनन का उत्पादन करने में किसान सफल हुआ। केन्द्रीय पूल में हमने सबसे अधिक अन्न दिया और 38 लाख टन का भंडारण में योगदान दिया। गन्ने के रेट की जहां तक बात है, यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरकार ने गन्ने का रेट 110 रूपये प्रति क्विंटल दिया है। पूरे हिन्दुस्तान में कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है जिसमें 110 रूप्ये प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने का भाव दिया गया हो। गन्ने का जो बकाया भुगतान पिछली सरकार के समय से लंबित था वह 21 करोड़ रूपये का जो किसान को भुगतान नहीं हो पाया, वह भी इस सरकार ने दिया है। (विघ्न)

कनाडा के प्रतिनिधिमंडल का अभिनंदन

Mr. Speaker: Hon'ble Members, it is a matter of great pleasure for all of us that the Canadian Minister of Citizenship and Immigration Mrs. Elinor Capiun alongwith her husband Mr. Peter Sutherland, High Commissioner and the following M.Ps. are sitting in the V.I.P. Galleries in Haryana Vidhan Sabha for witnessing the proceedings of the House:-

1. Mr. Reginold Alcock

2. Ms. Collen Beaumier

3. Mr. Gurbax Malhi

4. Mr. Deepak Obhrai

5. Mr. Gurmant Grewal

6. Mr. Stephen Owen

7. Mr. Judy Wsalycia-Leis

8. Mr. Judy Sgro

I, on my own behalf and on behalf of this House welcome all of them. (Thumping)

Now, I would request the Hon'ble Chief Minister, Haryana to say a few words.

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाल): अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार की तरफ से व हरियाणा प्रदेश की जनता की तरफ से मैं कैनेडियन डैलीगेशन का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें बहुत प्रसन्नता है। चूंकि हमारी विधान सभा इन सैशन है और यह डैलीगेशन विधान सभा की कार्यवाही देखने आया है जिसके लिए हम इनका आधार व्यक्त करते हैं।

Mr. Speaker: Now, Sh. Bhajan Lal, would like to say a few words.

श्री भजन लाल: परम आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं कैनेडियन डेलीगेशन के अध्यक्ष, मैम्बर पार्लियामैंट साहेबान और

डेलीगेशन के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इन्होंने हरियाणा विधान सभा में पधारने की कृपा की है मैं इसके लिए इनका हृदय से धन्यवाद करता हूं और कांग्रेस पार्टी तथा हाउस के सभी माननीय सदस्यों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं।

राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर चर्चा (पुररारंभ)

Mr. Speaker: Now, Sh. Rajinder Singh Bisla, will speak.

Sh. Rajender Singh Bisla (Ballabhgarh): Mr. Speaker, I am grateful to you for allocating time to me for expressing my views on the Address of His Excellency, the Governor of Haryana, here on the 5th of March, 2001.

I am here to speak in favour of the adoption of motion of thanks on the Govenor's Address in toto. In the brief and well-drafted Address, His Excellency, the Governor has touched upon many initiatives taken by the Government of Haryana to enhance productivilty in different sectors of the State's economy as also to make the people more prosperous.

Before I embark on my mission, I welcome the 12-member Canadian delegation which is present here in the gallery to view the proceedings of the Legislative Assembly of Haryana. I welcome Hon'ble Ms. Elinor Capiun, Minister of Citizenship and Immigration, Canada; her husband Mr. Peter Sutherland, High Commissioner; Mr. Reginold Alcock, M.P.; Ms. Collen Beaumier, M.P.; Mr. Gurbax Malhi, Mr. Deepak Obheraui M.P.; Mr. Gurmant Grewal, M.P.; Mr. Stephen Owen,

M.P.; Ms. Judy Wasalycia-Lies, M.P. and Ms. Judy Sgro, M.P. and others.

Mr. Speaker, the State of Haryana being a gateway to north India has been a witness to several invasions and legandary battles. This is the land of the sacred Vedas where the Vedic civilisation prospered and gave us the heritage we are proud of. This is also the land of the great battle of Mahabharta and the celestial message delivered by Lord Krishna to Arjuna. The State of Haryana is the embodiment of 'Karma-dedication to duty without the expectation of rewards epitomised in the world famous 'Shloka' of the Gita.

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन।

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सड्गोडस्त्वकर्मणि।।

Only yesterday, the Prime Minister of India, Mr. Atal Behari Vajpayee had visited the holy land of Kurukshetra on the invitation of the Chief Minister, Mr. Om Prakash Chauatala. During this visit, the Prime Minister inaugurated the Kurukshetra Panorama and Science Centre depicting the 18 days of the gruelling battle of Mahabharta as also the pioneering efforts of the ancient Indians in the field of science. The Prime Minister, while addressing a hugely attended public meeting, himself endorsed what has been mentioned in the Governor's Address. Not only did he praise the industrial policy of the State Government, he went on to thank the Chief Minister for stepping in to rehabilitate the industrial units that had to shift out of the nation's capital Delhi. He made pointed references to the successful attraction of foreign direct investment by the Government of Haryana and complimented

the Chief Minister for taking a lead in providing world class infrastructure facilities for setting up industrial units in the State. The Prime Minister himself credited the State Government for following a very positive policy for the development of Information Technology in the State and also to set up private ventures in this regard. The Prime Minister went so far as to offer all the help from the Government of India for furthering this effort of the Government of Haryana.

Mr. Speaker, March 6, 2001 was a red-letter day for the State of Haryana when the rest of the nation heard their supreme leader Prime Minister, Sh. Vajpayee referring to Haryana as a role model for continous pursuit of excellence in all fields. Till recently, the rest of India has been under the impression that Haryana is only an agricultural State with little or no scope for industrial developemnt. It is this Government which has brought an investment worth Rs. 200 billion Indian rupees in a short period after the announcement of its liberal Industrial Policy in Novermber, 1999. The Chief Minister himself led a joint official-business delegation alongwith the P.H.D. Chamber of Commerce and Industry to the South-East Asian countries of Japan, Singapore and South Korea in October, 2000. In a short period to time, you have the biggest names in the multi-national corporations like Honda, Denso, Suzuki, Benetton, Perfetti, Y.K.K. and so on becoming a household name in Haryana with the commencement of plants and operations by these MNCs in Haryana.

The Information Technology Policy promulgated by this Government aims at upgrading the standard of

administration, especially in social and public services sector, providing public-centered, efficient and cost-effective Government, extensive percolation of IT literacy and education in the State, promotion of investments in IT industry and increasing the share of IT in the State's gross domestic product. A highlight of this policy of the stress to be laid on generating IT related employment opportunities and hehancing earning capacity of the people, thereby ensuring a better quality of life. The State Government is already planning to set up a world class Cyber City in Gurgaon and two such complexes near Panchkula also. The Government is shortly planning to establish a State to the Art Indian Institute of Inforamtion Technology.

A package of incentives has been given to the IT industries which includes preferential allotment of land, uninterrupted supply of power, facilities on captive power generator sets, liberal change of existing industry to IT and change of land use. No charges would be levied for change of land for the IT industry/IT parks upto March 31, 2003. Licences for setting up software technology parks would be given liberally and on easy payment terms. Single Desk Clearance would be provided for obtaining easy clearance and approval of various Government departments. On-line clearance and support network will be established linked all related departments and organisations. The Secretariat for IT would coordinate approvals and facilitation. Relaxation in Floor Area Regulation would be permitted upto 100 per cent in areas specifically notified by the State Government for IT units and IT parks.

The State has also embarked on a new Education Policy to make education employment-oriented. The highlights of this Education Policy are the introduction of English education from class-I and the familiarisation of students to the computers from class-VI onwards. This Government has also worked out a clear and transparent transfer policy for all its teachers. One of the objectives has been to ensure proper education facilities to the students from the rural areas of the State also to bridge the urban-rural divide. The Government has recruited more than 10000 teachers and can proudly claim that there is no vacancy whatsoever of teachers in the primary sector.

While setting forth on its vision of a more prosperous and developed Haryana, the State Government is deeply conscious of the great heritage of its citizens and the lofty ideals put forth by the founder of Haryana, Ch. Devi Lal. The Governor's Address has re-asserted the Government's faith in the dictum enunciated bythe partriarch of Indian politiecs Ch. Devi Lal, that लोकराज लोकलाज से चलता है and redecicates itself ot the goal of creation of a Haryana where every citizen lives and works in dignity and enjoys the fruits of all-round prosperity and none remains unemployed; where the farmers are enabled to produce to their optimum capacity and get full value for their crops; where the traders sincerely engage in commercial activities without fear; where the industrialists get due facilities of basic infrastrcture and create wealth; where Government employees perform their duties with dedication; and peace and prosperity prevail in the State.

This Government is actutely conscious of the fact that close to 80 per cent population of the State is engaged in agriculture, directly or indirectly. A part from meeting its own requirement for foodgrains, Haryana also contributes about 45 lakh tonnes of foodgains to the Central pool annually. The last year in the two crops of paddy and wheat harvested by the farmers, the State has seen all previous records being shattered. This happened inspite of the vagaries of nature when most of the State faced drought like situation. It was the efficient management of the resources of power and irrigation that the farmers were able to sow and cultivate their crops. In this period, the Government provided 13 per cent additional power to its citizens by additional generation of electricity and with tapping its influence with the Government of India by getting additional power allocation from the Central Power Utilities. Simultaneously, the cleaning of canals and their efficient management allowed canal waters to flow right upto their tail-ends in areas where no irrigation facilities were earlier available. The result was not only a bumper crop here in the State, but also a situation where the State of Haryana was able to lend a helping hand to the drought-affected States of Rajasthan and Gujarat by providinig them with animal fodder and grain.

A significant feature of this Government has been the personal leadership provided by the Chief Minister, Mr. Om Prakash Chautala in providing relief and help to the suffering humanity iin any part of the country in the face of natural calamities. Whether it was the cyclone-ravaged Orissa, drought-affected parts of Rajasthan and Gujarat or the earthquate-devastated Rapar Taluka of Gujarat, the residents

of Haryana under the leadership of Mr. Chautala rose to the occasion and provided relief to the millions of affected people. This fact was recognised by the Prime Minister himself in the presence of a sea of humanity yesterday at Kurukshetra when he made a pointed reference to this in his speech.

Mr. Speaker, Sir, in the end I would like to quote a Shloka from the third chapter of Gita;

यद्यदाचरति श्रेश्ठस्तत्तदेवेतरो जनः।

स यत्प्रमाणं कुरूते लोकस्तदनुवर्तते।।

Translated into English it implies that the conduct to the leader is followed by the common man and the milestones achieved by the leader are guiding stones for the rest of humanity. The Leader of the House, Mr. Chautala with his conduct, his bearing and his qualities of leadership, is already leading the residents of this great State to a glorious path.

This Government is taking all the right steps to lead the State towards a path of progress and prosperity in an environment of peaceful co-existence. In the period of five years. I am sanguine that the coming generations will refer to this period as the harbinger of peace and development leading the State to its pristine glory.

राव इन्द्रजीत सिंह: अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, में आपसे रूलिंग चाहता हूं। जो कनेडियन डेलीगेशन हाउस की कार्यावाही देखने आया हुआ था वह भी अब चला गया है। मैं

आपसे पूछना चाहता हूं कि रूल के हिसाब से क्या कोई सदस्य राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर लिखित स्पीच पढ़ सकता है? कृपया आप इस बारे में हाउस को बतायें। अगर नहीं पढ़ सकता तो बिसला जी ने तो अभी अपनी लिखित स्पीच पढ़ी है, क्या आगे से कोई सदस्य इस तरह स्पीच पढ़ सकेगा या नहीं?

श्री अध्यक्ष: आपकी बात ठीक है। कोर्ठ भी सदस्य लिखित स्पीच नहीं पढ़ सकता। अगर आप लिखित स्पीच में रैफरैंस देना चाहें तेा दे सकते हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला: अध्यक्ष महोदय, मैंने लिखित स्पीच नहीं पढ़ी। मैंने तो उसमें से सिर्फ हैडिंग देखी हैं। मैंने 1956 में पंजाब यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूं, मैं एक प्रैक्टिशनर वकील हूं। मैं कोई अनपढ़ नहीं हूं।

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जो कनेडियन डेलीगेशन के सदस्य इनकी इंगलिश सुन रहे थे, वे बीच में ही उठकर चले गये। उन्होंने इनकी पूरी बात नहीं सुनी क्योंकि इनकी इंगलिश उनको समझ ही नहीं आई। बड़े ही निचले स्तर की इनकी इंगलिश थी।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला: अध्यक्ष महोदय, मुझे ही नहीं बल्कि पूरे सदन को इस बात से हैरानी हुई होगी कि चौ. भजन लाल जी राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर ठीक तरह से नहीं बोल पाये, ये दो मिनट भी राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर

नहीं बोले। ये बहुत ही सीनियर नेता हैं और कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं तथा केन्द्र में कृशि मंत्री भी रह चुके हैं। इस समय ये विपक्ष के नेता हैं फिर भी ये राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर ठीक तरह से नहीं बोल पाये। जब इनका यह हाल है तो छोटी जनरेशन इनसे क्या सीखेगी? (शोर एवं व्यवधान) Sir, I am sorry to say this day, Chaudhary Bhajan Lal has made a mockery while speaking on Governor's Address.

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि विपक्ष के नेता की जो स्पीच राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर होनी चाहिए थी वैसी स्पीच चौ. भजन लाल जी नहीं दे पाये। इन्होंने राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर दो मिनट भी स्पीच नहीं दी। जिस वक्त इनको बोलने का मौका दिया गया उस समय ये एक मिनट बोले और बैठ गये। उस समय ऐसा लग रहा था कि ये इस स्पीच से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब हाउस के लीडर हैं इन्हें सोच समझकर बात करनी चाहिए। कौर कितना बोला है यह बात कल अखबार से पता लग जायेगी।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, अखबार से कया पता लगेगा। क्या चौ. भजन लाल सब कुछ अखबार से ही देखते हैं?

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, सही बातों का पता तो अखबार स ही चलता है। अखबार देश की शक्ति होता है।

16.00 बजे

श्री ओमप्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, विपक्ष की इस सीट पर जब मैं होता था तो तहलका उठा करता था। (शोर) अब तो हरियाणा मौज कर रहा है। हरियाणा की चारों तरफ मौज है। (शोर) इनको तो दिवाला पिट गया। (शोर) ये खू खाते में गये। (शोर) इनकी तो कही चर्चा ही नहीं। (शोर) इनका दिवाला पिट गया है। इनको हमारी बात मान लेनी चाहिए। (शोर) कोई संकोच नहीं करना चाहिए। (शोर) ये विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाए। यह बात इनको मान कर चलनी चाहिए। (शोर)

चौ. भजन लाल: आप बात दें कि कैसे निभाई जाती है? (शोर) आपकी ****

श्री अध्यक्ष: अब जो भी भजन लाल जी बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: मेरी हैसियत प्रदेश की जनता ने बनाई है। मैं प्रदेश का मुख्य मंत्री हूं। (शोर)

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, गलती हमारे से हुई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, इनस गलती हुई है तो अब भुगतें भी। (शोर) दूसरे के ऊपर अपना दोश क्यों मढ़ते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सभी सीटों पर बैठें। अब इन्द्रजीत जी बोलेंगे।

राव इन्द्रजीत सिंह (जाटूसाना): स्पीकर महोदय, 34वां या 35वां गवर्नर एड्रैस इस विधानसभा के सामने रखा गया है। सन् 1966 के अन्दर हरियाणा पंजाब के अलग हुआ था। इस बजट सत्र के गवर्नर एड्रेस में ऐसी कई चीजों पर चर्चा की गई जो कि पिछले 30–35 वर्शों से करते आ रहे हैं। स्पीकर महोदय, आज इस सदन के अन्दर कोई तीन–चार मुख्य नेता बैठे हुए हैं जिन्होंने पिछले 34 या 35 सालों के दौरान हरियाणा का शासन संभाला। चौ. बंसी लाल जी जोकि तीन–चार बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, हमारी पार्टी के चौ. भजन लाल जी भी कई बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अब चौ. देवी लाल जी से सुपुत्र, जो कि इस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। ये खुद भी तीन–चार बार मुख्यमंत्री बने हैं हालांकि अर्सा थोड़ा–थोड़ा रहा। आज जो स्थिति है उसकी जिम्मेवारी इस सदन के सदस्यों के ऊपर और साथ–साथ इस सदन का नेतृत्व पिछले 35 सालों के अन्दर जिन्होंने किया था, उनके ऊपर भी पड़ती है। क्या इन 35 सालों से अन्दर हमने अपने शहरों में बसने वाले और देहातों के अन्दर बसने वाले लोगों का कुछ उद्धार किया है? मैं समझता हूं कि

आज के दिन इस विशय पर चर्चा होती चाएिहं 35 साल का अर्सा काफी लम्बा होता है। इसमें शक नहीं कि आज के दिन हरियाणा को अगर एग्रीकल्चर इकोनोमी कहें तो गलत बात नहीं होगी। पहले भी हरियाणा में एग्रीकल्चर इकोनोमी थी। आज भी हरियाणा एग्रीकल्चर इकोनोमी के ऊपर आधारित है। जब एग्रीकल्चर का भट्ठा बैठ गया तो साथ–साथ हरियाणा भी भट्ठा बैठ जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री चौ. ओमप्रकाश चौटाला जी की फैमिली खेती–बाड़ी कई अर्सो से करती आ रही है लेकिन आज के दिन एग्रीकल्चर की क्या स्थिति है? हालांकि एग्रीकल्चरिस्टस फैमली के नेता मुख्यमंत्री हैं फिर भी आज जमीनें धड़ाधड़ एक्वायर की जा रही है। दिल्ली की तीनों दिशाओं के अन्दर सिर्फ यू.पी. का जमुना वलाा इलाका छोड़कर बाकी सारी दिशाओं में 100–100 किलोमीटर तक जो हरे–भरे खेत हुआ करते थे वहां सीमेंट की पक्की दीवारें खड़ी हो गई हैं। वहां पर जो लोग खेती–बाड़ी किया करते थे और अपना खून–पसीना बहाया करते थे, आज उनके बच्चे उन फैक्ट्रियों के अन्दर दीवारें पर करके दाखिल नहीं हो सकते हैं। जबकि आज हम हरियाणा प्रदेश के इंडस्ट्रीयलाइजेशन की बात करते हैं। जमींदार को उसकी जमीन की कीमत देने में उसका बिल्कुल कत्ल कर दिया है। आज स्थिति यह है कि गुड़गांव रोड पर, रोहतक रोड पर और सोनीपत रोड पर जो गांव हैं आज वे गांव इस तरह से सिकुड़ कर रह गए हैं कि यदि वहां की बहन बेटियां बाथरूम जाना चाहें तो उनको जगह नहीं मिलती है। दिल्ली में वंसत गांव

है लेकिन उसके आस पास वंसत विहार शहर बन गया और अरजनी गांव के पास पंचसील बन गया आज वही स्थिति हरियाणा के दिल्ली के कंटीग्युअस एरिया के अन्दर उत्पन्न हो रही है। वहां पर बड़ी–बड़ी कालोनीज बन रही है। जो लोग आज से 15–20 साल पहले हरियाणा में नहीं थे आज उनकी कम्पनियां 3–3 और 4–4 हजार एकड़ जमीन लेकर प्लाट काट–काट कर हरियाणा के लोगों को दे रही हैं। अगर इस तरह का कोई फायदा हो तो वह हरियाणा के किसी आदमी को क्यों ने हो अगर इस बात की आपत्ति आप लोगों को नहीं है तो मैं समझता हूं कि आपका हित हरियाणा के प्रति नहीं है। स्पीकर साहब मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहूंगा कि गुडगांव जैसे शहर के अन्दर बाहर से आई कम्पनियों जैसे कहीं अनसल कम्पनी आ गई, कहीं डी.एल.एफ. आ गई। उनके पास चार–चार हजार एकड़ जमीन है वह जमीन उनके पास कैसे आई? वह जमीन उनके पास कैसे आई. यह मैं आपको बताता हूं। सरकार ने गरीब किसानों की जमीन सस्ते दामों पर एक्वायर की उसके बाद वह जमीन उन कालोनाईजरज को दे दी कि आप इसको कालोनाइज करें या और कुछ करें। उसके बाद जो जमीन किसानों से एक लाख या दो लाख रूपये प्रति एकड़ मुआवजे के हिसाब ले ली गई थी उस जमीन को आज करोड़ों रूपये के दाम पर बेच कर दिल्ली के लोग और बाहर के नान–रैजीडैंट इंडियन जो आए हैं, वे लोग वहां पर मालामाल हो रहे हैं। स्पीकर साहब, आज की हरियाणा सरकार इंडस्ट्रीयलाइजेशन के नाम पर क्रेडिट लेना चाहती है। आज

इंडस्ट्रीज लगाने के नाम पर जो जमीन एक्वायर की जा रही है मैं उसके बारे में सदन को बताना चाहता हूं। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इंडस्ट्रीयलाइजेशन करें, हमें कोई आपति नहीं है लेकिन वह ऐसे हिसाब से होनी चाहिए जो एग्रीकल्चरिस्ट रूरल इकोनमी के साथ–साथ चलती आ रही हो। आज के दिन दिल्ली के सारे के सारे पोल्यूटिड यूनिटस बंद कर दिए गए हैं, वह दिल्ली की सरकार ने बंद नहीं किए बल्कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बंद हुए हैं। दिल्ली में जितनी पोल्यूटिड इंडस्ट्रीज थी वे सारी की सारी आज के दिन हरियाणा की धरती पर आंख लगाए बैठी हुई हैं। हरियाणा सरकार ने उनको कहीं मानेसर के अन्दर, कहीं कुण्डली के अन्दर और कहीं धारूहेड़ा के अन्दर प्लाट दिए हैं। जो लोग दिल्ली से निकाले गए थे वे लोग आज हमारी धरती को पोल्यूटिड करने आ रहे हैं। हमीर सरकार क्रेडिट लेती है कि हमने इंडस्ट्रीयलाइजेशन के लिए उनको प्लाट दिए हैं। क्या दिल्ली की निस्बत यह इंडस्ट्रीयलाइजेशन हमारे सब स्वायल वाटर का प्रदूशित नहीं करेगा? मैं कहूंगा कि ऐसे आदमियों को हरियाणा प्रदेश के अन्दर कतई तौर पर प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। क्रेडिट लेने की बात तो दूसरी है। स्पीकर साहब, हमारे डिप्टी स्पीकर साहब यहां हाउस में बैठे हुए हैं गुड़गांव इनका क्षेत्र पड़ता है इनको भी पता है कि वहां के किसानों को पहले उनकी जमीनों का जो मुआवजा मिलता था वह उस समय मार्किट में जमीन का जो भाव हुआ करता था, उसके हिसाब से मिला करता

था। आज उनको वह मुआवजा भी नहीं मिलता हैं। वहां के किसान त्राही–त्राहि कर रहे हैं। अगर वे एजीटेशन करते हैं तो उन पर लाठीक चार्ज होता है। स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी यहां हाउस में बैठे हुए हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप उन किसानों के बारे में सोचें जिन किसानों ने इतने अर्से तक जमीनअपने पास रखी है तो उसको उसका एडिक्वेट कम्पनसेशन मिलना चाहिए ताकि आने वाले समय में वह कहीं जाकर जमीन तो ले लें। राज्यपाल महोदय के अभिभाशण में भी कहा गया है कि हरियाणा सरकार नई इंडस्ट्रीज लगाने के लिए इंडस्ट्रीयलिस्टस को बढ़ावा दे रही है जिनके माध्यम से हजारों जौब क्रिएट हो जाएंगे। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या वे जौब हरियाणा वासियों के लिए क्रिएट होंगे? लेकिन मैं कहूंगा कि वे जौब हरियाणा वासियों के लिए नहीं होंगे क्योंकि आज तक हरियाणा में जितनी भी इंडस्ट्रीज लगी हैं उनमें सारी कंट्रेस्ट लेबर लगती है। कोई बिहार से लेबर लाकर लगाता है और कोई यू.पी. से लाकर लगाता है लेकिन हरियाणा प्रदेश का कोई आदमी नहीं लगाया जाता है। स्पीकर साहब, राज्यपाल महोदय के अभिभाशण में कंप्यूटर टैक्नोलोजी की बात कही गई है। आज से कुछ अर्सा पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चन्द्र बाबू नायडू बने। आज का हिन्दुस्तान कहता है कि वह इन्फर्मेशन टैक्नोलोजी विजर्ड चीफ मिनिस्टर हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी उनको यहां बुला कर लाए थे। मैं इनसे पूछता हूं कि इन्फर्मेशन टैक्नोलोजी किसके पल्ले पडेगी? हरियाणा वालों के पल्ले तो पडने वाली नहीं है। चन्द्र बाबू नायडू को अगर आज

के दिन उनके प्रदेश के अन्दर इलैक्शन हो जाएं तो उनको आटे दाल के भाव मालूम हो जाएंगे। वहां के देहात के अन्दर रहने वाले जमींदार चन्द्र बाबू नायडू की इन्फर्मेशन टैक्नोलोजी को क्या समझते हैं वही पहलू आपके सामने आने वाला है। चन्द्र बाबू नायडू तो अब केवल कम्पयूटर तक ही रह गए हैं। वे देहात में नहीं जा सकते। (शोर एंव विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं तो अपने सुझाव दे रहा हूं। यह इनकी मर्जी है कि ये मेरे सुझाव मानें या न मानें। (शोर एंव विघ्न)

श्री अध्यक्षः राव साहब, आप गवर्नर एड्रैस पर बोलें। आप आन्ध्र प्रदेश में न जाएं, हरियाणा में ही रहें।

नगर एवं ग्रामीण आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह): अध्यक्ष महोदय, हमारे राव साहब काफी सीनियर मोस्ट विधायक हैं। जो आदमी सदन में मौजूर न हो और जो अपना पक्ष यहां पर नहीं रख सकता हो उसके बारे में बात करना शोभा नहीं देता। मेरा आपसे अनुरोध है कि उनके बारे में जो कहा गया है उसको कार्यवाही से निकलवा दिया जाये। (शोर एंव विघ्न)

श्री अध्यक्षः राव साहब, आपका 5 मिनट का समय रह गया है। आप अपनी बात जल्दी खत्म करें।

राव इन्द्रजीत सिंहः अध्यक्ष महोदय, अब तक तो हम बैठे बैठ ऊंघ ही रहे थे। अभी तो जागे हैं और अभी आप कह रहे हैं कि 5 मिनट में बात खत्म करें। अध्यक्ष महोदय, मैं किसानों की

बात कर रहा था। चौ. औम प्रकाश जी किसान के बेटे हैं। (शोर एंव विघ्न) यदि ये किसानों के प्रति हमदर्दी रखते तो ये उनको बिजली व पानी उपलब्ध करवाते। आज के दिन न तो किसानों को पानी मिल रहा है और न बिजली ही मिल पा रही है। जो पैदावार आज किसान पैदा कर रहा है उसका उचित मूल्य भी उसे नहीं मिल पा रहा। यदि यही हाल रहा तो फिर वह क्या पैदा करेगा?

कृशि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह संधू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राव साहब को बताना चाहूंगा कि जब इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो उस वक्त छः साढ़े छः प्रतिशत से ज्यादा धान की खरीद कभी सरकार ने नहीं की जबकि मौजूदा सरकार ने 82 प्रतिशत तक धान की खरीद की है।

राव इन्द्रजीत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गोल्ड स्मिथ के एक दोहे के माध्यम से से अपनी बात कहना चाहूंगा –

"Princess and Lords may flourish or may fade,

a breath can make them as a breath has made;

but a bold peasantry, a country's pride,

once destroyed can never be supplied."

आज हरियाणा के प्रीजैन्सरी सिस्टेमैटिकली डिस्ट्रास की जा रही है इसलिए खास तौर पर हमारी इस बारे में आपत्ति है। इस बारे में इस अभिभाशण में कोई जिक्र नहीं किया गया। हमारा

किसान आज से 10–15 साल पहले जब अपने खेत में लहलाहती फसल को देखता था वह किसी को गांठता नहीं था। उस वक्त किसान सोचा करता था कि जो फसल पैदा हो रही है उसको मैं सारा साल खाऊंगा और मेरा गुजारा आराम से हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, फसल के भाव देने के मामले में सरकार ने किसान को इतना निचोड़ दिया है कि उसका तेल निकल गया है। यदि किसान को अपने किसी काम के लिए किसी ऑफिस में जाना पड़ता है तो वह आफिसर के दफतर में जाते हुए डरता है। यह देखने वाली बात है कि क्या हम अपनी पीजैंटरी को डरपोक तो बनाने नहीं जा रहे हैं? यदि आज किसी किसान को किसी दफतर में कोई काम होता है तो वह सीधे सिकी अफसर से नहीं कह सकता है वह सोचता है कि किसी पोलीटीशियन के माध्यम से कहूंगा तब अफसर मेरी बात मानेगा। यह वास्तविकता है इसमें कोई गलत बात नहीं है। यदि ऐसा है तो हम अपने किसान को या तो बहुत डरपोक बनाना चाहते हैं या उसको गैंगस्टर बनाना चाहते हैं। इस समय चौ.बंसी लाल जी तो बैठे हुए नहीं है। लेकिन उनकी पार्टी के एक सदस्य बैठे हैं उन्होंने प्रोहीबिशन की बात कही थी में उनको बताना चाहूंगा क्योंकि मुझे यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि जब प्रदेश में प्रोहीबिशन लागू की गयी थी तो उससे एक माफिया पनपा था। जब अमरिका जैसे देश के अन्दर प्रोहीबिशन फेल हो गई तो फिर हमारे प्रदेश के अन्दर कैसे पास हो सकती थी? आज के दिन जगह–जगह डाके पड़ रहे हैं आज के दिन जो लूट–खसोट का वातावरण पैदा हो रहा है वह

शराब की तस्करी करने वालों की वजह से ही हो रहा है। (विघ्न) पीजैंटरी का ध्यान रखते हुए उनके उद्धार के लिए कम से कम कोई योजना बनाने की कृपा करें। आज डीजल का भाव बढ़ रहा हैं। सरसों का भाव उस रेशो से नहीं बढ़ा जिस रेशो से वह आज से 10 साल पहले बढ़ा करता था। आलू का क्या भाव है आप सबको यह मालूम है। आज हरियाणा और पंजाब दोनों प्रदेश मिलकर देश की 80 फीसदी ग्रेनरी की पूर्ति करते हैं। गेहूं का उत्पादन दोनों प्रदेशों का मिलाकर कुल देश का 80 फीसदी है और जहां तक जीरी की बात है अगर आन्ध्र प्रदेश को भी साथ में जोड़ लिया जाए तो तीनों प्रान्त देश के कुल उत्पादन की 80 फीसदी जीरी प्रोक्योर करते हैं। लेकिन यह सब कितने दिनों तक होगा, सवाल इस बाता का है। यह जो आज हम कह रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश के अन्दर ग्रीन रैवोल्यूशन है। ग्रीन रैवोलयूशन की वजह से हम अपने आप को मालामाल समझते हैं। कुछ किसानों की माली हालत बेहतर होगी लेकिन यह कितने दिन चलेगा और किसान को कितने दिन तक यह नसीब होगा? आज पानी नहीं लि रहा है। जो स्थिति है वह अभी मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बताई है कि अंडर ग्राउंड वाटर 99.5 प्रतिशत उपयोग में लाया जा चुका है। जहां ग्राउंड वाटर का उपयोग हो चुका है वहां ग्रे. ब्लैक तथा रैड तीन तीन रंग बताए गए हैं। मतलब यह है कि रैड रंग वह है जहां पानी खींचा जा सकता है, ग्रे रंग जो क्रिटिकल हो गया है और ब्लैक रंग का मतलब यह है जहां पानी बिल्कुल खत्म हो गया है और यह ऐरिया ब्लैक रंग के ऐरिया के अन्दर आ

गया है और आज ये बात करते हैं कि सिंचाई करवाएंगे, टेल पर पानी पहुंचाएंगे। हम कहते हैं कि आप टेल पर पानी पहुंचाएं लेकिन जिस दौरान बरसात होती है उस समय ड्रेनेज के माध्यम से वह बरसात का पानी हमारे इलाके में पहुंचना चाहिए। तीन–चार साल पहले बजट स्पीच के अन्दर चर्चा की गई थी कि ड्रेनेज के लिए कुरूक्षेत्र के लिए तो कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए अब योजना बनाई जारही है कि वहां का बरसात का पानी यमुना के अन्दर डालकर बे ऑफ बंगाल में भेज देंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप यह पानी बे ऑफ बंगाल की बजाये दक्षिणी हरियाणा में क्यों नहीं भेजते। हमारे उस क्षेत्र में बिल्कुल भी पानी नहीं है जो डैहर थे उनमें भी खेती की जा रही है। हमारे चौ. धीरपाल सिंह जी बैठे हुए हैं और वे अच्छी प्रकार से जानते हैं कि इनके झज्जर के ऐरिया में गांव–गांव में बड़े–बड़े पौण्डज हुआ करते थे, वाटर बॉडीज हुआ करती थीं, आज वे सारी की सारी वाटर बॉडीज खत्म हो गई हैं जिससे ववाटर रि–चार्जिज होना खत्म हो गया है। वाटर बाडीज नहीं रही है और वाटर रि–चार्जिज नहीं हो रही है तो खेतों के अन्दर पानी कहां से जाएगा? अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार माने तो मैं इस बारे में एक सुझाव देना चाहूंगा। जो किसान आज से 20 साल पहले वाटर बॉडीज के किनारे रहा करते थे और जो किसान उस वाटर बॉडी को ड्रेन आउट करके पानी खेतों में दे कर जीरी लगाते थे, पहले सरकार उन वाटर बाडीज को आईडैंटीफाई करे कि कौन–कौन सी वाटरबॉडीज हैं जो हरियाणा क सब सायल एरिया को रि–चार्जिग

करती थीं? फिर वहां पर किसान खेती न करें एवं उस क्षेत्र? को वह वाटर बॉडीज के रूप में इस्तेमाल करें। उस किसान को जिसकी वह जमीन है पूरा मुआवजा मिलना चाहिए जितना उस जमीन पर खेती करके वह कमाता है। यह सरकार की डयूटी है और सरकार को इस काम को करना चाहिए ताकि बाकी के किसान तो इस रि–चार्जिग के कारण कुछ फसल पैदा कर सकें। अध्यक्ष महोदय, आज राज्य में पानी की स्थिति बहुत ही खराब है। जैसे कि अभी भिवानी जिले के एक माननीय सदस्य ने बताया है कि 25 गांव ऐसे हो चुके हैं जो पानी के अभाव में गांव छोड़ कर चले जाएंगे। हम देखते रहे हैं कि गुजरात से पहले लोग आना शुरू होते थे और राजस्थान से लोग आना शुरू होते थे और सरसों में मौसम में अपनी–अपनी जगह छोड़कर पानी की तलाश में भटकते–भटकते हरियाणा के अन्दर आया करते थे। आज यह स्थिति हो गई है कि अगर दक्षिणी हरियाणा के अन्दर, भिवानी के अन्दर आज पानी नहीं मिलेगा तो भटक–भटक कर वे लोग पानी की तलाश में चण्डीगढ़ में आने लगेंगे या गंगा के किनारे जाने लगेंगे क्योंकि आज पानी की स्थिति हमारे दक्षिणी हरियाणा में ऐसी हो रही है।

श्री अध्यक्ष: राव साहब, अब आप वाईड अप करें।

राव इन्द्रजीत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई के पानी की असमानता के बारे में चर्चा करना चाहता हूं कि हरियाणा के अन्दर दो किस्म से इरीगेशन की जाती है एक इरीगेशन बिजली से

की जाती है और दूसरी कैनाल बेस्ड इरीगेशन है। वह किसान खुशनसीब किसान है जिसको 40 से 50 रूपये प्रति एकड़ के आबियाना के रूप में देने पड़ते हैं। लेकिन जिस किसान का चोआ 250 फीट से ऊपर है उसको कितना आबियाना देना पड़ेगा? अध्यक्ष महोदय, पहले जो दरे थी उनके अन्दर अन्तर था। जिसका चोआ कम गहरा था उसको ज्यादा पैसा देना पड़ता था जिसका चोआ ज्यादा गहरा था उसको कम पैसा देना पड़ता था।

वित्त मंत्री (प्रो. सम्पत सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूंगा कि अब स्लैब सिस्टम है और चार स्लैब हैं। जिसका चोआ 200 फीट से नीचे है उसका लोएस्ट रेट है।

राव इन्द्रजीत सिंह: अध्यक्ष महोदय, यहां पर एस.वाई. एल. कैनाल के पानी को लाने के बारे में भी चर्चा हुई। यह चर्चा आज से नहीं कई सालों से हो रही है। गवर्नर साहब ने अभिभाशण में कहा कि मेरी सरकार एस.वाई.एल. कैनाल और रावी–ब्यास नदियों के पानी में से हरियाणा का न्यायोचित हिस्सा प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प है। हरियाणा के हिस्से का 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलता है तो वह कहां जा रहा है और उसका बंटवारा कैसे हो रहा है? ये इस बारे में बताने का कश्ट करैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज बंसी लाल ली को कैसे हरियाणा में याद किया जाता है जब इनकी पहली बनी थी तब के कामों के लिए इनको याद किया जाता है दूसरी बार तो इनकी सरकार ज्यादा समय नहीं रही। जब इनकी

सरकार पहली बार बनी थी तो बंसी लाल जी ने बतौर मुख्यमंत्री बहुत सा पैसा एस.वाई.एल. कैनाल पर खर्च कर दिया था। इन्होंने अपने इलाके मैं कैनाल का नेटवर्क बनवा दिया उस पर कितना पैसा खर्च हुआ इस बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया, यह इसलिए किया गया ताकि उनके इलाके में एस.वाई.एल. कैनाल का पानी आए। उन्होंने ऐसे पैसा खर्च कर दिया कि पानी को लिफ्ट इरीगेशन के तहत कैनाल में डाला जाएगा। इन्होंने सारी जगह लिफ्ट इरीगेशन लगा दी। आज वहां पर क्या हो रहा है कि बिजली आती ही नहीं है अगर बिजली आती है तो पानी जैसे ही ऊपर चढ़ने लगता है तो बिजली चली जाती है और पानी फिर वापिस चला जाता है। वहां पर इतने लम्बे–लम्बे झेरे खोद दिए हैं कि पानी रास्ते में ही रहा जाता है टेल तक तो पहुंचने की बात दूर रही। इस बात के लिए बंसी लाल जी को याद किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या ये पानी का सही बंटवारा करके हमारे क्षेत्र में भी पानी देने का कश्ट करेंगे?

श्री अध्यक्ष: राव साहब, आपको बोलते हुए आधा घंटा हो गया है अब आप बैठ जाएं।

राव इन्द्रजीत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर कल की चर्चा करना चाहूंगा। हमने देखा कि मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को बुला लिया और उनको बड़े भारी आधार पर इम्प्रैस कर दिया। इनका जलसा बढ़िया हुआ यह मैं कहता हूं। जलसा बढ़िया कैसे

हुअस इसका जिक्र मैने नहीं किया था। सरकार ने इसके लिए क्या हथकंडे हाजिरी लगवाने के लिए अपनाए वह अलग बात है। मैं कह रहा था कि कल इन्होंने प्रधानमंत्री जी को इम्प्रैस कर दिया और गवर्नर साहब से भी अभिभाशण में कहलवाया कि जो सैंटर का अन–ऐलोकेटेड बिजली का पूल था उसमें से इन्होंने ज्यादा बिजली लेकर किसानों तक वितरित की। यह तो आपने अपने पांच एम.पीज. की बिनाह पर ले ली लेकिन मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि अभी जो दो या तीन दिन पहले रणजीत सागर डैम का प्रधानमंत्री द्वारा उदघाटन किया गया है क्या उसमें भी हरियाणा का बिजली का हिस्सा है? अगर नहीं है तो इस विशय पर आप क्यों चुप रहे और राज्यपाल के अभिभाशण में इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया? जब राबी ब्यास के पानी के हरियाणा का 3.5 एम.ए.एफ. का हक है तो रणजीत सागर डैम में हमारा हक क्यों नहीं होगा? आप अपना जबाव देते समय इस बात का उत्तर दें।

प्रो. सम्पत सिंहः स्पीकर सर, ये बार बार एक ही आंकड़े को रिपीट कर रहे हैं इसलिए मैं इसके बारे में इनको बताना चाहता हूं क्योंकि इससे हरियाणा के इंट्रस्ट को थोड़ी सी ठेस पहुंचती है। ये बार–बार रावी ब्यान के 3.5 एम.ए.एल. पानी का जिक्र कर रहे हैं जबकि यह 3.5 एम.ए.एफ. की जगह 3.83 एम. ए.एफ. है। इसलिए ये इसको ठीक कर लें।

राव इन्द्रजीत सिंह: ठीक है, मैं इसको अमैंड कर लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: राव साहब, अब आप वाईड अप करें।

राव इन्द्रजीत सिंह: स्पीकर साहब, मैं तो सरकार की तारीफ ही कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार ने रोडज बनायीं। बहुत दिनों से रूरल रोडज नहीं थीं। यह ठीक है कि इन्होंने उनको बनाया है। यह इन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन मैं सरकार से एक बात कहना चाहता हूं कि जो सैनिक शहीद हुए थे उनके लिए सरकार ने ऐलान किया था कि दस लाख रूपये हम अपनी सरकार की तरफ से देंगे। हमने इसके लिए भी इनकी सराहना की थी। लेकिन ग्राउंड रिएलटीज यह हैं कि कुछ शहीदों के परिवार वालों को इनके अनाउंस करने के बाद भी पैसा नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष: आप इस तरह से नाम बता दें।

राव इन्द्रजीत सिंह: इस तरह से दो गांव हैं एक तो गोठड़ा है और दूसरा मंदोला है जिनका मुझे पता है हो सकता है और ही ऐसे कई गांव हों। ये गांव खोड़ और जाटूसाना ब्लॉक में हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं अपने जवाब मैं ही सारी बातें कहूंगा। लेकिन मैं इनको बताना चाहूंगा कि ये फौजी के बेटे हैं इसलिए इनको पता होना चाहिए।

डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जिसे शहीद घोशित किया जाता है उसको हमारी सरकार द्वारा निर्धारित दस लाख रूपये दिये जाते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री वाले ही हमें बताते हैं। यह काम उनका है हमारा नहीं है। अगर कहीं से चूक हुई होगी तो वह उनकी तरफ से हुई होगी या हो सकता है कि उनके हिसाब से वह ठीक न हो। आज भी सरकार की तरफ से डिफेंस मिनिस्ट्री का वह पैसा सोल्जर बोर्ड के द्वारा दिया जाता है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है।

राव इन्द्रजीत सिंह: अगर ऐसा है कि ओवर लुक हो गया तब भी आप इसको चैक करवा लें और बता दें। अध्यक्ष महोदय, एक और बात मैं कहना चाहूंगा। जैसे गवर्नर साहब ने भी अपने अभिभाशण में जहां यह जिक्र किया कि रावी ब्यास का पानी नहीं आया है वहीं साथ–साथ उन्होंने यह भी कह है कि पंजाब और चंडीगढ़ के अन्दर जो हिन्दी स्पीकिंग एरियाज हैं उनको हम लेना चाहते हैं। क्या चंडीगढ़ के हिन्दी स्पीकिंग एरियाज की बात करके ये चंडीगढ़ पर क्लेम अबैंडेन्ट तो नहीं कर रहे हैं? चंडीगढ़ के हिन्दी स्पीकिंग एरियाज लेने का क्या मतलब है चण्डीगढ़ को तो पूरे लेना चाहिए। (विघ्न) इन्होंने तो दस्तखत करवाये थे, फैसला तीनों चीफ मिनिस्टरों का हुआ था यह इंदिरा गांधी के टाईम की बात है वैसे तो आप कुछ भी कह दें लेकिन वास्तविकता जो है वह यह है।

चौ. भजन लाल: ऑन ए प्वाइंट आफ आर्डर स्पीकर सर, पहले भी कई बार और आज सुबह ही चौटाला साहब ने कहा कि भजन लाल चपरासी की तरह बाहर बैठा रहा। मैं इनको कहना चाहता हूं कि कम से कम आदमी को उसकी जैसी शक्ल हो, वैसी बात नहीं करनी चाहिए, बात ठीक करनी चाहिए, यह विधान सभा है, आप चीफ मिनिस्टर हैं मैं भी आपको कुछ कह दूं तो क्या आपको अच्छा लगेगा?

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, एक अच्छी शक्ल वाले आदमी ने हरियाणा की सूरत बिगाड़ने का प्रयास किया जिसका अब परिणाम ये भुगत रहे हैं। राजीव–लौंगोवाल समझौते में आपने प्रदेश की हेठी करवाई, आप चपरासी की तरह बाहर बैठे थे। (विघ्न) आपने हरियाणा प्रदेश की शक्ल बिगाड़ने का काम किया। (शोर एवं विघ्न)

चौ. भजन लाल: यह चंडीगढ़ पंजाब को जाने की बात तय हो गई थी, लाइटें भी लगा दी गई थीं, मैंने यह रूकवाया था।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: यह तो हमने रूकवाया था, आपने तो चंडीगढ़ बेच दिया था। हम आंदोलन करके आये थे यहां तो रात में झंडे फहराने की बात हो रही थी। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्षः राव साहब, अब आप अपनी बात समाप्त करें।

राव इन्द्रजीत सिंहः अध्यक्ष महोदय, अगर ये दोनों बीच में न इंट्रस्ट करते तो मैं अपनी बात समाप्त कर चुका होता। मुझे दो मिनट का समय और दिया जाए। दो मिनट में मैं अपनी बात कह दूंगा। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार ने म्यूनिसिपल कमेटीज खासकर सी ग्रेड की म्यूनिसिपल कमेटीज को तोड़ दिया और वजह क्या बताई गई कि इनके पास इतना बजट नहीं है। जिन म्यूनिसिपल कमेटीज को तोड़ा गया है उनमें से कई घाटे में भी थी ऐसी ही एक कनीना की म्यूनिसिपल कमेटी थी। वहां की कमेटी वाले हाईकोर्ट में गए। हाईकोर्ट ने आदेश किए कि कनीना की कमेटी मुनाफे में थी इसलिए उसको रद्द नहीं करना चाहिए था। हाईकोर्ट का आदेश आ गया, 6 महीने गुजर गए लेकिन उस म्यूनिसिपलिटी को दोबारा से बहाल नहीं किया गया। उनका क्या हाल होगा, इस तरह की स्थिति है।

श्री अध्यक्षः आपका समय समाप्त होता है। आप बैठ जाइए।

राव इन्द्रजीत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए अपना स्थान लेता हूं। धन्यवाद।

डा. जयप्रकाश शर्मा (यमुनानगर): अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने के लिए आपने आफटर इवनिंग टाईम दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपोजीशन बैंचेज पर बैठे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं? लेकिन फिर भी मैंने पानी पीकर अपनी आंखे खोल रखी हैं ताकि मैं अपनी बात ठीक से कह सकूं व आप मेरी बात सुनें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि हर सैशन में मैंने इनके सामने एक सवाल रखा है – थर्मल पावर प्लांट जोकि यमुनागनर का है जिसके लिए हजारों एकड़ जमीन ऐक्वायर की गई। 1991 में उसका नींव पत्थर रखा गया था। पी. वी. नरसिम्हाराव जी प्राइम मिनिस्टर थे और चौ. भजन लाल जी चीफ मिनिस्टर थे लेकिन उनके बाद चौ. बंसी लाल जी आये उन्होंने भी उस पर कुछ काम नहीं किया। मैं आपके माध्यम से नोटिस में लाना चाहता हूं कि सरकारें बदलती हैं, आती हैं और जाती हैं लेकिन जो प्रोजैक्ट हैं चाहे बिजली के प्रोजैक्ट हैं या और कोई हैं, अच्छे प्रोजैक्टों की फाईल आपको खुड्डे लाईन नहीं लगानी चाहिये। वर्ल्ड बैंक भी उस प्लांट के लिए लोन देने के लिए मुकर गया है ऐसा मेरा ख्याल है। इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिये। गवर्नर साहब के अभिभाशण मैं आपने बड़े सुन्दर लफ्जों में गवर्नर साहब से कहलवाया है लेकिन ग्लोबल प्रोमोशन के हिसाब से देखा जाये तो एनवायरनमेंटल पोल्यूशन के बारे में कहीं भी चर्चा नहीं की गई है। आज की डेट में पोल्यूशन एक ऐसी चीज है जिससे इंसान का बचना जरूरी है पोल्यूशन ही वजह स ब्रोन–काईटिस तथा स्किन डिजीज जैसी कई बीमारियां

पैदा हो जाती हैं। दूसरी बात आपने गवर्नर महोदय के अभिभाशण में कही कि दिल्ली की फैक्ट्रियां कुण्डली के बोर्डर के आसपास शिफ्ट करने जा रहे हैं। आप यह अंदाजा लगायें कि जिन फैक्ट्रियों को पोल्यूशन की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली से बाहर शिफ्ट करने के आदेश दिये हैं आप उन्हीं फैक्टरियों को यहां क्यों लगाने जा रहे हैं? तीसरी बात यह है जिन हरियाणा रोडवेज की बसों को दिल्ली में चलाने के लिए मना किया हुआ है आप उन्हीं बसों को हरियाणा के ग्राणीम इलाकों में चला रहे हैं क्योंकि दिल्ली में तो वे बसें जो 15 साल पुरानी हैं जा नहीं सकती इसलिए आपको उन बसों को डिसकार्ड करना चाहिये। इसी में हमारी भलाई है। पोल्यूशन से बचाने की जिम्मेवारी सरकार की बनती है।

जहां तक लॉ एंड आर्डर की बात है। मेरे सभी साथियों ने जिक्र किया कि हरियाणा में लॉ एंड आर्डर की स्थिति खराब है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से टैलीफोन पर आग्रह किया था कि यमुनानगर इतना साफ सुथरा शहर था यहां पर कभी चोरी डैकेती नहीं पड़ती थी परन्तु आजकल यहां पर चोरी और डैकेती की वारदातें बढ़ रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने टैलीफोन पर कहा था कि चोरी डैकेती कभी खत्म थोड़े ही होती हैं। वे लोग तो अपनी मर्जी से आते हैं और चोरी डैकेती करके चले जाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी जब आप यमुनानगर में आये तो आपने पुलिस वालों को कसा नहीं बल्कि उनको अच्छे काम के लिए

सर्टिफिकेटस देकर आये। जहां तक चालान करने की बात है आजकल जो सड़कों पर चालान हो रहे हैं पुलिस वाले डंडा पकड़े बैठे रहते हैं चालान जब होता है तो वे किसी की बात नहीं सुनते, आर.सी. ले लेते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि ऐसा कुछ सिस्टम किया जाये कि दिल्ली की तरफ चालान मौके पर ही चुकाया जा सके क्योंकि चालान को भुगतने के लिए कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, वकील करने पड़ते हैं। सैंकड़ों चालान रोजाना होते हैं परन्तु कचहरी में मुश्किल से दस चालान भुगताये जाते हैं। जहां तक हैल्थ के बारे में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा। उन्होंने पापुलेशन पर तो काफी दबाव दिया। हैल्थ के बारे में मैंने अपना एक क्वैश्चन दिया था लेकिन उसके बारे में कोई प्रश्न आज तक नहीं लगा। हरियाणा प्रदेश की पापुलेशन दो करोड़ है और हैल्थ मिनिस्टर महोदय ने मैडिसन के लिए 3 करोड़ 92 लाख 75 हजार रूपये का प्रावधान किया है जिससे एक मरीज के लिए डेढ़ रूपया हिस्सा आता है उसमें दवाईयां, पट्टियां, भोजन आदि शामिल हैं।

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डा. एम.एल. रंगा): अध्यक्ष महोदय, 371 करोड़ रूपया जो हमने स्वास्थ्य विभाग के लिए बजट में दिया है अब माननीय सदस्य खुद हिसाब लगाकर देख लें कि एक आदमी के हिस्से डेढ़ रूपया आता है या 150 रूपये आते हैं या 200 रूपये आते हैं। मेरे हिसाब से लगभग 188 रूपये एक आदमी के हिस्से आते हैं।

डा. जय प्रकाश शर्मा: 150 रूपय कैसे हो सकते हैं? आपको अब तक केवल 30–35 करोड़ रूपये मिले हैं। आप चार करोड़ भी मान लें तो भी कुछ ज्यादा नहीं है हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा स्टेट है और वे 15 करोड़ रूपया दवाईयों पर खर्च करते हैं।

श्री मांगे राम गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मंत्री जी फिगर्ज और डा. जय प्रकाश जी द्वारा बताई फिगर्ज में बहुत बड़ा फर्क है। मंत्री जी 371 करोड़ रूपये बता रहे हैं और शर्मा जी 3.92 करोड़ रूपये बता रहे हैं इसलिए इसको क्लैरीफाई करवाया जाए।

श्री अध्यक्ष: गुप्ता जी, आप बैठिए आपको तो जवाब नहीं देना है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: गुप्ता जी, जब आप फाइनैंस मिनिस्टर हुआ करते थे तब आप कहा करते थे कि इसको पढ़ा मान लिया जाए। आपकी पार्टी का एक सदस्य बोल रहा है, उसका जवाब आप दे रहे हो, आपको इनको डिस्ट्रब नहीं करना चाहिए। जब बजट प्रस्तुत होगा, आप तब बोल लेना और देख लेना कि किस मद के लिए कितना पैसा रखा गया है। आज बजट पर बात नहीं हो रही है बल्कि गवर्नर एड्रैस पर बात हो रही है। (शोर एवं व्यवधान)

डा. जय प्रकाश शर्मा: अध्यक्ष महोदय, सोमवार को प्रो. सम्पत सिंह जी ने बजट पढ़ना है इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोगों के हैल्थ की तरफ ध्यान रखा जाना चाहिए क्योंकि लोगों की हैल्थ जरूरी है, मजदूर की हैल्थ जरूरी है। यमुनानगर के अस्पताल को 200 बैड का अप–ग्रेड करने की पिछली सरकार ने फैसला लिया था लेकिन अब वह फाईल कहां है, कुछ पता नहीं है कि यह अस्पताल बनेगा या नहीं? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हरियाणा में स्पैशलिस्ट डॉक्टर्ज को जनरल डयूंटीज दी गई हैं जैसे आईज स्पैशलिस्ट को डिस्पैंसरीज में लगा दिया जाता है। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि डॉक्टर्ज के साथ ऐसा अनर्थ न किया जाए। अगर सरकार ऐसा करेगी तो पब्लिक को सही सर्विसज नहीं मिल सकेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि ये रोहतक में गए थे और डॉक्टर्ज के एन.पी.ए. बढ़ाने के लिए कहा था लेकिन डाक्टर्ज के लिए एन.पी.ए. बढ़ाने के लिए आज तक ध्यान नहीं दिया गया जबकि हमारे पड़ौसी राज्य पंजाब और हरियाणा में डॉक्टर्ज की तन्खाह में 7000 रू. का फर्क है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि कया इन्होंने हैल्थ सैन्टर्ज और अस्पतालों का बाहर से या अन्दर से विजिट किया है? इन्होंने अगर बाहर स विजिट किया होगा तो जगह–जगह कूड़े करकट के ढेर लगे जरूर देखें होंगे। ये यमुनानगर में चलें तो मैं इनको वहां के अस्पतालों की हालत दिखा दूंगा। वहां ई.एस.आई. में दवाईयां नहीं हैं, मेरे सभी

साथियों ने कहा है कि अस्पतालों में इवाईयां नहीं मिल रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी ने नोटिस में लाना चाहूंगा कि यमुनानगर में ई.एस.आई. की बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी है लेकिन वहां डाक्टर्ज और दवाईयों की कमी है। इसके अलावा जो मजदूरों के रिम्बर्समैंट बिज होते हैं, वह बिल 5–5 हफ्ते तक क्लीयर नहीं होते तब तक सीरियस पेशन्ट ऊपर चले जाते हैं। पी.जी.आई. में जो इलाज होता है उसके लिए वे पहले कैश मांगते हैं। मैंने भी पी.जी.आई. में एक टैस्ट कराया था। मुख्यमंत्री महोदय गवाह है कि उन्होंने कहा कि पहले पैसा जमा करवाओ। पहले ई.एस.आई. ड्राफ्ट जमा करवा देती थी लेकिन अब ड्राफ्ट जमा नहीं होता इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगी कि इसके लिए भी कोई प्रावधान किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार को बने एक साल 7 महीने का समय हो गया है और यह सरकार नये सिरे से हाउस टैक्स प्रणाली लागू करने वाली है। इन्होंने फील्ड में सर्कूलर तो भेज दिउ है लेकिन अभी वे लागू नहीं हुए हैं। इस बारे में मैं सरकार को कहना चाहूंगा कि जो हाउस टैक्स लगाया जाये वह प्लाट की कीमत और प्लाट के उपर जो मकान बना हो उसकी कीमत को कैल्कूलेट करके नहीं लगाया जाये। इसके अतिरिक्त 10 प्रतिशत जो फायर स्टेशन टैक्स लगाया जा रहा है वह हर जगह पर नहीं लगाना चाहिए। जिस जगह फायर स्टेशन या फायर इंजन

ही नहीं है वहां पर यह 10 प्रतिशत टैक्स नहीं लगाना चाहिये जब वहां पर फायर स्टेशन बन जाये उस समय यह टैक्स लगाया जाए। जिस समय हाउस टैक्स का सर्कूलर यमुनानगर भेजा गया उस समय मैं भी वहां मीटिंग में था। वहां पर सभी की सर्वसम्मति से म्यूनिसिपल कमिशनर ने यह रैजोल्युशन पास करके भेज दिया था कि नई कर प्रणाली लागू न की जाये लेकिन फिर भी आप वहां पर यह प्रणाली लागू कर रहे हैं। म्यूनिसिपल कमेटी सिटीजन को कोई भी सुविधा नहीं देती। आज के दिन हर शहर से सफाई नहीं होती। यह बात जरूर है कि कुछ सफाई कर्मचारियौं की कमी जरूर है। दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है और जो सफाई कर्मचारी रिटायर हो गये हैं उनकी जगह नये सफाई कर्मचारी भर्ती नहीं किये गये हैं। इस बारे में मेरा मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि उस तरफ भी ध्यान दें। इसके अतिरिक्त मौजूदा सरकार ने एक नई वाटर सप्लाई स्कीम शुरू की हैं। जिसके तहत गरीब इलाकों में टयूबवैल लगाने के लिए 90 प्रतिशत पैसा सरकार देगी और 10 प्रतिशत पैसा लोग इक्टठा करके देंगे और जमीन भी पंचायत द्वारा दी जायेगी। इस बारे में मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि जमीन वाली बात तो ठीक है लेकिन जो 10 प्रतिशत का हिस्सा गरी जनता को देना पड़ेगा यह गलत है क्योंकि गरीब जनता कहां से पैसा देगी? इस ओर भी मुख्यमंत्री महोदय ध्यान दें। अध्यक्ष महोदय, मेरे सारे सुझाव सही हैं गलत नहीं हैं। इसके अतिरिक्त इस सरकार ने बिजली बोर्ड से बिजली के बिल की एन.ओ.सी. लेना जरूरी कर दिया है चाहे आप मोटर

साइकिल की रजिस्ट्रेशन करवायें या मकान प्लाट की रजिस्ट्री करवाएं। जब भी कोई आम आदमी बिजली वालों से एन.ओ.सी. लेनै के लिए जाता है तो वे लोग 50–60 रूपये लिये बगैर एन.ओ. सी. हनीं देते ओर कंज्यमर को कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। इससे भ्रश्टाचार बहुत ज्यादा फैल रहा है इसे बंद करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सराकर ने प्राईमरी शिक्षा और लड़कियों के लिए बी.ए. तक की शिक्षा मुफ्त कर रखी है यह बहुत की अच्छी बात है लेकिन मुख्यमंत्री महोदय गांवों में जाकर देखें। वहां पर स्कूलों की बहुत बुरी हालत है। गांवों के स्कूलों में लैबोरेट्री और लाईब्रेरी तो नाम मात्र की ही होती हैं उस ओर भी मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। इसी कारण से गांव के बच्चों का शिक्षा का लैवल नीचा है और वे शहर के बच्चों के साथ कंपीटीशन नहीं कर पाते। मौजूदा सरकार अध्यापकों की भर्ती कर रही है लेकिन गांवों के अंदर फिर भी अध्यापकों की बहुत कमी है। इस तरह भी सरकार ध्यान दे। यमुनानगर में एक शूगर मिल है इस बारे में मुख्यमंत्री महोदय भी जानते हैं। उन्होंने वायदा किया था कि वे हर साल 4–5 प्रतिशत गन्ने का मूल्य बढ़ायेंगे लेकिन इस साल नहीं बढ़ाया, इस ओर भी सरकार ध्यान दे। पिछली दफा किसानों को गन्ने की पेमैंट लेट मिली। वह पेमैंट तो मिल गई लेकिन 7–8 महीन का ब्याज किसानों को नहीं मिला, वह भी किसानों को दिया जाये। आजकल शूगर केन का सीजन चल रहा है इस कारण यमुनानगर में दो–दो, तीन–तीन घंटे तक ट्रैफिक का जाम लगा रहता है। वहां पर कोई फलाई ओवर बनाने की योजना बनाई

जाये ताकि जनता को असुविधा न हो। अध्यक्ष महोदय, वृद्धावस्था पैंशन के बारे में और बी.पी.एल. के पीले कार्डों का सभी साथियों ने जिक्र किया। इसी तरह से विधवाओं को पैंशन दिये जाने की बात है इन सबके लिये दोबारा से सर्वे होना चाहिए क्योंकि पैंशन भी सही आदमियों तक न पहुंच कर गलत आदमियों के पास जा रही है। जुलाई में मैंने मुख्यमंत्री चौ. ओम प्रकाश चौटाला जी से बात की थी कि गरीब मजदूरों के बारह मकान टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमैंट ने गिरा दिये। इन मजदूरों ने जैसे तैसे पैसा इकट्ठा करके एक–एक कमरे का मकान बनाया था। मंत्री महोदय श्री भडाना भी वहां गये थे और उन्होंने विश्वास दिलाया कि इन मजदूरों को मुआवजा दिया जाएगा। इनको आज तक मुआवजा नहीं मिला जब मैं खुद डायरैक्ट, टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग से मिला तो उन्होंने कहां कि हमारे पास इस तरह के मुआवजे का कोई इंतजाम नहीं है। डी.सी. ने भी जवाब दे दिया कि उसके पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मैंने एक जे.ई. की कम्पलेंट भी की थी जिसने इन मजदूरों से पैसा मांगा था। अच्छी–अच्छी बिल्डिंगों को तो टच भी नहीं किया गया जबकि इन गरीब आदमियों के मकान गिरा दिये गये। इसलिये मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इन 12 मजदूरों को मुआवजा जरूर दिया जाए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, ये लिखित में कम्पलेंट दे दें, हम उसकी इन्कवायरी करायेंगे।

डा. जय प्रकाश शर्मा: अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से सड़कों की बात आती है। कई जगह सीमेंट के रोड बना दिये गये। यह बड़ी अच्छी बात है लेकिन उनकी साइड़ो में मिट्टी इतनी गहरी है कि अगर एक वाहन क्रोस करे तो पहले वाले को साइड में रूकना पड़ेगा। इस सम्बन्ध में जब विभाग से बात की गई तो बताया गया कि सड़कें बनाने का प्रोविजन तो है लेकिन मिट्टी डालने का प्रोविजन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक लोकल बोडीज की बात है तो तहबाजारी रेट एक रूपये से 10 रूपये कर दिये गये जोकि गरीब आदमियों के लिये, रेहड़ी वालों के लिये बड़ी भारी ज्यादती है वहां पर रेहड़ी वालो को खड़ा नहीं होने देते। सब्जी की मंडियां तो लग जाएंगी, यह ठीक है लेकिन आपको याद होगा कि यैलो लाईन होती थी जिसके अन्दर ये रहेड़ी वाले खड़े होते थे। अब भी वे लोग मानते हैं कि उन्हें यैलो लाईन के अन्दर खड़ा होने का अधिकार है लेकिन लोकल बोडिज वाले इन सब्जी और फ्रूट वालो का सामान नीचे गिरा कर इनके पैसे छीन ले जाते हैं। इसकी भी इन्कवायरी होनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, आखिर में, मैं ऑगुमैंटेशन कैनाल की बात कहना चाहूंगा जो कि यमुना नगर से निकल कर नरवाला को जाती है। पानी भी यमुना नगर का और बर्बादी भी यमुना नगर की होती है। जो टयूबवैल साइड में लगे थे यह पानी लिफ्ट करके नहर में डालते थे लेकिन जो मोटरें खराब हो गई उनको ठीक नहीं किया जाता है। उसका रिजल्ट यह हुआ कि जो फसलें बीज ली जाती हैं वह कटती नहीं जिससे कि जमींदारों को बड़ी दिक्कत होती है।

इसलिये मेरा आपने माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस बात पर भी ध्यान दिया जाए ताकि गरीब किसानों का नुक्सान न हो। मुख्यमंत्री जी, आप तो अपने आपको गरीब किसानों के नेता समझते हैं लेकिन आज के दिन किसान दु:खी है, हर बन्दा दु:खी है (शोर)

एक आवाज: डाक्टर तो सुखी हैं (शोर)

डा. जय प्रकाश शर्मा: हां, डाक्टर तो सुखी हैं (शोर)

श्री भागी राम: आपको अपनी फीस से मतलब है, मरीज भले ही मर जाए। (शोर)

डा. जय प्रकाश शर्मा: अध्यक्ष महोदय, भागी राम जी का शायद डाक्टर से ठीक तरह पाला पड़ा नहीं। (शोर) अध्यक्ष महोदय, अगर इन्होंने कभी प्रीसक्रीप्शन देखा हो तो इनको पता चलेगा कि उसमें आर एक्स लिखा होता है। (शोर)

आर एक्स फ्रैन्च का शब्द है जिसका अर्थ है

"I pray to the almighty God that my patient should be alright with the prescription I am writing."

हम ठीक नहीं करते। ठीक तो भगवान की कृपा से होते हैं हम तो उनका नाम लेकर इलाज करते हैं। अन्त में मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे आराम से सुन लिया। धन्यवाद।

श्री शादी लाल बत्तरा (रोहतक): अध्यक्ष महोदय, हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय जब पांच मार्च को अपना अभिभाशण पढ़ कर सुना रहे थे तो उसमें जो घोशणाएं थीं उनके बारे में ऐसा लग रहा था कि अगर उन घोशणाओं में आधी घोशणाएं पूरी हो जाएं तो हमारा हरियाणा प्रदेश स्वर्ग बन जाएगा, हरियाणा देश में पहला प्रदेश होगा और हम शान से कह सकेंगे कि हम हरियाणावासी हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाशण को गौर से देखा तो नजर आया कि उन्होंने जो भी घोशणाएं की थीं उनका कोई आधार नहीं था। अध्यक्ष महोदय, अगर मैंने कल कोई घोशणा करनी है तो बीते हुए कल की घोशणा का अनुभव लूंगा लेकिन हम बीते हुए कल कोई घोशणा करनी है तो बीते हुए कल की घोशणा का अनुभव लूंगा लेकिन हम बीते हुए कल के अनुभव पर चलते हैं तो देखते है कि राज्यपाल महोदय द्वारा की गई घोशणाएं खोखली हैं। अध्यक्ष महोदय, आप शिक्षा की बात को ले लीजिए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में पहली कक्षा से अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी और प्राईमरी स्कूलों से कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी, यह इनकी बड़ी अच्छी बात है मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन देखना यह है कि यह शिक्षा नीति उच्च शिक्षा से मेल खाती है या नहीं। अध्यक्ष महोदय, आजकल उच्च शिक्षा में क्या हो रहा है वह मैं आपको बताता हूं। अमीर आदमी का बेटा गुणों के आधार पर उच्च शिक्षा के लिए एडमिशन भी ले लेता है और डिग्री भी ले लेता है लेकिन गरीब आदमी का बेटा गुणों के आधार पर उच्च शिक्षा के लिए

एडमिशन नहीं ले सकता क्योंकि यूनिवसर्सिटीज में सीटें पेड हो गई हैं जिसके कारण गरीब बच्चों के लिए शिक्षा के रास्ते बन्द हो गए हैं। गुणों के आधार पर एडमिशन नहीं मिलने से गरीब बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज एक तरफ काजेजिज में और यूनिवर्सिटीज में विधार्थियों की संख्या बढ़ रही है। चाहिए तो यह था कि अगर विधार्थियों की संख्या बढ़ रही है तो उसके साथ नई पोस्टें सैंक्शन हों ओर उनकी भर्ती की जाए अगर नई पोस्टों की सैक्शन न हो तो कालेजिज और यूनिवर्सिटी में जो आलरेडी पोस्टें चल रही थीं, अगर उन पर रोक लग गई तो उन विद्याथियों का क्या होगा जिनको न अच्छे अध्यापक मिले और न अच्छी शिक्षा मिली? जो वहां से डिग्री लेकर आएगा वह केवल व्हाईट कालर जौब के लिए काफी होगा लेकिन व्हाईट कालर जौब उसको नहीं मिलेगी तो फिर वह अपराधीकरण की तरफ जाएगा। स्पीकर साहब, मेरा आपके माध्यम से इस सरकार से कहना है कि सरकार ने जो शिक्षा प्रणाली बनाई है वह ठीक नहीं है। यह बात तो ठीक है कि गांवों के बच्चों को इंगलिश में शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर बच्चे माडल स्कूलों में या पब्लिक स्कूलों में इंगलिश पढ़ कर आते हैं तो उनकी आगे चल कर कामयाब रोने की ज्यादा सम्भावराएं होती हैं। यह बात भी ठीक है कि गांवों के गरीब बच्चों को यह अवसर मिलना चाहिए लेकिन इसके साथ साथ उच्च शिक्षा का मुकाबला करके उच्च शिक्षा में भी सुधार करना चाहिए। उच्च शिक्षा में बच्चों का एडमिशन गुणों के आधार पर हो और सरकार ने जो यह आदेश

दिया है कि यूनिवर्सिटीज अपने फंड खुद क्रिएट करे उनकी यह फंड प्रणाली दूर की जाए और उनको गांट दी जाए। अगर हम पिछले तीन चार सालों का मुकाबला करें तो यूनिवर्सिटीज को हर साल में कम ग्रांट दी जा रही है और उसका सीधा प्रभाव शिक्षा पर पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप उच्च शिक्षा की तरफ भी ध्यान दें और यूनिवर्सिटीज की ग्रांट पर जो कट लगा रहें है वह न लगाएं। जो नए अध्यापाकों की अप्वायंटमैंअ पर रोक लगाई गई है उस रोक को दूर करें। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अध्यापकों की जो भी पोस्ट सैंक्शन होनी हैं उनको सैक्शन किया जाए। अध्यक्ष महोदय, दिन प्रतिदिन विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है। देखना यह होगा कि उसका क्या कारण है। उसका कारण एक ही है कि हमारी आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। आज सुबह प्रश्नकाल के दौरान इस बारे में एक प्रश्न था। उसका जवाब देते हुए हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि हम आबादी बढ़ने पर रोक लगा रहें हैं और हमने उसके लिए ये ये कदम उठाए हैं। मैं कहूंगा कि इन्होंने आबादी को बढ़ने से रोकने के लिए जो कदम उठाए हैं वे काफी नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप यह आहवान करें कि 'एक परिवार एक संतान'। अगर हम यह आह्वान करते हैं तो मैं समझता हूं कि हरियाणा प्रदेश देश का प्रथम प्रदेश होगा जो इस प्रणाली को आगे लेकर चलेगा। अगर यह आह्वान पूरा हो गया तो जो आबादी बढ़ रही है उसका न केवल हम अपने प्रदेश

में कंट्रोल करेंगे बल्कि उसका असर सारे देश पर पड़ेगा। इसके कई गुण हैं। जब हम यह कहेंगे कि 'एक परिवार एक संतान' तो उसमें यह बात आएगी कि लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है। जब किसी को किसी तरीके से पता लग जाता है कि उसकी औरत के गर्भ में लड़की है तो वह उसका अबोर्शन करवा देता है। अगर कोई यह चाहता है कि उसके लड़की न हो लड़का ही हो इस चाह में उनके ज्यादा संतान हो जाती हैं। अगर आपने यह रोक लगा दी कि लड़का ही हो इस चाह में उसके ज्यादा संतान हो जाती है। अगर आपने यह रोक लगा दी कि लड़का लड़की में कोई फक नहीं है तो यह होगा कि लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है। अगर एक बच्चा चाहे वह कोई सा भी हो, उसको सरकार अपनी तरफ से शिक्षा भी दे सकेगी और जब वह 18 या 20 साल का हो जाएगा तो उसको रोजगार मिलने में भी आसानी होगी। अगर उसको रोजगार नहीं मिलेगा तो सरकार उसको बेरोजगारी भत्ता भी अदा कर सकेगी।

17.00 बजे

अगर हम यह कर सकते हैं तो यह आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा होगा और हम सब आपके अनुग्रहित होंगे।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं स्वास्थ्य के बारे में बात कहना चाहूंगा। हरियाणा प्रदेश के अन्दर केवल एक मैडिकल कालेज रोहतक में है, यह मैडिकल कालेज 1962 में बना था। उसके बाद

से लेकर आज तक इस कालेज में बहुत मामूली एक्सटेंशन हुई है। जितने डाक्टर्ज वहां पर उस वक्त लगे थे उतने ही आज के दिन हैं यानि नई पोस्टें सैक्शन नहीं हुई। नई पोस्टें तो सैंक्शन होना दूर की बात है जो पोस्टें सैंक्शन हैं वह भी पूरी भरी हुई नहीं हैं, लोग प्राईवेट डाक्टर से इलाज करवाना पसंद करते हैं। मैडिकल कालेज का इलाज महंगा हो गया है, वहां पर केवल अमीर लोग ही अपना इलाज करवा पा रहे हैं। अब यह कालेज आम आदमी के लिए न रहकर केवल अमीरों के लिए बन कर रह गया है। मेरी सरकार से मांग है कि वहां पर पोस्टें और सैक्शन की जायें और उसकी एक्सटैंशन समय के अनुसार की जाये। इसके अलालवा जो पोस्टें वहां पर खाली पड़ी हुई हैं उनको जल्दी से जल्दी भरा जाये ताकि मरीज परेशान न हों इसके अलावा इस कालेज की ग्रान्ट को भी बढ़ाया जाये ताकि आम आदमी को फायदा हो सके। मुख्यमंत्री जी ने घोशणा की थी कि करनाल में एक ट्रोमा सेन्टर बनाया जायेगा। अच्छी बात है, यह ट्रोमा सेन्टर अवश्य खोला जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि रोहतक में भी ऐसे एक ट्रोमा सेन्टर पर साढ़े तीन करोड़ रूपये खर्च हो चुके हैं। अब वहां पर बहुत थोड़ा पैसा खर्च करके इसको चालू किया जा सकता है। इसके चालू होने पर रोहतक के आसपाल जितने भी जिले लगते हैं उन सबको इसका फायदा पहुंचेगा। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं रोहतक मेडिकल कालेज के पिछले 6 महीने के आंकड़े देना चाहूंगा। वहां पर इन पिछले 6 महीनों में 12 हजार मरीज दाखिल हुए और इन 12 हजार मरीजों

में से 400 मरीजों की मृत्यु हो गई। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि इस ट्रोमा सेन्अर के चालू होने से वहां पर आने वाले मरीजों को इसका फायदा पहुंचेगा।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने ग्राम विकास के लिए और शहर के विकास के लिए जो नीति बनाई है वह अधूरी है। आज रोहतक में 100 कालोनीज के करीब अनअथोराईज्ड डिक्लेयर की हुई हैं। जब वे लोग कमेटी को टैक्स दे रहे हैं, कमेटी की तरफ से उनको पानी व बिजली दी जा रही है तो फिर वे अनअथोराईज्ड कैसे रह गई? जब इन कालोनीज में रहने वाले लोग अपने मकान में एक्सटैंशन के लिए कमेटी के पास जाते हैं तो उनसे एडीशनल चार्ज देने के लिए कहा जाता है। मेरी सरकार से मांग है कि इन कालोनीज को जिनमें सरकार की तरफ से सुविधायें दी जा रही हैं उनको अथोराईज्ड डिक्लेयर किया जाये। इसी संबंध में मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि अनअथोराईज्ड कालोनीज को रोकने के लिए मौजूदा नियम सरकार ने बना रखे हैं वे काफी नहीं है यानि मौजूदा नियमों के तहत ऐसी अनअथोराईज्ड कालोनीज को बनाये जाने से रोका जाना संभव नहीं होगा। आज के दिन बहुत से प्रोपर्टी डीलर्ज किसानाकं की कम भाव पर जमीन लेकर ऊंचे दामों पर कालोनीज काटे जा रहे हैं। जब कहीं पर कोई ऐसा केस दर्ज होता है तो उन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। जो दूसरे लोग हैं वे ही इनमें फंसते हैं यानि प्रोपर्टी डीलर्ज का कहीं पर कोई

नाम नहीं होता। वो किसान जिसकी जमीन ली जाती है इसका नाम होता है प्लॉट की रजिस्ट्री वे डायरैकट करवा देते हैं। वह किसान जो अनपढ़ है, बेकसूर है, गरीब है वह उस मुकदमें में फंस जाता है। वह जमीन भी बेच बैठता है और उसको कुछ नहीं मिलता है, इस तरह की कालोनियों पर कुद रोक–थाम लगाई जाए और उसके लिए ऐसा प्रावधान किया जाए कि जो कॉलोनियों पहले बन चुकी हैं उनको तो रैगुलराईज कर दिया जाए, उनको जो फैसीलिटीज दी जानी हैं वे दी जाएं लेकिन बाकी कालोनीज के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। जो कालोनीज कट रही हैं उनको आप रोकिए। कालोनीज कट जाने के बाद प्लाटस बिक जाते हैं और मकान जब बन जाते हैं तो फिर उनका कोई फायदा नहीं होता है फिर हम उनको रोक नहीं सके हैं। मैं यह भी नहीं चाहूंगा कि जो कालोनीज कट चुकी हैं और प्लाटस बिक चुके हैं उनको रोका जाए लेकिन आज हम नई कटने वाली कालोनियों को तो रोक सकते हैं। आज हम कह सकते हैं कि ऐसा न किया जाए या उन पर हम कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: लेकिन सरकार तो उस पर कार्यवाही करेगी जिसकी जमीन है। आप ऐसे केसिज की कम्पलेंट करें तो उनकी अलग से इन्क्वायरी करवा ली जाएगी। अगर मेरे नाम जमीन है और मैं उसको बेचता हूं तो नाम तो मेरा रहेगा ही और अगर कोई एक्शन होगा तो वह मेरे खिलाु ही होगा (विघ्न)

श्री शादी लाल बत्तरा: मुख्यमंत्री जी, मैं यह कहना चाहूंगा कि जब कालोनीज कट रही होती हैं तभी टाउन प्लानर्ज ऑफिसर को उनको देखना चाहिए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: पर्चा कटने के बाद ही मुकदमा दर्ज होगा। (विघ्न)

श्री शादी लाल बत्तरा: मैं यह बात कहता हूं कि पर्चा उसके नाम पर दर्ज होगा लेकिन एग्रीमैंट हो जाता है (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: उसी एग्रीमैंअ की नकल के आधार पर आम कम्पलैंट करें उस पर भी इन्क्वायरी करवाई जा सकती है।

श्री शादी लाल बत्तरा: मुख्यमंत्री जी, मैं किसी की कम्पलेंट नहीं कर रहा हूं मैं तो जनरल बात कह रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: बिना किसी शिकायत के तो सरकार को कुछ पता नहीं चलता है।

श्री शादी लाल बत्तरा: मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूं मैं तो यह कह रहा हूं कि जनरली ऐसा होता है और अगर ऐसा होता रहा तो यह हमारे आने वाले टाईम के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और इसमें जो अन–एथोराईज्ड कालोनीज बन जाएंगी वो इतनी हैफहजर्ड कन्स्ट्रक्शन होगी कि उसका फल कोई

अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं। मैं किसी की कम्पलेंट नहीं कर रहा हूं मैं केवल इतनी बात कह रहा हूं कि आने वाले टाईम के लिए उसकी रोकथाम होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अब मैं बिजली की बात करता हूं। मुख्यमंत्री जी, अभिभाशण में यह कहा गया है कि आने वाले टाईम में 10 हजार टयब्वैलज कनैक्शन्ज मिलेंगे, यह बड़ी अच्छी बात है लेकिन अगर हम देखें कि पिछले करीब डेढ़ साल में कितने कनैक्शन्ज दिए गए हैं तो मैं यह कह सकता हूं और मेरा विश्वास भी हैं कि हरियाणा प्रदेश में एक भी कनैक्शन रिलीज नहीं हुआ है (विघ्न)

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा): अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय साथी की जानकारी के लिए इनको कनैक्शन्ज की वस्तुस्थिति बता देता हूं जो कि इस प्रकार हैं। 1997–98 में 960 कनैक्शन्ज दिये गये, 1998–99 में 835 कनैक्शन्ज दिये गये तथा 2000–2001 में 911 कनैक्शन्ज दिए गए हैं। (इस समय मेजे थपथपाई गई)

श्री शादी लाल बत्तरा: अध्यक्ष महोदय, मैं टयूबवैल के कनैक्शन के लिए अप्लाई करना चाहता था और मैं इसके लिए एक्सीयन से मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि पिछले कई सालों से कोई कनैक्शन नहीं दिया गया है इसलिए आपको अभी कनैक्शन नहीं मिल सकता है।

सरदार जसविन्द्र सिंह सधु: अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने पहले सिक्योरिटी भरी हुइ हैं उनको प्रायरिटी के आधार पर कनैक्शन्ज दिये गये हैं।

श्री शादी लाल बत्तरा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी की बात ठीक हो सकती है मैं यह कह रहा हूं कि रोहतक में मेरे साथ यह बात हुई है। टयूबवैल के कनैक्शन के लिए मैंने एप्लाई किया और मुझे कहा गया कि टयूबवैल कनैक्शन रिलीज नहीं हो सकता है। (विघ्न) क्योंकि पिछले डेढ़ साल से कोई भी कनैक्शन रिलीज नहीं किया गया है। गर्वनर एड्रैस में कहा गया है कि तत्काल की पालिसी होगी, ट्रांसफार्मर की पॉलिसी होगी। तत्काल ट्रांसफार्मर की जो पालिसी आती है उसमें तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि टयूबवैल के लिए स्पैशल कन्सैशन होना चाहिए और अगर कोई एग्रीकल्चर लैण्ड के लिए कनैक्शन लेना चाहिए है तो तत्काल की कोई फीस अगर रखी जाए तो वह भी हो सकता है लेकिन टयूबवैल का कनैक्शन मिल जाना चाहिए (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: बत्तरा साहब, आप अब वाईड अप करें।

श्री शादी लाल बत्तरा: अध्यक्ष महोदय, आप मुझे जब भी आदेश करैंगे मैं बैठ जाउंगा। मैं तो एक ला एबाईडिंग आदमी हूं अगर आप मुझे कहेंगे कि बोलना बन्द कर दें तो मैं बन्द कर दूंगा। (विघ्न) मुख्यमंत्री जी जब बिजली की बात करते है तो हम यह बात करते हें कि यह चीज आगे या पीछे रहेगी। मुख्यमंत्री जी

कहीं पर गए तो उन्होंने एक मिसाल दी कि मैं तो तेल के दिये में पढ़ा था आप भी तेल का दिया जला कर पढ़े, मोमबत्ती की रोशनी में पढें। वैसे तो यह बड़ी अच्छी बात है लेकिन साथ ही मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कम्पयूटर सीखें लैप–टाप भी दूंगा और सारी चीजें कम्पयूटराईज्ड भी कर देंगे। अगर एक तरफ तो ये कम्पयूटराईजेशन कर रहे हैं दूसरी तरफ कहते है कि जला कर पढ़े तो फिर कम्पयूटर कैसे चलाएंगे और कम्पयूटर की शिक्षा कैस मिलेगी? (विघ्न) इसलिए कुछ न कुछ हमें बिजली के बारे में कहना होगा ताकि ये जो कम्पूयटर देंगे वे चल सकें। अध्यक्ष महोदय, बिजली का कनैक्शन लेना हो, नक्शा पास करवाना हो, सिवनेज का कनैक्शन लेना हो तो उसके लिए डवैल्पमैंट फंड अलग अलग जामा करवाने पड़ते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहूंगा कि ये जो भी फंड या टैक्स देने होते हैं उसके लिए एक ही खिड़की होनी चाहिए ताकि मकान बनाने वाले को यह पता रहे कि उसे क्या क्या टैक्स जमा करवाने है। इसके साथ साथ मैं सरकार को आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर किसी आदमी ने अपनी ही तार और मीटर अरेंज करने होते हैं तो उनसे यह सिक्योरिटी किस बात की ली जाती है? अगर सिक्योरिटी ली जाती है तो उन चीजों का इन्तजाम भी सरकार को करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमारे पास विकास के लिए कई प्रणालियां हैं। यह जो विकास समिति गठित हुई है यह बहुत ही अच्छी बात है लेकिन इसका प्रभाव पंचायतों पर पड़े, यह ठीक बात नहीं है। पंचायतों को एक एक्ट

के अन्दर बनाया गया था, उनका चुनाव हुआ और लोगों ने उनको वोट दिए। जब ग्रामवासियों के उनको चुनकर भेजा तो उनके ऊपर विकास समितियों का गठन करके बिठा दिया गया। उसके कारण क्या हुआ कि पंचायत वाले कहते हैं कि हमें जनता ने चुनकर भेजा है और विकास समिति के मैम्बर्ज को सरकार ने लगाया है इसलिए हम उनसे ऊपर हैं। इसके कारण उनमें भेदभाव की भावना पैदा हो रही है। आज आपने यह समिति बनानी है तो इन समितियों के मैम्बर्ज को चुनने की पावर पंचायत को देनी चाहिए ताकि उनके अन्दर किसी तरह का भेदभाव न आ सके।

श्री रामबीर सिंह: आन ए प्वांट आफ आर्डर सर, अध्यक्ष महोदय, यहां पर विपक्ष के भाईयों ने बहस करते हुए ग्राम विकास समितियों पर बहुत ही जोर दिया है। मैं सभी सदस्यों को बताना चाहूंगा कि मैं गुजरात में 15 दिन के लिए गया था। वहां पर जितनी भी बिल्डिंगज गिरी हैं उनमें ज्यादातर सरकारी बिल्डिंगज थी या पंचायतों की बिल्डिंगज थी। विकास समितियों के कारण क्या होगा मैं यह बताना चाहूंगा कि पहले जो अधिकारी या दूसरा कोई मैटिरियल में गड़बड़ करता था वह गड़बड़ नहीं हो पाएगी। जो बिल्डिंगज बनेगी वे पक्की बनेंगी और भवनों के निर्माण में गुणवता बढ़ेगी।

श्री शादी लाल बत्तरा: अध्यक्ष महोदय, यह जो विकास समितियों का गठन होना चाहिए वह किस एक्ट के तहत होना चाहिए उनका गठन कैसे होना चाहिए, यह सब पहले से तय होना

चाहिए? अध्यक्ष महोदय, यसह जो इलैक्टिड बाडी है उसको ज्यादा पावर होनी चाहिए ताकि वे ऊपर जाकर जवाब दे सके कि वह विकास कार्य किया है और यह विकास कार्य नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है? अगर कोई विकास कार्य करना है तो वह क्या क्या और कहां कहां पर करना है। अध्यक्ष महोदय, अब पानी की बात आती है। आज वाटर लैवल कम हो गया है क्योंकि बारिश नहीं हुई है। मैं अपने इलाके की बात करना चाहूंगा कि मायना, काहनौर, चिमनी और ढराणा की टेल तक जे.एल.एन. कैनाल का पानी नहीं पहुंचता है जिसके कारण खेती नहीं हो सकी। हमारे वहां पर वाटर वर्क्स पानी से महरूम रह गए हैं। वहां पर जो लोग हैं उनको न तो पीने के लिए पानी लि रहा है और न ही खेती के लिए पानी मिल रहा है। तो उसके लिए मैं एक बात कहूंगा कि पानी का बंटवारा ठीक से होना चाहिए। जितने दिन भी पानी चलता है वह स्पैसिफिकेशंज के मुताबिक टेल तक जरूर पहुंचना चाहिए। पहले 23 दिन कैनाल चलती थी अब 35 दिन हो गयी है लेकिन अगर उतने दिन में भी पानी नहीं मिलेगा तो फिर तो जमीदारों का नुक्सान ही होगा। आज वे पानी न मिलने के कारण त्राहि–2 कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री बलवन्त सिंह मायना (हसनगढ़): स्पीकर साहब, पांच तारीख को इस सदन के अंदर महामहिम राज्यपाल बाबू परमानन्द

जी ने जो अपना अभिभाशण दिया और जो सरकार ने विकास कार्य किए, उसको उसमें दर्शाया, उसके लिए उनका अभिनन्दन करते हुए कुछ चर्चा करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं हरियाणा की सरकार का और मुख्यमंत्री चौ. ओम प्रकाश चौटाला जी का इस बात के लिए आभार प्रकट करूंगा कि गुजरात में जो भगवान ने विनाशलीला की और जिस तरह से वहां नुक्सान हुआ, ऐसे वक्त में हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने और हरियाणा की जनता ने वहां जाकर जो 19 गांव में राहत कार्य किए वह एक सराहनीय बात है। गुजरात में हर एक गांव की यह मांग थी कि उनका गांव हरियाणा सरकार के अधीन दिया जाए। जिस प्रकार से वहां पर हरियाणा की जनता ने और हरियाणा सरकार ने राहत कार्य किए वह एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।) उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं हरियाणा प्रदेश में शिक्षा की बात करना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी के सामने बहुत कठिनाईयां थीं। पहले चाहे वह चौ. बंसी लाल जी की सरकार रही हो या चौ. भजनलाल की सरकार रही हो किसी ने भी शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया। पहले जिस तरह से दूसरी सरकारों ने जनता से दूरी बढ़ाई उसके विपरीत हमारे मुख्यमंत्री जी से 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत जनता से दूरी कम करने का काम किया। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। इस कार्यक्रम के तहत उस वक्त जो भी गांव वालों के सामने परेशानियां थी उनका उन्होंने मौके पर ही समाधान किया। मेरे से पहले बहुत से बोलने वाले हमारे साथियों ने शिक्षा के बारे में बातें कही हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कहना

चाहूंगा कि आज हरियाणा प्रदेश के अन्दर कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां पर सरकार ने उपरोक्त कार्यक्रम के तहत स्कूलों में कमरे न बनवायें हों। मैं इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं 1991 में एम.एल.ए. बनकर आया था उस समय चाहे मुख्यमंत्री कोई भी रहा लेकिन कोई काम नहीं किए गए। उस समय चुनाव के समय जब हमारे इलाके में ये लोग जाते थे ते सर छोटू राम का नाम लेकर लोगों से वोट लेने की बात करते थे। हम 1991 से लेकर 1996 तक कई बार मांग करते रहे लेकिन इन्होंने हमारी बात नहीं मानी लेकिन हमारे मुख्यमंत्री थी ने एक मिनट नहीं लगाई मेरे इलाके में सांपला में लड़कियों का कालेज बनाने का काम कर दिया है। यह एक बहुत ही सराहनीय काम था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में पहले ग्रामीण आंचलों में बसने वाले गरीबों के बच्चे किसी भी कम्पटीशन में नहीं आते थे। वे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे रह जाते थे। इसका कारण क्या था? इसका कारण यही था कि शिक्षा इस प्रकार की थी कि बड़े घराने अपने बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ाते थे और बड़े शहरों में उनके बच्चे पढ़ते थे। ग्रामीण आंचलों में बसने वाले लोगों के बच्चे इस तरह की पढ़ाई नहीं पढ़ सकते थे इस समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले पहली क्लास से अंग्रेजी पढ़ाने का जो काम किया है और ग्रामीण अंचलों में बसने वाले लोगों के बच्चों को जो प्राथमिकता दी है उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। अग्रोहा मैडीकल कालेज में जो हमारे प्रदेश के

बच्चे डॉक्टरी की शिक्षा पढ़ते थे वे शिक्षा से वंचित हो गए थे लेकिन चौटाला साहब ने सबसे पहले अग्रोहा मेडीकल कालेज को चालू करने का काम किया। आज का युग कम्प्यूटर का युग है, नयी तकनीक आ गई इसलिए आज मुख्यमंत्री जी ने कम्प्यूटर पद्धति लागू की है ताकि हरियाणा प्रदेश विकास की तरफ जा सके। सरकार ने हरियाणा प्रदेश के नौजवान बच्चों के लिए सराहनीय कार्य किया है और सबसे ज्यादा ध्यान उसने शिक्षा पर दिया है, चाहे चौ. भजन लाल की सरकार थी या बंसी लाल जी की सरकार थी, बच्चे पढ़ने वाले तो होते थे लेकिन मास्टर पढ़ाने वाले नहीं होते थे। आज चौ. ओम प्रकाश चौटाला जी ने नौजवानों को रोजगार देने व बच्चों को मास्टर देने का काम किया है और दस हजार शिक्षकों की भर्ती की है, यह एक सराहनीय काम है। चाहे पुलिस की भर्ती की बात है या वी.एल.डी.ए. और ए.एन.एम. की भर्ती की बात है। चौ. भजन लाल व चौ. बंसी लाल जी ने लड़के–लड़कियों की भर्ती नहीं की लेनिक चौ. ओम प्रकाश चौटाला जी ने 14 हजार लड़के–लड़कियों की भर्ती करके रोजगार देने का काम हरियाणा प्रदेश में किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी सम्मानित साथी यह साबित कर दे कि पैसे लेकर नौकरी दी है तो मैं विधान सभा से अपना इस्तीफा देकर चला जाऊंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पता है कि गुप्ता जी भी एक–एक घूंट पानी पीकर सांस लिया करते थे लेकिन आज वे भी नहीं बोल रहे हैं। शिक्षा पर ध्यान देने के साथ–साथ कृशि पर भी चौटाला साहब ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया

है। एक तो कुदरत की निगाह ऐसी रही कि बारिश कम हुई लेनिक बारिश कम होने के बावजूद भी चौटाला साहब ने ऐसे प्रयास किए कि नहरों की टेल तक पानी पहुंचे। मेरे हल्के में कभी भी टेल तक पानी नहीं पहुंचा था लेकिन इस बार माननीय श्री चौटाला साहब के प्रयासों से वहां पर पानी पहुंचा है। मैं यह बात दावे के साथ कह रहा हूं। यह ठीक है कि सरकार के सामने मजबूरियां हैं, समस्याएं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कृशि की चर्चा हो रही थी मेरे माननीय साथी बोल रहे थे कि हरियाणा प्रदेश के अन्दर कृशि सिंचाई करने के दो ही साधन हैं एक तो टयूबवैल्ज और दूसरा यमुना या भाखड़ा नहर का पानी। पिछली सरकारों ने टयूबवैल्ज के कोई कनैक्शंज नहीं दिये। जबकि चौ. ओम प्रकाश चौटाला की सरकार ने सत्ता संभालते ही 9111 टयूबवैल्ज कनैक्शंज देने का काम किया है। उपाध्यक्ष महोदय, किसानों को गन्ने का भाव 104, 106 और 110 रूपये क्विंटल किस्म के हिसाब से देने का काम इस इस सरकार ने किया है जो कि सारे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा है। जो किसानों का बकाया मिल मालिकों की तरफ 21 करोड़ रूप्ये था उसका भुगतान करने का काम भी इस सरकार ने किया है जिसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री चौ. ओम प्रकाश चौटाला जी बधाई के पात्र हैं। मेरे विपक्ष के भाईयों का यह कहना कि यह सरकार किसानों की हितैशी नहीं है, ठीक नहीं है। इसके बाद मैं डिप्टी स्पीकर साहब, बिजली के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। कुछ साथी बिजली की बात कर रहे थे। मैं उनको बताना चाहूंगा कि चौ. ओम प्रकाश चौटाला

जी की सरकारने बिजली के बारे में जितना काम किया है उतना किसी सरकार ने नहीं किया। चौ. भजन लाल और चौ. बंसी लाल जी की सरकरों ने हरियाणा प्रदेश के अन्दर बिजली का एक भी प्रोजैक्ट नहीं लगाया। चौ. देवीलाल जी की सरकार के वक्त जैसा की माननीय साथी श्री कृश्ण लाल पंवार जी ने बताया कि पानीपत थर्मल प्लांट की छठी यूनिट का जो सामन लाकर रखा गया था, उसको लगाने का काम भी उन सरकारों से नहीं हुआ। अब इस सरकार ने आने के बाद इस यूनिट पर दोबारा काम शुरू किया है जो कि अप्रैल तक पूरा हो जायेगा। इसके बाद हरियाणा प्रदेश को पूरी बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी, विपक्ष के माननीय साथी किसानों की बात करते हैं। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब, इसी प्रकार से मैं सड़कों की बात करता हूं। चौ. बंसी लाल जी कहा करते थे कि मैंने हरियाणा प्रदेश में इतनी सड़कें निकाल दी हैं कि भविश्य में कोई सरकार इन पर थेगली लगाने वाली भी नहीं मिलेगी। आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज हरियाणा प्रदेश के अन्दर चौ. ओम प्रकाश चौटाला ने राज्य मार्गो को बनाया है उसी प्रकार से गांवों की सड़कों को बनाने का काम भी उन्होंने किया है। अगर कोई माननीय साथी चाहे तो मेरे साथ चलकर देख सकता है। वह गांव की सड़क पर भी अपनी गाड़ी को 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर चला सकता है। एक मेरे माननीय साथी कह रहे थे कि बेरी की सड़कों की हालत खराब है। वह मेरे साथ चलकर देख सकते हैं कि वहां की सड़कें बनाई गई हैं कि नहीं बनाई गई। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष: मायना साहब, सड़कें बनाने की बात तो विपक्ष के साथी मान गये हैं।

श्री बलवन्त सिंह मायना: उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने कठिनाईयां हैं क्योंकि पिछली सरकारों के समय के काफी खाते खाली मिले थे। लेकिन इसके बावजूद भी आज परिवहन की बसें मंगवाई जा रही हैं। 1100 नई बसें मंगवाने का कार्य चल रहा है और इनमें से 450 बसें तो आ चुकी हैं। यह प्रदेश में आज की सरकार की कार गुजारी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मुझे याद है जब मैं सरपंच होता था इस समय ब्लाक स्तर पर खेल हुआ करते थे, स्टेट लैवल पर खेल हुआ करते थे। चौ. देवीलाल जी ने खेल करवाए थे लेकिन बाद में बंसी लाल जी और भजन लाल जी की सरकारें आई तो खेलों को बिल्कुल खत्म का दिया गया। आज मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री चौ. ओम प्रकाश चौटाला जी का और अभय सिंह चौटाला जी का जो हरियाणा ओलम्पिक ऐसोसिएशन के प्रधान हैं, आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने हरियाणा में स्टेट लैवल पर खेलों की दोबारा शुरूआत की। यह एक सराहनीय कार्य है। इसी प्रकार से अब मुख्यमंत्री महोदय ने सभी बोर्डो और कार्पोरेशनज के अन्दर ये हिदायतें कर दी है कि खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री महोदय ने हरियाणा पुलिस की भर्ती में 114 पद खिलाडियों के लिए रिजर्व कर दिए हैं। नौकरियों के अन्दर भी खिलाडियों के लिए 3 प्रतिशत सीटें रिजर्व करके

मुख्यमंत्री महोदय ने एक सराहनीय कार्य किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं 20 सालों तक सरपंच रहा हूं। मैं आज मुख्यमंत्री को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने विधानसभा के, जिला परिशदों के, ब्लाक समितियों के और पंचायतों के चुनाव फेयर और ईमानदारी से कराए हैं यह हरियाणा में पहली बार हुआ है। मुख्यमंत्री महोदय ने पंचायतों को अधिकार भी दिए हैं। अब पंचायतों या जिला परिशदों में से जो भी श्रेश्ठ काम करके प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करेगी उसके लिए उनको प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 8 लाख रू., दूसरा स्थान प्राप्त करने पर 5 लाख रू. और तृतीय स्थान प्राप्त करने पर 3 लाख रू. देने की घोशणा मुख्यमंत्री जी ने की ताकि उनका हौंसला बना रहे और वे अच्छा काम कर सकें। यह एक सराहनीय कार्य है। उपाध्यक्ष महोदय, गांवों में जो ग्राम विकास समितियां बनाई गई हैं वे इसलिए बनायी गयी हैं क्योंकि कई बार अच्छे आदमी पंचायतों का चुनाव लड़ना नहीं चाहते और वे विकास के कार्यो से जुड़ने से वंचित रह जाते थे। अच्छे आदमी वंचित न रह जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री चौ. ओम प्रकाश चौटाला जी ने ग्राम विकास समितियां बनाई हैं। रिटायर्ड फौजियों और बैकवर्ड क्लास के लोगों को भी इनमें शामिल किया है ताकि वे अच्छा काम करवाने में शामिल हो जाएं, गांव के विकास कार्यो में शामिल हो जाएं। इसलिए ग्राम विकास समितियों को गठन करके चौ. ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक अच्छा निर्णय लिया है। उपाध्यक्ष महोदय, बुढ़ापा, विकलांग और विडो पैंशन पहले वाली सरकारें

2–3 लाख लोगों को ही देती थीं लेकिन माननीय चौ. ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार ने इस पैंशन को बढ़कर 100 रूपये से 200 रूपये ही नहीं किया बल्कि दोबारा से सर्वे करवाकर अब यह पैंशन 13 लाख लोगों को दी जा रही है। यह मौजूदा सरकार का बहुत सराहनीय कार्य है और इसके लिए मैं चौ. ओम प्रकाश चौटाला जी को बधाई देता हूं। (शोर एवं व्यवधान) इसके अतिरिक्त मौजूदा सरकार ने हरियाणा के अन्दर जितने भी राज मार्ग हैं वहां पर 19 जगहों पर फर्स्ट ऐड की सुविधा शुरू कर दी है। भगवान करे ऐसा न हो कि किसी का एक्सीडैंट हो जाये, लेकिन अगर हाईवे के ऊपर एक्सीडैंट हो जाता है तो अब तुरन्त वहां पर फर्स्ट ऐड की सुविधा मिल जाएगी। (शोर एवं व्यवधान) मौजूदा सरकार का यह भी एक सराहनीय कार्य है और इसके लिए वह बधाई की पात्र है। उपाध्यक्ष महोदय, आज के दिन हरियाणा प्रांत के अन्दर चारों तरफ चहुंमुखी विकास हो रहा है। इसके अतिरिक्त मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस समय चौ. भजन लाल जी मुख्यमंत्री थे और हम विपक्ष में बैठे किसानों के हक की बात करते थे तो उस समय चौ. भजन लाल जी किसानों की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं देते थे जबकि आज इन्हें किसानों का ध्यान आ रहा है। (शोर एवं व्यवधान) इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका दोबारा से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाशण का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

चौ. भजन लाल: उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय मैं मुख्यमंत्री था उस समय जिस जमीन पर बुआई नहीं हो पाई थी उसके लिए प्रति एकड़ के हिसाब स 3–3 हजार रूपये मुआवजे के रूप में किसान को दिए गये थे और आज कुछ भी नहीं दिया जा रहा।

श्री रमेश कुमार खटक: उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के गांव जवारा में चौ. भजन लाल जी के मुख्यमंत्री काल के दौरान 25–25 पैसे प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया गया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती सरिता नारायण (कलानौर, अनुसूचित जाति): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं और राज्यपाल महोदय के अभिभाशण का समर्थन करती हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री महोदय ने शासन में आते ही बहुत से सराहनीय कार्य किये हैं उनके लिए मैं उनको बधाई देती हूं। शासन में आते ही उन्होंने जो जवाब बोर्डर पर शहीद होते थे उनके परिवार की तरफ ध्यान दिया और शहीदों का पूरे मान सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस ओर केन्द्र सरकार ने भी पूरा ध्यान दिया। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी हरियाणा सरकार ने शहीद परिवारों के लिए जो राशि पहले पांच लाख थी, वह बढ़ाकर 10 लाख कर दी। इसके अतिरिक्त घायल जवानों के परिवारों को जो पहले तीन लाख की राशि मिलती थी, वह भी बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई। हरियाणा सरकार

ने यह एक बड़ा सराहनीय कार्य किया है। उपाध्यक्ष महोदय, हरिजन लड़कियों की शादी के समय हरिजन लड़कियों को कन्यादान के रूप में 5100 रूपये की राशि हरियाणा सरकार दे रही है इसके अलावा हरिजन विधवाओं की लड़कियों की शादी के लिए भी 10000/– रूपये की राशि दी जाती है जो कि पहले 5000 रूपये थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने कृशि उत्पादन बढ़ाने पर अत्याधिक बल दिया है और मेहनती एवं कर्मठ किसानों को अधिक उत्पादन करने हेतू प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रमाणित बीजों पर 200 रूपये से लेकर 1000 रूपये प्रति क्विंटल की सबसिडी दी है। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने महिलाओं की शिक्षा पर भी विशेश बल दिया है। वर्श 2001 के दौरान महिलाओं के लिए दो नये राजकीय महाविद्यालय खोले गये, जिससे कन्या महाविद्यालयों की संख्या आठ हो गई। इसके अलावा 164 महाविद्यालयों में महिला विकास एवं अध्ययन सैल स्थापित किय गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने महिलाओं के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों की सुरक्षा तथा उनके सामाजिक स्तर को सुधारने के लिए राज्य महिला आयोग स्थापित किया है उसके लिये भी मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार सड़कों के निर्माण और मरम्मत का काम भी बड़ी तेजी से कर रही है, मेरे हल्के की भी कुछ सड़कें हालांकि बन रही हैं लेकिन कुछ सड़कें जो अभी बहुत खराब हैं, उनका विवरण मैं सदन में देना चाहती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इन सड़कों की हालत काफी हद तक खराब है मेरे हल्के की कुछ सड़कों की तरफ विशेश ध्यान देना जरूरी है क्योंकि मेरा हल्का काफी पिछड़ा हुआ है। पहले जो भी माननीय विधायक इस हल्के से रहे हैं उन्होंने मेरे हल्के को बड़ा अनदेखा किया था। मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि अगर इस हल्के के सुधार के लिये 20 साल भी दिये जाएं वो वह भी कम हैं क्योंकि पिछली जो सरकारें रही हैं उन्होंने इस हल्के के साथ बड़ा सोतेला व्यवहार किया है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां तक कि वहां पर आई.टी.आई. खोलने के लिये जो जमीन तय की गई उसके लिए भी केवल 15 लाख रूपय की राशि ही तय हुई। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगी कि वह जमीन जोहडनुमा जमीन है और इस जोहड़नुमा जमीन की भरत वगैरह करके समतल बनाने पर ही 15 लाख रूपये लग जाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगी कि अगर जल्द से जल्द यह आई.टी.आई. बन जाए तो इससे हल्का कलानौर के आसपास के काफी बच्चों को फायदा हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि खेलों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगी कि जहां मेरे हल्के में खेलों की तरफ इतना ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है तो वहां पर एक स्टेडियम या पार्क बनवा दिया जाए तो वहां के ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाभ पहुंचेगा। उपाध्यक्ष महोदय, अब स्कूल अपग्रेडेशन की बात आती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि शिक्षा के मामले में, स्कूलों

के मामले में और सभी विकास कार्यों के मामले में मेरा हल्का बड़ा पिछड़ा हुआ था लेकिन अपनी यह सरकार आने के बाद मेरे हल्के में काफी हद तक सुधार हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानती कि वहां के मेरे से पहले रहे माननीय विधायकों से उस हल्के की तरफ क्यों ध्यान नहीं दिया। उपाध्यक्ष महोदय, चौ. ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार आने के बाद इस हल्के के लोगों में भी जागरूकता आई है वे देखप रहे हैं कि दूसरे हल्कों में विकास कार्य कितनी तेजी से हो रहे हैं। वे चाहते हैं कि हमारी आवाज मुख्य मंत्री जी तक पहुंचे ताकि 15 साल से पिछड़े हुए इस हल्के के विकास का काम भी दूसरे हल्कों की भांति हो और दूसरे हल्कों के साथ–साथ यह हल्का भी आगे बढ़े। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में लाहली माईनर है जिसमें पानी का प्रैशर बहुत कम होता है जिसके कारण टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान अपने हल्के की माईनर की ओर दिलाना चाहूंगी कि माईनर में पानी का प्रैशर कम होने की वजह से मेरे हल्के के गांवों में टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता। जब भी नहर आती है तो ये गांव इसके पानी से वंचित रह जाते हैं। इसके अलावा एक भूतियान माईनर है अगर उसे चौड़ा कर दिया जाए तो इस से भी वहां के काफी गांवों के किसानों की समस्या हल हो सकती है। इस तरह काहनौर डिस्ट्रीब्यूटरी का लैवल भी ठीक नहीं है इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करती हूं कि काहनौर डिस्ट्रीब्यूअरी का भी लैवल ठीक कर दिया जाए तो वहां के कई

गांवों के किसानों को इसका लाभ मिले। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में पशुओं के अस्पताल की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। उस बिल्डिंग की छत के नीचे कोई आदमी बैठ नहीं सकता क्योंकि उसकी छत किसी भी समय गिर सकती है। उसकी तरफ सरकार ध्यान दे। हरियाणा प्रदेश में सड़कें बनाने का काम और टूटी हुई सड़कों की रिपेयर कर काम बहुत तेजी से चल रहा है। बहुत जल्दी सारी सड़कें चारों तरफ पक्की होने जा रही हैं। मेरे हल्के में कुछ नई सड़कें बनी हैं और कुछ पर कार्य चल रहा है। मैं अपने हल्के की कुछ सड़कें बनाने की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगी। ये सड़कें हैं—कलानौर से सैम्पल तक, गरनावठी से सुण्डाना तक, सिंहपुरा खुर्द से बहुजामालपुर तक, कैलंगा से चांग तक, भगवतीपुर से गिरावड़ तक, गरनावठी से भाड़ोधी तक, भाड़ोधाी से पटवापुरतक, भाड़ोधी से ककराना तक, डोभ से काहनोर तक, कैलंगा स सैम्पल तक, सैम्पल से बसाना तक, कलानौर कालेज मोड से काहनोर तक, आवल से लाहली तक और बहुअकबरपुर से लाहली तक। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के कलानौर के स्कूल अपग्रेड होने चाहिएं। जो स्कूल पांचवी कक्षा तक के हैं उनका दर्जा बढ़ा कर 8वीं कक्षा तक किया जाए, जो स्कूल 8वीं तक के हैं उनका दर्जा बढ़ाकर 10वीं तक का किया जाए और जो स्कूल 10वीं तक के हैं उनका दर्जा बढ़ाकर 10+2 तक किया जाए। मेरे हल्के के गांव जिन्दरान का स्कूल 8वीं तक का है उसका दर्जा बढ़ाकर 10वीं तक का किया जाए। इसी तरह से भगवतीपुर गांव का स्कूल 10वीं तक का है उसका दर्जा बढ़ा कर

10+2 का किया जाए क्योंकि उस गांव की लड़कियों को पढ़ने के लिए बसों में लद कर कलानौर और भिवानी आना जाना पड़ता हैं बहुजमालपुर गांव का स्कूल पांचवी कक्षा तक का है उसका दर्जा बढ़ा कर 8वीं तक का किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं कहना चाहूंगी कि गुजरात में जो भूकम्प आया उससे वहां पर जान माल की बहुत हानि हुई। वहां पर हरियाणा सरकार ने जो भूकम्प से प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए राहत शिविर लगाये और हरियाणा सरकार ने रापड़ तालुका के 19 गांव पूर्ण राहत पहुंचाने के लिए चुने उसके कारण पूरे देश में हरियाणा सरकार की बड़ाई हुई हैं। यह एक बहुत ही सराहनीय काम है। उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे बोलने का काम दिया। धन्यवाद।

श्री रमेश कुमार खटक (बड़ौदा, अनुसूचित जाति): उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर बोलने का मौका दिया। उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाशण में सरकार की जो उपलब्धियां दर्शाई गई हैं मैं उनके बारे में चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं उनका समर्थन करता हूं। मेरे से पूर्व बोलने वाले सदस्यों ने इस सरकार के बारे में और पिछली जो सरकारें रही उनके बारे में चर्चा की। उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात में जो भूकम्प आया उसमें हजारों जानें मौत के मुंह में चली गई। 26 जनवरी का दिन सारे देश में बड़े हर्श और उल्लास

से मनाया जा रहा था। ज्यों ही यह दुखद भरा समाचार लोगों को पता चला तो सारे देश के अन्दर एक सन्नाटा सा छा गया क्योंकि यह घटना एक बहुत बड़ी घटना थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री चौ. ओम प्रकाश चौटाला का धन्यवाद करता हूं और इनका आभार प्रकट करता हूं कि हमारी सरकार ने न केवल वहां पर सामग्री भेज क बल्कि हमारे कुछ उच्च अधिकारियों को भेज व कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को स्पीकर साहब की रहनुमाई में भेज के जो भी जरूरत थी, वहां पर उन लोगों की मदद करने का काम किया। इसी प्रकार से उड़ीसा में भी हमारी सरकार ने काफी मदद की। इस दिशा में हमारी हरियाणा सरकार ने जो जो काम किये वे सबके सामने हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बताया कि चौ. बंसी लाल जी ने कहा था कि उन्होंने हरियाणा प्रदेश में इतनी सड़कें बना दी है कि उनकी मुरम्मत करनी भी मुश्किल होगी। चौ. बंसी लाल जी ने केवल सड़कों के नाम पर पैसा खाने का काम किया था। अगर सड़कों पर काम किया गया है तो वह चौ. ओम प्रकाश चौटाला की सरकार के समय किया गया है। मैं इस बारे में खासतौर से अपने हल्के बड़ौदा के बारे में कहना चाहूगा। मेरा हल्का काफी समय से अपोजीशन का हल्का रहा है। वहां पर एक भी सड़क चौ. भजन लाल के नेतृत्व वाली व बंसी लाल जी के नेतृत्व वाली सरकारों के समय में नहीं बनी, कई बार मैंने इनसे प्रार्थना की थी लेकिन मेरी प्रार्थना पर सरकार ने

कभी गौर नहीं किया और न ही इनके समय में मेरे हल्के में कोई नई सड़क बन पाई और न ही किसी सड़क की रिपेयर हो पायी थी। अब मैं अपने मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जहां सारे हरियाणा में सड़कों का काम चाहे वे नई सड़कें बनाने का काम हो या पुरानी सड़कों की रिपेयर का काम हो, पूरे जोर से चल रहा है। चौ. ओम प्रकाश चौटाला ने मेरे हल्के में 18 नई सड़कें मंजूर की हैं और जिन सड़कों की मुरम्मत का काम होना था, उनकी मुरम्मत की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। पिछली सरकारों के समय में जब भी सैशन चला करता था तो शिक्षा की बात जरूर करते थे लेकिन वह सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाते थे। लेकिन आज के दिन में अपने मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि देहात के बच्चों के बीच में और शहर के बच्चों के बीच में जो अन्तर पढ़ाई का था, इसको दूर करने का उन्होंने कोशिश की है। शहर के बच्चों की अपेक्षा देहात के बच्चों को इन्टरव्यू में मात खानी पड़ती थी। वह मात इसलिए खानी पड़ती थी कि देहात के बच्चे के पास अंग्रेजी का बेस नहीं होता था। इसी खाई को दूर करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली कक्षा से लेकर पांचवी कक्षा तक अंग्रेजी विशय हो देहात के सरकारी स्कूलों में भी अनिवार्य विशय बनाया है। इसी प्रकार से हमारे हरिजन बच्चों को जिनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था उनकी दिक्कत को दूर करते

हुए आज उनके ड्रैम व किताबें भी समय पर सरकार की तरफ से मुहैय्या करवाई जा रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास के बारे में चौ. भजन लाल जी बड़े बुलन्द दावे किया करते थे और कहा करते थे कि ग्रामीण विकास और पंचायतों के लिए हम काम कर रहे हैं। अगर उन्होंने ग्रामीण विकास का रिकार्ड देखना है तो आज चौ. ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार का देखें। आज हमारी पंचायतों को जो सहूलियतें इस सरकार ने दी हैं वे सराहनीय है। पहले अपने गांव के विकास के लिए 25 हजार रूपये तक का कोई भी विकास कार्य ग्राम पंचायत कर सकती थी लेकिन इस सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कोई भी ग्राम पंचायत 25 हजार रूपये से लेकर एक लाख रूपये तक का विकास का काम कर सकती हैै। इसी प्रकार से ग्राम विकास समितियां 50 हजार से लेकर तीन लाख तक का कोई भी विकास का काम कर सकती है। जिला परिशद के मैम्बर एक लाख से लेकर पाचं लाख तक का कोई भी विकास के कार्य अपने जिले के अन्दर कर सकते हैं। इस प्रकार हमारी सरकार ने यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण के बारे में दूसरी सरकारें कहा करती थी कि हम लोगों का कल्याण कर रहे हैं लेकिन चौ. देवी लाल जी ने नीति चलाई थी कोई भी सम्मानित बुजुर्ग चाहे वह किसी भी कौम का क्यों न हो, 65 वर्श की उम्र पूरी करते ही उसको 100 रूपये प्रति माह के हिसाब से सम्मान के रूप में उसके घर भेजे जाने के का काम किया जाएगा। लेकिन पिछली सरकार ने उन बुजुर्गो को सम्मान देने की बजाए उनकी पैंशने काटने का

काम किया। आज हमारी सरकार के मुख्यमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जहां पहले अढ़ाई या तीन लाख बुजुर्गो को पैंशन दी जाती थी आज हमारी सरकार द्वारा 13 लाख विकलांग, विधवाओं और बुजुर्गो को पैंशन दी जा रही हैं। इसी प्रकार से विधवाओं के कल्याण के लिए हमारी सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। पिछड़े वर्ग के बच्चों की टयूशन फीस आदि में बड़ा सहयोग सरकार ने दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, चौ. बंसी लाल जी के जो पिछला राज था उसमें उन्होंने हरिजनों के साथ बड़ा अन्याय किया था और जहां कहीं भी हमारा हरिजनों का कोई बच्चो इन्टरव्यू देने जाता था तो उसकी परसैंटेज काट दी गई थी लेकिन मैं वर्तमान मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने आते ही अंकों में 10 प्रतिशत अंकों की छूट देने का फैसला किया है जिसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। हरिजन विधवा की लड़की की शादी हे तो उसको 10 हजार रूपयें देने का काम माननीय चौ. ओम प्रकाश चौटाला जी ने किय है और हरिजन भाईयों की लड़की की शादी के लिए 5100 रूपये का कन्यादान भेजने का काम भी इसी सरकार ने किया है। इस स्कीम से लाभ प्राप्त करने वाले जो ऐसी जाति या पिछड़े वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं उन साढ़े बारह हजार लोगों के लिए 43.47 करोड़ रूपये का प्रस्ताव इस सरकार ने रखा है। इसी प्रकार से अब मैं खेलों की बात करना चाहूंगा। खेलों में हमारे प्रदेश का कभी बहुत बोल बाला हुआ करता था लेकिन पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण

खेलों में बहुत भारी गिरावट आई थी। खेलों में हमारे जवानों का हमारे देश के अन्दर और अन्तर्राश्ट्रीय स्तर पर भी बहुत नाम हुआ करता था। इसी तरह से हरियाणा प्रदेश के नौजवानों का भी खेलों में बड़ा बोलबाला था चाहे वह कब्बडी हो, रेस्टलिंग हो या बास्केट बाल हो। लेकिन कुछ समय से यह बोलबाला ढीला पड़ा हुआ था। लेकिन आज हमारी सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देकर उनके हौंसले बढ़ाए हैं। जिस तरह से आज टी.वी. पर 'कौन बनेगा करोड़पति' नाम का सीरियल आता है उसी तरह से हमारे मुख्मयंत्री जी ने एक बात कही थी कि खिलाड़ियों को जो पदक जीत कर आएंगे उनको उसके पदक के हिसाब से उन्हें राशि ईनाम में दी जाएगी उसको उन्होंने सच करके दिखा दिया है। उन्होंने लोगों के बीच में मल्लेश्वरी जिसने हमारे देश का नाम रोशन किया है को 25 लाख का चैक दे करके अपने वायदे को सच सिद्ध कर दिया हैं। उन्होंने जो वायदा किया था उसको पूरा कर दिया है। मुझे गर्व है कि मेरे हल्के के तीन लड़कों ने एशियाड में तीन गोल्ड मैडल जीते हैं। मुख्यमंत्री जी ने उनको बुला करके सम्मानित किया है इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। मुख्यमंत्री जी के साथ साथ में अभय भाई साहब का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने खेलों में रूचि लेकर खेलों को आगे बढ़ाने का काम किया है।

18.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय, कृशि के बारे में और किसानों के बारे में हमारी सरकार बहुत चिन्तित है पहले जब भी कोई आपदा या कोई मुसीबत आया करती थी तो दूसरी सरकारें किसी को कोई भी मुआवजा नहीं दिया करती थी। अब की बार कोई ऐसी आपदा नहीं आई है। अब की बार बारिश नहीं हुई है फिर भी मुख्यमंत्री जी ने किसानों को ठीक समय पर बिजली देकर बहुत ही अच्छा काम किया है। इसके साथ–साथ मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा था अगर केन्द्र सरकार गेहूं का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाएगी तो स्टेट गवर्नमैंट की तरफ से किसानों को 20 रूपये प्रति क्विंटल बोनस के रूप में दिया जाएगा। इस तरह का आह्वान मुख्यमंत्री जी ने किया था। इस तरह से हमारी सरकार ने किसानों को राहत देने का काम किया है। चाहे कोई भी फील्ड था मुख्यमंत्री जी ने राहत देने का काम किया है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवादी हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर बोलने का समय दिया इसके लए मैं आपका भी धन्यवादी हूं। जयहिन्द।

श्रीमती अनिता यादव (साल्हावास): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। पांच मार्च को महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाशण पढ़ा वह उन्होंने अपनी जिम्मेदारी जो होती है उसके कारण पढ़ा था। हरियाणा सरकार ने जो अभिभाशण तैयार करके उनको थमाया

उन्होंने उसको पढ़कर अपनी जिम्मेवारी पूरी की है। लेकिन जो कुछ अभिभाशण में कहा गया है वह असत्य का पुलिंदा है, राजनीति के प्रेरित हैं यह किसी से भी छुपा नहीं है कि मेरा क्षेत्र साल्हावास पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र है। मेरे क्षेत्र में कुछ दिक्कतें हैं। हमारे इस क्षेत्र के एक एम.एल.ए. धर्मवीर यादय थे जो पी. डब्ल्यू.डी. मंत्री रहे हैं, को छोड़कर साल्हावास क्षेत्र अपोजीशन का ही रहा है। चौ. बंसीलाल जी की सरकार की जो कारगुजारी थी वह उसी के कारण चलती बनी। मुझे अब इस बात का डर है कि कहीं यह सरकार भी जो अपना एक साल पूरा कर चुकी है, अपनी कारगुजारियों के कारण न गिर जाए। मेरे क्षेत्र से संबंधित कुछ मेरी पर्सनल तकलीफें हैं जिन्हें मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने लाना चाहती हूं। (विघ्न) हमारी बहन बेटियों को ऐजूकेशन बहुत कम दी जाती है वे शिक्षा के मामले में पीछे रखी जाती हैं। मेरा क्षेत्र ग्रामीण आंचल में बसा होने के कारण मैं सरकार से गुजारिश करना चाहती हूं कि मेरे हल्के में मातनहेल और बिरोहड़ दो गांव हें अगर इनमें से किसी में भी एक महिला कालेज खोल दिया जाए तो वहां की बहन बेटियां की समस्या का समाधान हो सकता है। इस तरह के कालेज को खोलने की जो जो फैसिलिटीज चाहिएं वह बिरोहड़ गांव देने के लिए तैयार है। इसलिए अगर बिरोहड़ गांव में महाविद्यालय खोल दिया जाए तो आसानी से हमारी बहन बेटियों को शिक्षा मिल सकती है। इससे एक परिवार नहीं बल्कि दो दो परिवारों को आगे आने का मौका मिल सकता है। इसके आलवा एक और समस्या ऐडहाक बेसिज पर

लगे हुए टीचर्ज की है। जिनकी सर्विस 6 या 8 साल की हो गयी है उनको भी हटाया जा रहा है इसलिए इस बात पर भी गौर फरमाया जाना चाहिए। आज इस सरकार के समय में कालेजों में टीचर्ज और स्टूडैन्टस के बीच बहुत ग्रुपबाजी चल रही है। ये छात्र–अध्यापक धड़ल्ले के लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं और जब हम इन लड़कियों की सपोर्ट में वहां जाते हैं तो उनका यह कहना होता है कि हमारी सरकार है आप हमीर बदली नहीं करवा सकती। इस तरह से जो शरारती अध्यापक है उनके बारे में मैं आपके माध्यम से सरकार को सचेत करना चाहती हूं। सरकार को चाहिए कि वह इस तरह की व्यवस्था करें कि ये अध्यापक बच्चों को ठीक तरह से पढ़ाए न कि ग्रुपबाजी करें। मेरे क्षेत्र एक रूरल एरिया है वहां पर लड़कियां पढ़ने बहुत कम जाती हैं। वहां पर एक कालेज में लड़कियां 15 साल के बाद पढ़ने के लिए गयी हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहती हूं कि वह नाहड़ महाविद्यालय के बारे में अवश्य गौर फरमाए। इसी तरह से रेलवे स्टेशन कौसली के पास शिव कालोनी की आबादी दो हजार के करीब है वहां पर 36 बिरादरी के लोग रहते हैं अमीर भी, गरीब भी और व्यापारी वर्ग के लोग भी वहां रहते हैं। एक तरफ तो सरकार इंजीनियरिंग कालेज और कम्पयूटर की या बड़ी 2 संस्थाओं की बात करती है लेकिन दूसरी तरफ वह कफद नहीं करती। मैंने पिछली बार भी मुख्यमंत्री का ध्यान दिलवाया था कि रेलवे स्टेशन शिव कालोनी कौसली की आबादी दो हजार है उसमें एक प्राइमरी स्कूल तक नहीं है और अगर आपके पास कोई

योजना हो तो वहां पर एक प्राइमरी स्कूल खोला जाना चाहिए। इसी तरफ से फ्री ऐजुकेशन के बारे में बात कही जा रही थी। मेरे हल्के में एक गांव अकेहड़ी मदनपुर है वहां पर एक छोटी सी ट्रासंर्फामर की बात थी। वहां पर ट्रांसफार्मर लगने हैं इसके लिए 10 बार डी.सी. से कह चुके हैं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। ये छोटी छोटी सी बातें हमें ग्रीवैंसिज कमेटी में उठानी पड़ती हैं। मेरी गुजारिश है कि सरकार इसके लिए कुछ प्रबन्ध करे। इसी तरह से जो पांचवीं के स्कूल थे वे आठवीं तक बनने जा रहें हैं और जो 10वीं के स्कूल थे वे जमा दो तक बनने जा रहे हैं। उनमें से कुछ स्कूल मैट्रिक तक ही रहेंगे, मेरा निवेदन है कि मैट्रिक के स्कूल जहां हैं। उन्हें भी जमा देा तक जरूर कर दें क्योंकि जब बहन बेटियों की शादी की बात आती है, तो ये जरूर पूछा जाता है कि लड़की कितनी पढ़ी हुई है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरी गुजारिश है कि इन मैट्रिक तक के स्कूलों का स्टैंडर्ड जमा दो तक जरूर बढ़ा दें। इसी तरह जहां तक सैंट्रल स्कूल मातनहेल कौंसली की बात थी, चीफ मिनिस्टर साहब उसका उदघाटन करके आए थे उसकी बिल्डिंग पूरी बनी हुई थी उस पर कितना काम चल रहा है कब पूरा हो जाएगा और कब तक स्कूल चालू हो जाएगा यह मैं जानना चाहूंगी? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से 'सरकार आपने द्वारा कार्यक्रम' के बारे में जानना चाहूंगी मेरी समझ से यह पूरा ढकोसला है और इस कार्यक्रम से ग्रामीण पंचायतें गुमराह हुई हैं और जो अफसरशाही है वह बढ़ी है। आफिसर्ज चुने हुए जन

प्रतिनिधियों से अच्छा विहैवियर नहीं करते हैं मैं आग्रह करना चाहती हूं कि चुने हुए प्रतिनिधियों पर जो अफसरशादी हावी हुई है यह ठीक नहीं है। अधिकांश जब हम उनसे मिलने जाते हैं तो वे यह कहते हैं कि तुमने मेरे पास आकर मेरे आफिस कार्य में बाधा डाली है। हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनता की समस्याएं लेकर अधिकारियों के पास नहीं जाएंगे तो हमें यह बताया जाए कि हमारी डयूटी क्या हैं, हमारे फर्ज क्या हैं? इसी तरह से हमारे यहां कौसली मंडी है इसके बारे में कई बार रैजोल्यूशन दे चुके हैं कि एक फायर बिग्रेड स्टेशन कौसली मंडी में होना चाहिए क्योंकि झज्जर में भी फायर बिग्रेड नहीं है और जब रिवाड़ी से फायर बिग्रेड आती है तो उसको आते आते एक घंटा लग जाता है मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि जो फायर बिग्रेड कौसली में होनी चाहिए, वह नहीं है इसलिए कौसली में फायर बिग्रेड दी जाए। इसी तरह से कौसली मंडी का काम भी अधूरा पड़ा हुआ है वहां जो काम होना चाहिए था, वह नहीं हुआ है इसलिए किसानों को अपना प्रोडैक्ट बेचने के लिए दिल्ली व दूसरी मंडियों में जाना पड़ता है अतः निवेदन है कि यदि सरकार किसानों के हित की बात सोचती है तो कौसली मंडी को तुरन्त चालू करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: अनीता जी, प्लीज वाइंड अप कीजिए। चौ. धर्मवीर सिंह जी आप इनके बाद बोलने के लिए तैयार रहें। अनीता जी, आप पांच मिनट में वाइंड अप करें।

चौ. भजन लाल: उपाध्यक्ष महोदय, धर्मवीर सिंह जी, इस समय हाउस में नहीं हैं जो सदस्य हमारी बोलने वालों की लिस्ट में हैं और वे हाउस में नहीं बैठे हैं उनको आप कल बोलने का मौका दे दें।

श्री उपाध्यक्ष: चौ. भजन लाल जी, आपने जो नाम दिये हुए हैं उनमें से आलमोस्ट बुलवा दिए हैं। (विघ्न)

श्रीमती अनीता यादव: उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजली की बात है मैं उस बारे में भी कुछ कहना चाहूंगी। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष: अनीता जी, आप बैठ जाइए, मैं लीडर आफ दि अपोजीशन से बात कर रहा हूं। जो समय भजन लाल जी आपने बोलने के लिए मांगा है वह दिया है। आपको बोलने के लिए समय की कमी नहीं रहने दी जाएगी।

चौ. भजन लाल: उपाध्यक्ष महोदय, आपने यही उम्मीद है। मेरी आपसे इतनी प्रार्थना है कि आज हमारे जो मैम्बर्ज मौजूद नहीं है उनको कृपा करके कल बोलने वालों की लिस्ट में रखना।

श्री उपाध्यक्ष: चौ. साहब, आपको यह देखना चाहिए कि जिस सदस्य का नाम आप बोलने के लिए देते हैं वे सीट पर जरूर हों।

चौ. भजन लाल: उपाध्यक्ष महोदय, बोलने वालों की हमारी लिस्ट में एक नम्बर पर जयप्रकाश बरवाला का नाम था

उनको बोलने का समय नहीं दिया गया दूसरा नम्बर श्री धर्मबीर सिंह का था। उनका नाम भी नहीं लिया गया। आज वे चले गये हैं इसलिए उनको कल बोलने का समय दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: कल की कल देखी जायेगी। आज चले गये हैं तो ठीक हैं।

(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुये)

श्रीमती अनीता यादव: अध्यक्ष महोदय, यह सरकार बिजली के बिल भरने की बात भी करती है। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से इस सरकार को कहना चाहूंगी कि जो लोग अपने बिजली के बिल भर देते हैं और जो अपने बिजली के मीटर रिप्लेस करवा लेते हैं उनके घरों में भी अधिकारी बिना किसी वजह से वे समय सुबह पांच बजे या रात के आठ बजे जाते रहते हैं और बेकार में लोगों को परेशान करते हैं। उनका इस तरह का तौर तरीका ठीक नहीं है। यह कहते तो हैं कि हम किसानों को पूरी बिजली देंगे। लेकिन सरकार ने कोई वायदा पूरा नहीं किया है। मैं स्टूडैण्टस के बारे में कहना चाहूंगी कि आज स्टूडैण्टस को पढ़ने के लिये पूरी बिजली नहीं मिल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही जो मेरे गले नहीं उतर रही है। एक तरफ तो माननीय मुख्यमंत्री जी कम्प्यूटर की बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कालेजों की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ लालऐन की बात करते हैं कि हम तो चिमनी की रोशनी से पढ़े हुए हैं। मैं उनको

आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि आज का स्टूडैण्ट चिमनी की रोशनी में नहीं पढ़ सकता उसके लिए आपको लाईट देनी ही पड़ेगी और उनके भविश्य के बारे में सोचना पड़ेगा। जहां तक इलैक्ट्रिक पौल की बात है कोसली में कई कालोनियों हैं, जिनमें इलैक्ट्रिक पौल नहीं हैं इसी तरह कई गांव हैं जैसे कि नांगल भगवा, आकेहड़ी मदनपुर, रेढूवास, नवादा और सुंदरैहटी इन सभी गांवों की हरिजन कालोनियां में इलैक्ट्रिक पौल नहीं है इन गांवों में बिजली और पानी की सुविधा दी जाये। जो रेढूवास और नवादा की हरिजन कालोनी हैवे 50–60 वर्श से बसी हुई हैं और उन में बिजली पानी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अनिता जी, वाईड अप कीजिए।

श्रीमती अनिता यादव: अध्यक्ष महोदय, जहां तक नहरों की बात है। साल्हावास लिफ्ट चैनल के आधुनिकीकरण के बारे में मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी। श्रीमती इन्दिरा गांधी वहां पर जिस कमरे में नीचे उतरकर आई थी उसकी पटरियां टूट गई हैं उसका कोई खैर खबर लेने वाला नहीं है। आप उस साल्हावास लिफ्ट चैनल को दोबारा से चलाने की कृपा करें। जहां तक नहरों में पानी देनै की बात है पहले 15 दिन में पानी आता था अब महीने में 5 दिन नहरों में पानी आता है इतना कम पानी आता है कि टेल तक नहीं पहुंच पाता। दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी यह कह रहे हैं कि नहरों की मोरियों को ऊंचा उठायेंगे ताकि टेल तक पानी पहुंचे, परन्तु मैं इनको बताना चाहूंगी कि पशुओं को भी

पीने का पानी नहीं मिल रहा है। पानी के अभाव में पक्षी भी कर रहे हैं। कई ऐसे गांव हैं कि आज भी उनमें पीने का पानी नहीं मिल रहा है। उनको पीने का पानी लेने के लिए पैसे भी देने पड़ते हैं और कई गांवों में जैसे मातनहेल, रेलवे स्टेशन कोसली का इलाका है, वहां पर तो दो रूपये का एक पानी का घड़ा मिलता है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मुझे नंद–गांव (बरसाना) में जाने का मौका मिला था, उस गांव की बहुत बुरी हालत है। लोग खेतों में से पीने का पानी लाते हैं क्योंकि कुंओं में पानी नहीं है। जो पानी वे लाते हैं वह कीचड़ वाला होता हैं। मैंने वहां के लोगों से पूछा कि यह पानी कैसा है और इसको आप कैसे पीते हो तो उन्होंने कहा कि इस पानी को हम निथार कर पीते हैं। लोहारू कैनाल से कितलाना डिस्ट्रीब्यूटरी के द्वारा पानी इस साल बिल्कुल नहीं आया जिसकी वजह से पशुओं के लिए पीने का पानी भी नहीं है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस लोहारू कैनाल से कितलाना डिस्ट्रीब्यूटरी को चालू करवाने का काम करवाएं ताकि वहां के पशुओं की जान की हानि न हो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि जहां तक किसानों के लिये स्लैब प्रणाली की बात है हमारे 12 गांव इस प्रणाली के अंडर नहीं है। इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि इन 12 गांवों से स्लैब प्रणाली लागू करवाएं। भिवानी में यह स्लैब प्रणाली लागू है जबकि हमारे साथ लगते क्षेत्र में नहीं है। क्या उनका क्षेत्र अच्छा है और हमारा क्षेत्र बुरा है? सड़कों के बारे में पहले भी जिक्र किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री

महोदय का ध्यान सड़कों की ओर भी दिलवाना चाहूंगी। साल्हावास हल्के की सड़कों की हालत बहुत ही जर्जर है। बिरोहड़ से कालियावास से सासरोली तक 2 किलोमीटर का सड़क का टुकड़ा है जहां रोड़िया भी उधड़ती जा रही हैं, इसके बारे में ध्यान दिय जाए। इस तरह से लिहाहेड़ी से कोल्दराली तक, नवादा से साल्हावास तक रोडज पर तेल नहीं डाला गया। हमने एक्सीयन को कहा कि इन सड़कों पर ध्यान क्यों नहीं देते तो उन्होंने कहाकि सरकार के पास पैसा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह अकेहड़ी मदनपुर से मुन्डाहेड़ा रोड जाती है। वह रोड बिल्कुल खत्म हो गई है। आज तक किसी अफसर वे वहां जाने की कोशिश नहीं की। 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम बिल्कुल ढकोसला है। गांवों में घुसने को रास्ते का पता नहीं चलता। अकेहड़ी गांव के लोग मुन्डाहेड़ा गांव के लोगौं को वहां से जाने नहीं देते। मुन्डाहेड़ा गांव का एक किलोमीटर का टुकड़ा जो रोड में मिलता है उसको पक्का करा दिया जाए तो जन साधारण की जीवन आसान हो जाएगा। झामरी गांव की रोड की हालत इतनी खराब है कि अकेला आदमी उस सड़क पर नहीं चल सकता। इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि उस सड़क के गड्डों को भरवाने की कोशिश की जाए। इसी तरह कोसली मंडी वाया सादतनगर, नेहरूगढ़–झाड़ोदा खेड़ी–नांगल की सड़क पर 4–4 फुट गड्डे हैं जिससे लोग बहुत परेशान हैं। लोगों की छोटी–बड़ी गाड़ियां गांव नेहरूगढ़ में होकर निकलती हैं जिसकी वजह से कई बार दुर्घनाएं

हो जाती हैं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं ला एंड आर्डर की बात करना चाहूंगी। हरियाणा में कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट है।

श्री अध्यक्ष: अनिता यादव जी, अब आप बैठिए।

श्रीमती अनीता यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा में कानून व्यवस्था के बारे में बोल रही हूं। ****

श्री अध्यक्ष: बहन अनीता यादव जी, अब जो कह रही हैं, वह रिकार्ड न किया जाए।

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, एक महिला होने के नाते आपको ध्यान रखना चाहिए कि उनको बोलने का पूरा मौका मिले।

श्री अध्यक्ष: यहां सभी बराबर हैं और सभी को बोलने का बराबर समय मिलेगा।

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, हमने सुबह श्री जय प्रकाश जी और श्री धर्मबीर जी का नाम आपको बोलने के लिए दिया था कि उन्हें सुबह ही राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर बोलने का मौका दिया जाये। लेकिन आपने उन्हें सुबह बोलने का मौका नहीं दिया। इस समय वे चले गये हैं इसलिए उन्हें कल सुबह 9.30 बजे बोलने का मौका दें। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर सर, ऐसा पहली बार हो रहा है कि विपक्ष को राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर बोलने का

मौका दिया जा रहा है और वे बोलने के लिए तैयार ही नहीं हैं। स्पीकर सर, जिस समय हम विपक्ष में होते थे उस समय हम बोलने के लिए सयम मांगते थे लेकिन हमें समय नहीं मिलता था। लेकिन इस समय उल्टा हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के दूसरे सदस्य नहीं हैं तो विपक्ष के नेता दोबारा बोल ले हमें तो कोई एतराज नहीं है।

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं दोबारा यह कहना चाहूंगा कि बिजनैस एजवाईजरी कमेटी की मीटिंग में यह तय हुआ था कि हम आपको हमारे जो सदस्य बोलेंगे, उनके नाम दे देंगे और आप उन्हें बोलने का समय देंगे और आपने कहा था कि हमारे मैम्बरों को बोलने का ज्यादा से ज्यादा समय दिया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान) इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे जो मैम्बर बगैर बोले रह गये हैं उन्हें कल सुबह मौका बोलने का दिया जाये।

प्रो. सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के जो सदस्य चले गये वे हाउस स्थगित होने से पहले क्यों गये?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, उन मैम्बरों को दफतर में दूसरा काम होगा इसलिए चले गये होंगे। इसके अतिरिक्त यहां सुबह 9.30 बजे से बैठे–बैठे आदमी वैसे भी थकान महसूस करने लग जाता है।

प्रो. सम्पत सिंह: हाउस की कार्यवाही से जरूरी दूसरा क्या काम हो सकता है? इस समय उन्हें हाउस में रहना चाहिए था। (शोर एवं व्यवधान)

राव इन्द्रजीत सिंह: अध्यक्ष महोदय, अभी श्रीमती अनिता यादव बोल रही थीं आप उन्हें ही बोलने दें क्योंकि हाउस स्थगित होने में पांच मिनट रह गये हैं। जो दूसरे मैम्बर बोलने वाले हैं उन्हें कल सुबह समय दे दिया गया।

बैठक का समय बढ़ाया

श्री अध्यक्ष: यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

आवाजें: जी हां।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, हाउस का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

राज्यपाल के अभिभाशण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

डा. बिशन लाल सैनी (जगाधरी): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं और साथ ही साथ राज्यपाल महोदय को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यहां आकर अभिभाशण पढ़ा जिससे उस पर हम सबको चर्चा करने का मौका मिला। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (ओम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, यह पहली दफा हम देख रहे हैं कि ऐसा विपक्ष आया है। पिछले सैशन में भी इनकी तरफ से वोट ओफ नो कांफीडैंस मोशन मूव किया गया लेकिन मूवर्ज उस पर चर्चा करने से पहले ही भाग लिये। आज जब हमने इनको छिक के बोलने के लिए कह दिया तो बोलनै वाले मैम्बर्ज कह रहे हैं कि हमें माफ करो, हाउस का समय और न बढ़ाओं। स्पीकर साहब यह सदन चलेगा और सबको बोलने का पूरा समय मिलेगा।

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, आज का प्रोग्राम यहीं खत्म कर दें। (शोर)

श्री अध्यक्ष: भजन लाल जी, अब तो एक घंटे का समय बढ़ा दिया गया है। (शोर)

वाक आउट

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, आपने समय बढ़ा दिया है लेकिन हम इसे नहीं मानते। साढ़े छः बज चुके हैं (शोर) आप हाउस को एडजर्न कर दें। अगर हाउस एडजर्न नहीं करते तो फिर हम एज ए प्रोटैस्ट वाक आउट करेंगे।

श्री अध्यक्ष: आपकी मर्जी हैं। अगर आप नहीं मानते तो चले जाएं। (शोर)

(इस समय इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य वाक आउट कर गए।)

राज्यपाल के अभिभाशण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): जो लिस्टिड मैम्बर्ज है अगर वे आज नहीं बोलेंगे तो फिर कल उनको बोलने के लिये समय नहीं मिलेगा। (शोर)

श्री अध्यक्ष: जय प्रकाश जी, अगर आप हाउस के अन्दर आकर कुछ बोलना चाहते है तो बोल सकते हैं क्योंकि कल फिर आपको बोलने का समय नहीं मिलेगा।

श्री रामकिशन फौजी: अध्यक्ष महोदय, जब हाउस चला उस वक्त मेरे को बोलने का टाईम मिला था मैंने उसी समय कहा था कि कांग्रेस विपक्ष की भूमि का नहीं निभाएगी क्योंकि मुझे मालूम था। ये तो चार हैं (हंसी)

वित मंत्री (प्रो. सम्पत सिंह): अध्यक्ष महोदय, पहले जब विपक्ष के सदस्यों को बोलने का समय नहीं मिलता था या फिर बोलने के लिये पूरा समय नहीं मिलता था तभी प्रोटैस्ट के तौर पर विपक्ष वाक आउट या बायकाट किया करता था। पहले सैशन का टाइम कम होता था, एक्सटैंशन नहीं मिलती थी, डबल सिटिंग नहीं होती थी। वह सही है कि विपक्ष का फर्ज भी बनता है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा बोलने का समय मिलें। अब तो उन्हें बोलने का पूरा समय दिया गया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हाउस

को एक्सटैंड किया जा रहा है और विपक्ष वाक आउट कर रहा है वरना विपक्ष तक वाकआउट करता है जब उन्हें बोलने का पूरा टाईम नहीं मिलता। इसका मतलब सीधा क्लीयर है कि वे सीरिया नहीं है। इतना ही नहीं ये लिस्टिड लोगों को छिपाये बैठे रहे। भजन लाल जी की पुरानी आदत है और पता नहीं कि मैम्बरों को क्या लोभ अथवा लालच दे देते हैं। जैसे कि पहले थैलियां देकर सरकार बदला करते थे, उसी तरह से अपने मैम्बरों को लोभ या लालच देकर बाहर लोबी में बिठाए रखा। ये मैम्बरों को इस तरह से छिपाकर गायब करके हाउस में असत्य बोलते हैं। आपके द्वारा बाउन्ड्री के अन्दर अनाउंसमैंट कराये जाने के बाद भी मैम्बर्ज हाउस में नहीं आये जबकि अगर लोबी के अन्दर भी कोई मैम्बर बैठा हो और उसका नाम लेकर बुलाया जाए तो मैम्बर को हाउस में हाजिर होना पड़ता है। मैम्बर का बोलने के लिये नाम लेने के बाद भी हाउस में उपस्थित न होना, यह तो वही बात हुई कि जब बिल्ली थैले से बाहर आ गई तो कहते हैं कि हमारे मैम्बर्ज हैं नहीं। स्पीकर सर, आपने आवाजें दे–दे कर और नाम लेकर मैम्बरों को बोलने के लिए बुलाया फिर भी वे हाउस में उपस्थित नहीं हुए। मेरे ख्याल में विपक्ष का इससे निन्दनीय रोल और क्या हो सकता है?

श्री अध्यक्ष: अब बिशन लाल सैनी कन्टीन्यू करें।

डा. बिशन लाल सैनी: अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में चौ. ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व की सरकार चल रही है।

इस सरकार का एक प्रोग्राम चल रहा है 'सरकार आपके द्वार'। इस प्रोग्राम के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बोलते हुए हमारी एक माननीय सदस्या कह रही थी कि यह प्रोग्राम एक ढकोराला है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहन चाहूंगा कि इस प्रोग्राम के तहत दूसरे प्रदेश में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का मौका किया है जब चौ. बंसी लाल जी की सरकार थी तो उसने अपनी सारी ताकत प्रदेश में शराब बंद करने पर लगा दी थी जिसके कारण उस सरकार का सारा ध्यान प्रदेश के विकास कार्यों की तरफ से पूर्ण रूप से हट गया था। लेकिन आदरणीय चौ. ओम प्रकाश चौटाला की सरकार आने के बाद जब से इन्होंने 'सरकार आपके द्वार' प्रोग्राम शुरू किया है तब से प्रदेश में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का मौका मिला है। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के जगाधरी में 4 फरवरी को 'सरकार आपके द्वार' प्रोग्राम के तहत एक बहुत महत्वपूर्ण दरबार लगाया गया। इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए जब मैं गांव–गांव में लोगों को उसमें आने का न्यौता देने के लिए गया तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि हर गांव में चाहे वह छोआ गांव था और चाहे वह बड़ा गांव था, हर गांव में कोई न कोई विकास का कार्य चल रहा था जोकि इस सरकार का एक बहुत ही सराहनीय कदम हैं। चाहे किसी गांव में कोई पक्की फिरनी बनाई जा रही हो, चाहे कहीं कोई नाला पक्का बनाया जा रहा हो, चाहे कहीं कोई पक्की सड़क को निर्माण कार्य चल रहा है, मेरे कहने का मतलब है कि प्रदेश में सभी जगहों पर विकास के कार्य चल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के कुछ

माननीय सदस्यों ने अपनी चर्चा के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला विपक्षी सदस्यों के हल्कों के विकास कार्यों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर वे साथी यहां पर बैठै होते तो मैं उनको बताता कि हल्का जगाधरी से मैं बी.एस.पी. का केवल मात्र एक सदस्य हूं लेकिन वहां पर इस वक्त 25 नई सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है। 'सरकार आपके द्वार' प्रोग्राम के तहत वहां पर 4 फरवरी को जो दरबार लगाया गया, उसके बारे में मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही हैं कि उस समय आदरणीय मुख्यमंत्री जी वहां पर सड़कों के अलावा 10 करोड़ रूपए के नए विकास कार्य मंजूर करके आए। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बात कहते हुए बड़ी प्रसन्नता अनुभव हो रही है कि आदरणीय मुख्यमंत्री चौ. ओम प्रकाश चौटाला इस बार मेरे हल्के में जितनी सड़के मंजूर करके आए हैं उतनी सड़के किसी दूसरे हल्के में मंजूर नहीं करके आए। वे मेरे हल्के जगाधरी में 17 और नई सड़कें मंजूर करके आए हैं। यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है। अध्यक्ष महोदय, जगाधरी हल्के के तलाकौर गांव के अन्दर 66 के.वी. के नये सब–स्टेशन का निर्माण कार्य हो गया है और मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं यह उनका बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि वह 66 के.वी. का सब–स्टेशन बनने से वहां के किसानों को उचित मात्रा में बिजली उपलब्ध होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर चर्चा करते हुए यह कहना चाहूंगा कि जो स्लैब प्रणाली चौ. बंसी

लाल जी ने हरियाणा प्रदेश में शुरू की थी जिसके बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने यहां पर जिक्र किया हैं वह बहुत ही त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि उस स्लैब प्रणाली के होते हुए हमारे जिले के किसानों को आज भी बहुत नुक्सान उठाना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो स्लैब प्रणाली चौ. बंसी लाल के मुख्य मंत्रीत्वकाल के दौरान शुरू की गई थी उसकी वजह से हमारे जिले के बहुत किसानों को नुक्सान उठाना पड़ रहा है क्योकि उस समय जिन नलकूपों की गहराई का सर्वेक्षण किया गया था वह बहुत ही गलत किया गया था। मेरे जिले के 70 प्रतिशत टयूबवैल 150 फुट से भी ज्यादा गहरे हैं लेकिन उस सर्वे में 100 फुअ से भी कम गहरे दिखाए गए थे। पानी नीचे होने के कारण भी उसका खर्च किसानों पर अधिक आ रहा है। यमुना नगर जिले के साथ इस मामले में बड़ा अन्याय हो रहा है। पहले जो सर्वे करवाया गया था वह ठीक नहीं हुआ था इसलिए मेरी मांग है कि इस सर्वे को दुबारा से करवाया जाये ताकि किसानों को इसका फायदा मिल सके।

स्पीकर साहब, सरकार ने गरीब हरिजन की लड़कियों की शादी के मौके पर 5100 रूपये की इमदाद तो कन्यादान के रूप में जरूर कर रखी है लेकिन इसका सही फायदा गरी हरिजनों को नहीं मिल पा रहा। इसका फायदा केवल वे लोग उठा पा रहे हैं जिनके पास पीले राशन कार्ड होते हैं। पहले गरीबी रेखा से नीचे का जो सर्वेक्षण हुआ था वह अधूरा हुआ था। इस बारे में

मेरी सरकार से मांग है कि इस सर्वेक्षण को दुबारा करवाया जाये ताकि उन गरीब हरिजन परिवारों को लाभ मिल सके जो वाकई इसके हकदार हैं।

अध्यक्ष महोदय, दादुपूर नलवी नहर जो 20 साल से मंजूर हुई पड़ी है उसका जिक्र इस अभिभाशण में कहीं पर भी नहीं है। इस नहर के बनने से कुरूक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर और अम्बाला के लोगों को फायदा पहुंचाना है। इस बारे में मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस नहर का काम हमारी मौजूदा सरकार अवश्य करवाये। अन्त में स्पीकर साहब, मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री जगजीत सिंह सांगवान (चरखी दादरी): माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे 5 तारीख को महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। 5 तारीख को महामहिम ने जो अपना अभिभाशण दिया उसमें बहुत सी ऐसी बातें रह गई हैं। जिनको शामिल नहीं किया जा सका, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि जो बातें रह गई थी और अब मैं जिनका जिक्र करूंगा, उन पर मौजूदा सरकार गौर फरमाये।

अध्यक्ष महोदय, बिजली का मुदा एक अहम मुद्दा हैं। प्रदेश में और खासतौर से हमारे इलाके में जहां पर सिंचाई के साधन केवल टयूबवैल्ज हैं, जहां पर नहर का पानी जाता नहीं वहां

पर केवल बिजली की सप्लाई द्वारा ही सिंचाई होती हैं, हमारे इलाके में सरकार बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करे क्योंकि अगर बिजली की सप्लाई पूरी नहीं हुई तो किसान जिनकी फसल पकने पर है, उसकी बहुत कम पैदावार होगी और नेपा (वजन कम आयेगा)। इसलिए मेरी मांग है कि उस एरिया में बिजली की पूरी सप्लाई उपलब्ध करवाई जाये।

अध्यक्ष महोदय, हमारे एरिया में पिछले 10–10 सालों से लोगों के नलकूपों के कनैक्शन बकाया पड़े हैं। अब सरकार ने एक नई स्कीम बनाई है जिसके तहत किसान अपना ट्रांसफारर्मर खरीद कर लायें, तार खरीदकर लाए और खम्बे आदि खरीद कर लायें। किसान के लिए यह स्कीम बहुत मंहगी है। पहले तो किसान का डेढ़ दो लाख रूपया टयूबवैल्ज पर खर्चा आये और फिर इतना ही पैसा इन चीजों पर खर्च करे तो यह उसके वश से बाहर की बात है। पहले जिस स्कीम के तहत 1990–1991 के अन्दर जिन लोगों ने सीनियोरिटी के हिसाब से पैसे जमा करवा रखे थे, चाहे वे किसी के 3 हजार थे या इससे कम या अधिक थे उनको सीनियोरिटी के हिसाब से कनैक्शन देनै की बात पर सरकार पुनर्विचार करे ताकि किसानों को कुछ राहत मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा दादरी उप मण्डल के अन्दर कुछ ऐसी नहरें हैं जो बैकार पड़ी हुई है जिन पर काफी पैसा लगा है जिनका दो दो या चार चार आर.डी. का काम रह गया है अगर सरकार चाहे तो वे रूके हुए काम शुरू करवा दे और

ये नहरे बन जाएं तो इन नहरों की भी उपयोगिता हो सकती है। (विघ्न) मैं उन नहरों का नाम भी बता दूंगा। इन नहरों के बन जाने से सिंचाई का काम हो सकता है। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: आप यह बताएं कि वे नहरें अधूरी पड़ी हुई हैं या उनका निर्माण कार्य शुरू करना है?

श्री जगजीत सिंह सांगवान: अध्यक्ष महोदय, वे बीच में अधूरी पड़ी हुई है और एक्सटैंड करने के लिए है जैसे कि साहूवास तक माईनर है वह अगर 1300 आर.डी. से 2800 आर.डी. तक बन जाए तो काफी लाभ हो सकता है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: आप ये सारी लिखकर भिजवा दें तो इन पर काम करवा दिया जाएगा।

श्री जगजीत सिंह सांगवान: मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको लिखकर भिजवा दूंगा। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इसके लिए धन्यवाद करूंगा। जो नहरे अधूरी पड़ी हैं और जिनमें बाईचांस पानी चलता है वरना वे सूखी पड़ी रहती हैं और वे अपनी शेप में नहीं हैं। मेरे ख्याल से इस पर पिछली सरकार ने भी थोड़ा काम किया था अब अगर वे पूरी हो जाएगी तो बहुत ही अच्छा है। (विघ्न) एक कमोद गांव की नहर है, अचिना माईनर है, मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मेरे सुझाव को पूरा करवाने का वायदा किया है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथी ही साथ गवर्नर महोदय के

अभिभाशण में औद्योगिक विकास का भी काफी जिक्र आया है। मैंने पिछली बार भी मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना की थी कि प्रदेश में काफी बड़े–बड़े बजट की फैक्टरियां बन्द पड़ी हैं उनमें से एक गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया की सी.सी.आई. चरखी दादरी की फैक्टरी है जो कि पिछले कई सालों से बन्द पड़ी है। हजारों श्रमिक इसके कारण बेकार हो गए हैं। यह फैक्टरी दादरी की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्त्रोत भी रहा है जो कि अब बन्द हो गया है। अगर मुख्यमंत्री जी मानेंगे तो मैं उनसे निवेदन भी करना चाहूंगा। जब मुख्यमंत्री जी के बेटे ने वहां से पार्लियामैंट का चुनाव लड़ा था उस समय यह आम बात भी हुई थी कि इस फैक्टरी को चलवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी करूंगा कि वे इस बारे में सही और ठोस कदम उठाएं ताकि उन मजदूरों का भला हो और इलाके के अन्दर खुशहाली भी आए। जनस्वास्थ्य के बारे में मैंने एक ग्रीवैन्सिज कमेटी की मीटिंग में मुख्यमन्त्री महोदय से बात भी की थी। वैसे तो मुख्यमंत्री जी ग्रीवैन्सिज कमेटी की मीटिंग्ज में भाग लेने के लिए जाते ही रहते है, एक मीटिंग में मैंने उनसे यह निवेदन किया था कि भिवानी जिले के सब गांवों के जोहड़ भरवा दिये जाए और जो डिग्गिया हैं वे भी भरवाई जाए। कुछ इलाके को छोड़ कर जमीन के अन्दर का सारा पानी खारा है और लोगों के लिए पीने के पानी की भारी समस्या है। मुख्यमंत्री जी ने तुरन्त आदेश दिये लेकिन सारे तालाब और डिग्गियां फिर भी नहीं भर पाई क्योंकि अधिकारियों के लैवल पर कोताही बरती गई। वैसे इससे कुछ राहत मिल गई और उसके

बाद कुछ बारिश भी हो गई। अब भी मैंने इस बारे में लिख कर अलग से क्वैश्चन भी दिया और मैं उनके नाम भी बता सकता हूं जोकि बहुत ज्यादा हैं (विघ्न) अगर मुख्यमंत्री जी चाहैंगे तों मैं उनको अलग से लिखकर दे दूंगा कि किन गांवों के जोहड़ और किन गांवों की डिग्गियां भरवाई जानी है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: आप लिख पर भिजवा दें तो इनको भरवा दिया जाएगा।

श्री जगजीत सिंह सांगवान: मुख्यमंत्री जी ने यह भी वायदा किया है बहुत अच्छी बात है मैं इनका धन्यवाद करता हूं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात यह हैं कि जनस्वास्थ्य से सम्बन्धित एक और मामला चरखी दादरी का हैं। दादरी के अन्दर आबादी बहुत ज्यादा हो गई है और शहर भी बहुत बड़ा हो गया है। यहां की आबादी करीब 60 हजार है, वहां पर थोड़ी जगहों पर सीवरेल का काम है और थोड़ी बहुत जगहों पर यह सीवरेज सिस्टम बेकार पड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने सीवरेज के लिए छः शहर पिछले साल और छः शहरों के नाम इस साल के लिए भी दिए हुए हैं। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि दादरी को भी इसमें शामिल कर लिया जाए क्योंकि दादरी उप–मण्डल प्रदेश का सबसे बड़ा उप–मण्डल हैं और जिला बनने लायक भी है। जिला बनाने के लिए सारी चीजें वहां पर मौजूद हैं। जीन्द रियासत के जमाने में भी चरखी दादरी जिला हुआ करता था। कम से कम उसकी सीवर व्यवस्था

का प्रबन्ध किया जाए। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि जो भी गांव इस जिले में रहना चाहेंगे उनको इसमें शामिल किया जाएगा, हमारा तो सारा उपमण्डल यह फैसला कर देगा और रैजोल्यूशन कर देगा कि हमें जिले का दर्जा दे दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसे ही जनगणना का कार्य पूरा होगा मैं आपको इस बारे में लिख कर दे दूंगा कि दादरी को जिला बना दें जिससे मुख्यमंत्री जी का नाम आ जाएगा कि उन्होंने भी एक जिला बनाया है (विघ्न) मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में अभी कोई जिला नहीं बनाया है। (विघ्न)

अध्यक्ष महोदय, मेरे से पहले बोलते हुए सभी मैम्बर्ज ने यह बात रखी कि ग्राम पंचायतों को अधिकार तो दिए हैं लेकिन उसके ऊपर या नीचे ग्राम विकास समितियां बना दी हैं। अध्यक्ष महोदय, ब्लाक समिति के मैम्बर्ज को, जिला परिशद के मैम्बर्ज को और मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट को पैसा खर्च करने का अधिकार है। दूसरे स्टेटस में तो एम.एल.एज. को भी पैसा अपने हल्के में खर्च करने का अधिकार है। लेकिन हरियाणा में एम.एल.एज. को पैसा खर्च करने का अधिकार नहीं है। मेरे सत्ता पक्ष के मैम्बर्ज भी मन–मन में यह पैसा खर्च करने का अधिकार चाहते हैं और इस विशय में मेरे से उन्होंने कई बार कहा है और मुझे कहते हैं कि हमारी इस मांग को आप ही हाउस में रखें। अध्यक्ष महोदय, आप हयां पर पर्ची डलवा कर देख लें तो पता चल जाएगा कि कौन कौन यह ग्रान्ट चालू करवाना चाहते हैं चह जो ग्रान्ट मैम्बर्ज को

मिलती थी उसको बंसी लाल जी बंद कर गए थे मेरे ख्याल से यह 50 लाख के करीब की ग्रान्ट थी। मुख्यमंत्री जी इस हाउस में इस बारे में बोलते रहे हैं तो मेरी मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि इस ग्रान्ट को दोबारा से चालू करें और हो सके तो इस ग्रान्ट को 50 लाख से बढ़ाकर भी चालू करें अगर ये ऐसा करते हैं तो इनकी सारे राज्य में प्रशंसा होगी। जब इनके एम.एल.एज. अपने हल्के में जाएंगे तो वे इनकी प्रशंसा करेंगे ही और जब हम जाएंगे तो हम भी इस बारे में कहेंगे कि चौ. ओम प्रकाश चौटाला जी ने यह काम किया है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अधिकारियों को तो हर जगह का पता नहीं होता है कि कहां पर क्या कमी हैं। एक एम.एल.ए. ही अपने हल्के में जाता है उसको पता होता है कि कहां पर गाड़ी धंस जाती है और कहां पर गड्डे हैं। कहां पर चार दीवारी बनानी है और कहां पर क्या–2 काम करवाने की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष: सांगवान जी आप वाइंड–अप करें।

श्री जगजीत सिंह सांगवान: अध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ और बातें कहनी हैं इसके बाद मैं वाइंड–अप कर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इस ग्रान्ट का जारी करें। अगर वे ऐसा करते हैं तो उनका काफी नाम होगा। उनके एम.एल.एज. के साथ साथ जब हम भी अपने हल्कों में जाएंगे तो हम लोगों से यही कहेंगे कि चौ. ओम प्रकाश चौटाला जी ने यह काम किया है। (विघ्न) इसके अलावा

मुख्यमंत्री जी यात्रियों को कुछ सुविधाएं देने का प्रयास कर रहे हैं जो कि सराहनीय काम है। लेकिन हरियाणा में चरखी दादरी में जो हरियाणा रोडवेज का डिपों था बन्द कर दिया गया है उसके लिए यह कहा गया कि वह घाटे में था मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा में चार और डिपोज ऐसे हैं जो घाटे में चल रहे हैं उनमें से भिवानी, सोनीपत और दूसरे डिपो भी हैं। वे भी घाटे में हैं। लेकिन तोड़ा गया सिर्फ चरखी दादरी का डिपो ही। हम डिपो अभी ही तोड़ा गया है इस बारे में मुख्यमंत्री जी दोबारा से विचार कर लें।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बारे में मेरे से पहले बोलते हुए कई सदस्यों ने बात करी हैं। सरकार ने कई नई सस्थाएं खोली है और कई नगए कोर्सिज हरियाणा में शुरू किय हैं।

दादरी के अन्दर एक आयुर्वेदिक कालेज खोलने की अनुमति केन्द्र सरकार से मिल गयी थी। सरकार के पास वह केस आया भी था हो सकता है कि उसमें 19–21 की कमी हो। आप उस कमी को पूरा करवाकर उसकी मंजूरी दे सकते थे। आप इस मामले को दोबारा से दिखवा लें। वहां पर आयुर्वेदिक कालेज खोलने के लिए सारे साधन मौजूद हैं। दादरी के अन्दर कोई भी इंजीनियरिंग कालेज नहीं हैं। न कोई गवर्नमेंट कालेज है और न ही वहां पर कोई महिला कालेज है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि वहां पर एक इंजीनियरिंग कालेज खोला जाए ताकि शिक्षा के क्षेत्र में सारे हरियाणा में समानता आ जाए। (विघ्न) पिछले सत्र

में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि पीले कार्ड बनवाने में जो धांधली की बात यहां पर आयी थी उसके बारे में वे दोबारा से सर्वे करवाएंगे। उस समय सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी एम.एल.एज. ने इस बारे में कहा था। उस समय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि बुढ़ापा पैंशन, पीले कार्ड या विधावाओं का सही सर्वे करवाया जाएगा लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं हुई। मुझे उम्मीद है कि अब मुख्यमंत्री जी इस तरफ ध्यान देंगे। इसी तरह से श्रम एवं रोजगार की बात है। रोजगार के कुछ अवसर इस सरकार ने प्रदान किए हैं लेकिन साथ ही चरखी दादरी के साथ बड़ा अत्याचार हुआ है वहां का रोजगार कार्यालय तोड़ दिया गया जिससे सरकार के खिलाफ गांवों में यह बात गयी कि इस सरकार ने वहां का डिपों भी तोड़ दिया और रोजगार का कार्यालय भी हटा दिया। अब वहां बेरोजगारों को तीस किलोमीटर दूर जाना पड़ता है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अगर वहां रोजगार कार्यालय में किसी बेरोजगार का नाम है तो आप हमें बताएं।

श्री जगजीत सिंह सांगवान: कई नाम हैं वहां पर सब डिवीजन के लैवल पर सबसे ज्यादा बेरोजगारों के नाम हैं।

श्री ओमप्रकाश चौटाला: आप पता करके हमें बात दें।

श्री जगजीत सिंह सांगवान: ठीक है जी, इसी तरह से सहकारिता का मामला है। दिल्ली से एन.सी.वी.आई. की एक टीम

आयी थी। मुख्यमंत्री जी ने भी अखबारों के माध्यम से कहा था कि हम इस बारे में गौर कर रहे हैं और नये बाई लॉज व नये कानून भी बना रहे हैं। सहकारिता के क्षेत्र में कुछ ऐसी संस्थाएं थी जो कई सालों से काम कर रही थीं हालांकि इनमें से कुछ घाटे में चल रही थी। लेकिन उनको बचाने के बजाए बंद कर दिया गया जो कि अच्छी बात नहीं है। सारे देश में हरको फैड की तरफ संस्थाएं हैं जो कोआपरेटिव सैक्टर में काम कर रही हैं। इन संस्थाओं का मुनाफे से कोई लेना देना नहीं होता है। इनका तो यही काम होता है कि सहकारिता को कैसे बढ़ावा मिले। जिस तरह से हरको फैड के बंद करने की बात है उसी तरह से इंडस्ट्रियल फैडरेशन या हांसी स्पीनिंग मिल को भी बंद कर दिया गया। इस मिल को हैफेड लेकर चला सकता था। अब कहा जा रहा है कि दो तीन बार टैंडर मंगवाए हैं। वहां पर काफी जमीन है। सरकार को इस जमीन को बेचने के बजाए इसका कहीं ओर उपयोग करना चाहिए। वह जमीन बहुत ही मौके की जमीन हैं। इसलिए वहां पर कोई और इंडस्ट्री लगाा दी जाए तो बहुत बढ़िया बात होगी। अंत में में आपके माध्यम से चाहूंगा कि जो मैंने आपके सामने प्रस्ताव रखें हैं सरकार उन पर पूरा गौर फरमाए। जिन दो तनी नहरों और सड़कों की बातों के बारे में मुझे मुख्यमंत्री जी ने कहा है वह मैं मुख्यमंत्री जी को लिखकर दे दूंगा। मैं चाहता हूं कि इन सब बातों को शामिल करके इस अभिभाशण को दुरूस्त कर लिया जाए। धन्यवाद।

19.00 बजे

श्री लीला राम (कैथल): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आपके माध्यम से मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने जिस प्रकार से अपनी दरियादिली का परिचय दिया वह सराहनीय है। चाहे वह राजस्थान में सूखे का मामला था, चाहे उड़ीसा में तूफान या फिर गुजरात में पिछले दिनों आए भूकम्प का मामला हो, जिस प्रकार से सम्मानित मुख्यमंत्री जी ने दिल खोलकर पूरे हिन्दुस्तान में एक मिसाल कायम की है वह काबिले तारीफ है। जिस समय पूरा हिन्दुस्तान पूरे हर्शोल्लास के साथ 26 जनवरी के दिन अपना गणतंत्र दिवस मना रहा था तभी परमात्मा की नजर टेड़ी हुई और मिन्टों के अन्दर गुजरात के तालुका भुज और भचाऊ में लाखों लोगों की जानें चली गई और 400 बच्चे एक ही छत के नीचे दबकर मर गए। वहां पर उनकी चीख पुकार सुनने वाला भी कोई नहीं था। हरियाणा प्रदेश द्वारा दी गई मदद की सारे हिन्दुस्तान ने व वर्ल्ड ने प्रशंसा की। इसके लिये मैं भी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं आज हरियाणा प्रदेश के अन्दर चौ.ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में विकासशील सरकार काम कर रही है और आज सुबह 9.30 बजे से राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर चर्चा हो रही है लेकिन जब हमने किसानों की बात की तो हमारे विपक्ष के साथी उठकर चले

गये परन्तु उन लोगों के मुंह से किसानों की बात करना अच्छा नहीं लगता क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता पिछली सरकारों को एक दो वर्श तक नहीं लगातार कई वर्शों तक झेल चुकी है। अध्यक्ष महोदय, चौ. भजन लाल के नेतृत्व में जब हरियाणा प्रदेश के अन्दर कांग्रेस की सरकार थी तब जब भी किसानों ने अपनी किसी मांग के लिए कोइ ऐजीटशन किया या कोई धरना दिया उनमें चाहे निसिंग हो, चाहे कादमा हो, चाहे टोहाना या नारनौल हो, वहां पर किसानों को गोलियों से भून दिया गया। जिन लोगों के हाथ किसानों के खून से रंगे हुए हों उन लोगों ने किसानों के हित की बात करने की कोशिश की। कौन किसान का हितेशी है कौन दुश्मन है हरियाणा प्रदेश के लोग इन नेताओं के मगरमच्छी आंसुओं को अच्छी तरह से जानते हैं पिछले डेढ़ साले से जब से चौ. ओम प्रकाश चौटाला जी ने इस प्रदेश की गद्दी संभाली है तब से वे 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत 90 के 90 हल्कों में अपने विधायकों या अधिकारियों के साथ हर हल्के में गए और वहां पर पंचायतों को बुलाया गया और खुले दरबार लगाए गए और जिस प्रकार से पंचायतों की बात सुनी गई, पंचायतों मुख्यमंत्री जी से सीधे रूबरू हुई और जिस पंचायत ने जो भी मांगा, मुख्यमंत्री जी के सामने रखा चाहे यह गलियों का मामला था चाहे वे बैकवर्ड चौपालें थी चाहे किसी स्कूल की चारदीवारी का मामला था चाहे और मामले थे, मुख्य मंत्री जी ने आगे बढ़कर कहा कि क्या आपका यहां पशु अस्पताल है? यदि पंचायत ने कहा कि नहीं है तो उन्होंने कहा कि इनके यहां पशु अस्पताल बनाया

जाए और इन बातों से जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने लोगों के दिलों पर छाप छोड़ी, उसकी मिसाल नहीं है यह कोई राजनीति की बात नहीं है उस बात को लोग समझ व मान चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि 1991 से लेकर 1999 तक आपने देखा होगा कि हरियाणा प्रदेश में सड़कों की क्या दुर्दशा थी? नेशनल हाई–वे और स्टेट हाई–वे को छोड़कर प्रदेश में कहीं भी एक किलोमीटर की नई सड़क नहीं बनाई गई थी। परन्तु माननीय मुख्यमंत्री जी ने थोड़े समय के अंदर ही एक प्रकार का रिकार्ड कायम करके 4100 किलोमीटर के लगभग सड़कें बनाने का काम किया है। विपक्ष के नेता सदन के अन्दर किसानों की बात करते थे, कृशि की बात करते थे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात के लिए भी रिकार्ड कायम किया है। जिन किसानों को उनके गन्ने का भाव 50 पैसे प्रति क्विंटल भी नहीं मिलता था और उसका भाव बढ़वाने के लिए भी पहले उनको लाठियां और गोलियां खानी पड़ती थी परन्तु हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुर्सी पर बैठते ही किसानों को गन्ने का भाव 110 रूपये प्रति क्विंटल देने का काम किया है जो सारे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक शिक्षा का सवाल है। शिक्षा की बात इस सदन में आई है। माननीय मुख्यमंत्री ने आज यह देख लिया कि आज सरकार सरकारी स्कूलों से बच्चे हटकर प्राईवेट स्कूलों में एडमिशन लेते हैं। गरीब से गरीब आदमी यह

चाहता है कि उसका बच्चा इंटैलीजेंट बने। मैं तो गरीब हूं लेकिन मेरा बच्चा कामयाब हो जाये। इसलिए न चाहते हुए भी वह अपने बच्चे को प्राईवेट स्कूल में डालता है। चौ. ओम प्रकाश चौटाला जी ने इस बात की आवश्यकता को देखा और सरकार ने यह फैसला लिया कि हरियाणा प्रदेश के हर सरकारी स्कूल में प्राईमरी कक्षा से अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू की जाये। जिससे आने वाले समय में अच्छे नतीजे सामने आयेंगे और हरियाणा प्रदेश की नई जररेशन को अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। जहां तक उच्च शिक्षा की बात है हरियाणा प्रदेश में आज इंजीनियरिंग कालेजों को बढ़ावा दिया गया है। मैं समझता हूं कि कोई भी ऐसा जिला नहीं होगा जिसमें नये इंजीनियरिंग कालेज को सरकार ने खोलने की मान्यता न दी हो। आज प्रदेश के अन्दर कम्पयूटर की शिक्षा लागू की गई है, इंफोर्मेशन टेक्नालोजी को बढ़ावा दिया गया है। इस प्रकार का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश में किया है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजली की चर्चा हुई। हरियाणा प्रदेश में पिछले 20 सालों में किसानों को बिजली लेने के लिए लगातार एजीटेशन करने पड़ते थे और धरने दिए जाते थे तब भी किसानों को लाठियों और गोलियों के सिवाय कुछ नहीं मिलता था। लेकिन चौ. ओम प्रकाश चौटाला जी ने इस प्रदेश की सरकार की बागडोर संभालते ही बिजली का सुधार किया है। पूरे देश में बारिश न होने के बावजूद भी हरियाणा प्रदेश में फसलों की रिकार्ड तोड़ पैदावार हुई है और हरियाणा प्रदेश ने केन्द्र के पूल में पिछले साल के 38 लाख टन अन्न के मुकाबले इस साल 45

लाख टन अन्न का देने का काम किया है। यह असतय बात नहीं है यह तथ्यों पर आधारित बात है, पिछली सरकारों के समय किसानों को पूरी वोल्टेज की बिजली नहीं मिल पाती थी लेकिन वर्तमान सरकार ने किसानों को 24 घंटे बिजली देने की बजाये चाहे थोड़े समय के लिए बिजली दी हो परन्तु पूरी वोल्टेज की बिजली दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी कोशिश है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा बिजली दी जाये ताकि वे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें। पिछले दिनों जब चौ. अमर सिंह जी के हल्के चीका में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 220 के.वी. स्टेशन की आधार शिलाा रखी थी तो वहां पर भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि हमारे पाडला गांव के 33 के.वी.ए. सब–स्टेशन का दर्जा भी बढ़ा दें। मुख्यमंत्री महोदय ने उसी सयम आदेश किए कि पाडला गांव में 33 के.वी.ए. के सब–स्टेशन को 132 के.वी.ए. का बना दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री महोदय ने पूरे प्रदेश में बिजली का जाल बिछाने की अच्छी योजना बनाई है ताकि हरियाणा की जनता को और सिकानों को 24 घंटे बिजली मिल सके। अध्यक्ष महोदय, जहां तक उद्योगों की बात है तो विपक्ष के साथियों ने कहा कि हरियाणा के उद्योग धन्धे पलायन कर रहे हैं लेकिन ये लोग इस रतह की राजनीतिक बातें करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज हरियाणा का बच्चा–2 जानता है कि आज हरियाणा में कितने नए–2 उद्योग लग रहे हैं। गुड़गांव जिले और सोनीपत जिले में नए उद्योग लगाने के लिए एक–2 दिन में

1400–1400 एप्लीकेशंज हरियाणा सरकार के पास आ रही हैं और यह रिकार्ड की बात है।

श्री अध्यक्षः लीला राम जी, आप अपनी बात 5 मिनट में खत्म करें।

श्री लीला रामः अध्यक्ष महोदय, ठीक है मैं 5 मिनअ में अपनी बात समाप्त करके बैठ जाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले चुनावों में हरियाणा की जनता के साथ जो वायदे किए थे उन सभी वायदों को मुख्यमंत्री महोदय ने थोड़े ही समय में पूरा कर दिया। चौ. देवी लाल जी ने बुजुर्गो को मान सम्मान के रूप में 100 रू. पैंशन देने का काम शुरू किया था लेकिन इस सरकार ने आते ही हरियाणा के साढ़े 10 लाख बुजुर्गो को मिलने वाली 100 रू. पैंशन को 200 रू. किया इसके अलावा इस सरकार ने गरीब हरिजना कन्याओं के विवार पर 5100 रू. कन्यादान के रूप में देने का सराहनीय कार्य किया है। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथी भ्रश्टाचार की बात कर रहे थे तो मैं इनको कहना चाहूंगा कि हरियाणा की जनता को क्या हिन्दुस्तान की जनता इस बात को समझ चुकी है कि भ्रश्टाचार को जन्म देने वाला कौन है? कांग्रेस की सरकार के समय में चपड़ासी से लेकर बड़ी से बड़ी नौकरियां बिकती थी और बेरोजगार नव–युवक अपनी जमीनों को बेचकर, गहनों को बेचकर नौकरियों के लिए मारे–2 फिरते थे। चौ. ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में बनी सरकार ने एक उदाहरण पेश

किया है, और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा पुलिस में 2000 नौजवानों की जो भर्ती हुई है वह पैसे के दाम पर नहीं हुई बल्कि योग्यता के आधार पर हुई है। इसी तरह से 10000 जे.बी.टी. टीचर्ज की भर्ती भी योग्यता और बिना भेदभाव के हुई है। इस प्रकार जो भ्रश्टाचार फैलाने वाले लोग हैं, वे आज चौ. औम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में बनी सरकार में जेलों में बन्द पड़े हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय और हरियाणा सरकार का धन्यवाद करता हूं तथा मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री मूलाराम (नारनौल): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जब से चौ. ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार बनी है करीब डेढ़ साल का समय हुआ है इस समय में बरसात की कमी होने के कारण प्रदेश के अन्दर कुछ समय के लिए तो बिजली और नहरी पानी की कमी आई थी। लेकिन हमीर सरकार ने ठोस कदम उठाते हुए बाहर से बिजली लेकर इसकी पूर्ति की। जहां तक बढ़े हुए करों का सवाल है ये इसलिए हुआ क्योंकि यह पिछली सरकार का दिया हुआ बोझ है। हमारी सरकार ने प्रदेश में अमन शांति दी है, भ्रश्टाचार को खत्म किया है। चौ. ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार ने बुढ़ापा पैंशन को 100 रूपये से बढ़ाकर 200 रूपये किया। हरिजन

लड़कियों की शादी के लिए 5100 रूपये कन्यादान के रूप में अनुदान राशि दी गई। कारगिल में शहीद होने वाले जवानों के लिए अनुदान राशि को पांच लाख रूपये से बढ़ाकर 10 लाख रूपये कर दिया गया। किसानों को गन्ने का सरकार ने उचित भाव दिया। पंचायती राज को उचित अधिकार दिये गये। बेरोजगार युवकों को नौकरियां दी गई ओर अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को पांच साल बढ़ाकर उम्र में रियायत दी गई। ये सब मौजूदा सरकार की एक साल की उपलब्धियां हैं इनके लिए मैं चौ. ओम प्रकाश चौटाला जी को बधाई देता हूं। आगे आने वाले चार सालों में हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश को हर लिहाज से पूरे भारत देश के नक्शे पर सर्वप्रथम बना देगी और आने वाले समय में हरियाणावासी दूसरी सरकारों को भूल जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं दोबारा से आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री भीम सैन मेहता (इन्द्री): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर चर्चा करने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाशण पढ़ा है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाशण में सबसे पहले गुजरात में आये भूकम्प पीड़ियों के बारे में चर्चा की है, यह बहुत ही सराहनीय काम है कि मौजूदा सरकार ने भूकम्प पीड़ितों की सहायता सबसे पहले की। इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री

महोदय की सराहना केवल हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है। मेरे से पहले बोलते हुए विपक्ष के भाइयों ने कहा कि सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम एक ढकोसला है। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि विपक्ष के भाई हाउस के अंदर ही ऐसी बातें करते हैं बाहर तो वे भी मानते हैं कि चारों ओर विकास हो रहा है और उनके हल्कों में भी कार्य हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी दिसम्बर, 1999 में मेरे यहां आते थे और इन्होंने जो भी घोशणाएं मेरे यहां की थीं वे लगभग पूरी भी हो गई हैं। आज के दिन हरियाणा प्रदेश के अंदर हर हल्के में कार्य हो रहा है। हो सकता है कही पर किसी मजबूरी के कारण कोई कार्य न हुआ हो। लेकिन सरकार की ऐसी मंशा कतई नहीं है कि कहीं पर कोई कार्य न किया जाये। मुख्यमंत्री जी जिस समय मेरे यहां आये थे और जो घोशणाएं की थी उनमें से एक आध कार्य रह गया है, हो सकता है कि यह कार्य किसी मजबूरी के कारण रह गया हो। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री महोदय कि ऐसी मंशा नहीं है कि वे ये कार्य नहीं करेंगे, ऐसा हम हम सबको भी पता है। करनाल जिले के अन्दर मेरे हल्के इन्द्री में ज्यादातर जीरी की फसल की जाती है, यदि वहां पर हैफेड का एक राईस सैल्टर बना दिया जाये तो इससे किसानों को काफी फायदा होगा और इससे सरकार को भी फायदा होगा, साथ ही साथ बेरोजगार युवकों को नौकरी भी मिलेगी। इसके अतिरिक्त हमारे यहां यमुना नदी पर एक बहुत पुराना पुल बना हुआ है जोकि कभी भी टूट सकता है और दुर्घटना भी हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम

से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि यह पुल दोबारा से बनना सैंग्शन हो चुका है इस बारे में मैंने संबंधित विभाग से पता किया था। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि यदि इस पुल को जल्दी बना दिया जाये तो किसी बड़ी दुर्घटना से बचा जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में एक भादसूं गांव है जिसकी ग्राम पंचायत के पास अढ़ाई–तीन करोड़ रूपया है, इस गांव के 25–30 कि.मी. तक के दायरे में कोई आई.टी.आई. नहीं हैं। यदि मुख्यमंत्री जी इस गांव में आई. टी.आई. बनवा दें तो बहुत अच्छा होगा और जो पैसा पंचायत के पास है उससे बिल्डिंग भी बन जायेगी तथा सरकार का ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा। हमारे नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के लिए अपने पैरों पर खड़े होने के लिये शिक्षा मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां एक सब्जी मण्डी का सर्वेक्षण हुआ है अगर यह जल्दी बन जाए तो किसानों के हित की बात होगी और उन्हें अपनी सब्जियों का सही मूल्य मिल पाएगा। अध्यक्ष महोदय, इन्द्री में पहले नगरपालिका थी और वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से सीवरेज का कार्य शुरू हुआ। अध्यक्ष महोदय, वहां की सारी की सारी गलियां टूट गई हैं और आज कोई भी गली ऐसी नहीं है जहां पर ठीक तरह से चला जा सके। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अरग वे इन विकास कार्यों की ओर ध्यान दें तो जनता में उनका ओर भी संदेश जाएगा और इस बात को मजबूती मिलेगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो जो कहते हैं वह करते हैं। अगर ये

कार्य भी हो जाएं तो हमें और भी ज्यादा सुविधा मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किये हैं। प्राईमरी लैवल पर बच्चों को पहली कक्षा से अंग्रेजी की शिक्षा मिले, यह बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है। इससे प्राईवेट स्कूलों में अंग्रेजी के नाम पर जो लूट–पाट होती है उस लूट–पाट से प्रदेश की जनता बच पाएगी। इसके साथ–साथ सरकार ने ग्रामीण समितियों की विकास समितियां बनाने का जो निर्णय लिया है वह माननीय मुख्यमंत्री जी के दिमाग की पैदाईश है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और विकास के कार्य सही तरीके से गांव–गांव में होंगे और किसी भी प्रकार का घोटाला किसी कार्य में नहीं होगा। कृशि के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने गन्ने का रेट 110/– रूपये प्रति क्विंटल देकर सबसे बड़ा सराहनीय कार्य किया है। यह किसानों के हित की बात है और असल में किसानों के नेता हमारे मुख्यमंत्री चौ. ओम प्रकाश चौटाला जी है। इनकी नस–नस में जो खून बहता है वह हमारे हिन्दुस्तान के ताऊ चौ. देवीलाल जी का है जिनके बताए हुए रास्ते पर चलकर जो कार्य हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे है उसमें सही मायनों में चौ. देवीलाल जी के सपनों को साकार करने ज रहे हैं। अगर ऐसे कामों की प्रशंसा न की जाए तो यह भी हमारे स्तर पर एक कोताही होगी। जो अच्छे कार्य किये जाते हैं उनकी प्रशंसा करना भी जरूरी है और मैं उन कार्यो की वाकई में प्रशंसा करूंगा। बिजली के क्षेत्र में कई प्रकार की बातें कही गई कि नये कनैक्शन नहीं दिये गये। अध्यक्ष महोदय, मैं उधर के साथियों को बताना चाहूंगा कि यह रिकार्ड की बात है

कि पिछले एक साल में हजारों नये कनैक्शन किसानों को दिये गये जिससे किसानों को काफी लाभ होगा। अध्यक्ष महोदय, सड़कों की बात है, सड़कों की मरम्मत का कार्य खूब जोरौं से चल रहा है अगर मेरे हल्के की सड़कों की बात है, सड़कों की मरम्मत का कार्य खूब जोरों से चल रहा है अगर मेरे हल्के की सड़कों की मरम्मत के काम में और तेजी लाएं तो हमें और भी ज्यादा सुविधा मिल सकती है। मैं अपने हल्के की कुछ सड़कों के नाम लेना चाहूंगा और आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि नेवल से चुगांवा तक की एक ऐसी सड़क है जो दो जिलों करनाल को यमुना नगर के साथ सही तरीके से जोड़ रही है अगर उसकी मरम्मत की जाए तो कम से कम 15 किलोमीटर का रास्ता कम हो सकता है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, ये ऐसी सड़कों के नाम अलग से लिखकर दे दें जो कि मरम्मत वाली हों या एक आध किलोमीटर बनाने से फासला कम होता हो।

श्री भीम सैन मेहता: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिये धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने सड़कों के बारे में ऐसा आश्वासन दिया है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से एक साथी ने रोडवेज के डिपो के बारे में कहा था। इस सम्बन्ध में मेरा भी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि करनाल डिपो का सब

डिपो कोई खोलना है अगर यह सब डिपो इन्द्री में खोला जाए तो ज्यादा सुविधा होगी।

स्पीकर साहब, मैं आपकी मार्फत बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी के प्रयास से करनाल में ट्रोमा सैन्टर स्थापित होने जा रहा है उससे करनाल जिले को बहुत फायदा होगा। जी.टी. रोड पर चलने वाले किसी मुसाुरि की यदि कोई दुर्घटना हो जाएगी तो उसको उस ट्रोमा सैन्टर से बहुत सहायता मिलेगी। इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाशण का समर्थन करते हुए कहना चाहूंगा कि प्रदेश में अनेको विकास के कार्य चल रहे हैं उनकी जितनी भी सराहना की जाए उतीन कम है। धन्यवाद।

Mr. Speaker: Now, the House is adjourned till 9.30 A.M. on Thursday, the 8th March, 2001.

***19.26 hrs**

(The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Thursday, the 8th March, 2001.)